संस्कारहीन शिक्षा समाज और देश के लिए गंभीर खतरा

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भारतीय जीवन पद्धति में मानव जीवन के 16 संस्कारों को बड़ा महत्व रहा है। बालक को शिक्षा मंदिर भेजने से पहले उपनयन संस्कार किया जाता था जिसका अर्थ यह था कि अब बालक को ज्ञान का नेत्र मिलेगा। जन्म के समय तो चर्म चक्षु ही प्राप्त होते हैं, अध्यापक ज्ञान के नेत्र देता है। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन संस्कार भी कहा जाता था। इसके पश्चात ही गुरू घर में शिक्षा पाने के लिए बच्चों को भेजा जाता था। आज यह शब्द और यह संस्कार लगभग गायब हो चुका है, पर यह सच है कि बच्चों को दूध के दांतों के साथ ही स्कूलों में अवश्य भेज दिया जाता था। यह स्कूल भी गुरूकुल की तरह सबका साथ सबका विकास वाले सिद्धांत पर नहीं चलते हैं, अपितु जिस परिवार के पास जितना ज्यादा धन बल है उतने ही सुख-सुविधाओं संपन्न शिक्षालयों में बच्चों को भेज दिया जाता है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का प्रमुख आधार है। शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता पहले तो माना जाता था अब सिर्फ कहा जाता है क्योंकि जिस ढंग से शिक्षकों को वेतन के लिए धक्के खाते, नौकरी पक्की करवाने के लिए सरकारी लाठियां सहते देखा जा रहा है उससे यह लगता है कि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता अब यह सरकारें नहीं मानतीं। वह तो केवल रोटी कमाता और बच्चों को निर्धारित पाठयक्रम पढ़ाता है।

सारी कर्मियों और विषमताओं के बाद भी एक सत्य स्वीकार करना ही है कि 1947 के बाद भारत ने ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय उन्नति की है। आकाश से लेकर पाताल तक हमारे युवक-युवतियां पहुंच बना सके हैं और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिसमें वे देश और मानवता की सेवा के लिए तैयार न हो हों। चिकित्सा के क्षेत्र में, खगोल और अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में हिंदुस्तान की तूती बोलती है। अब तो दुनिया के अनेक देशों में हमारे ही डॉक्टर अपनी योग्यता से लोगों को जीवन दे रहे हैं। इंजीनियरिंग की उच्च स्तरीय शिक्षा भारत में मिलती है। स्वतंत्रता के समय हमारे देश में केवल 16 प्रतिशत ही लोग शिक्षित थे। अब विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार केवल 20 प्रतिशत ही अशिक्षित हैं। यह किसी बड़ी क्रांति से कम सच्चाई नहीं, पर जो हम खो रहे हैं उस ओर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। कभी कहते थे कि विद्या ददाती विनयं विनयात याति पात्रताम् अर्थात विद्या विनय देती है और विनय से ही योग्यता प्राप्त होती है। इसी के आधार पर व्यक्ति धन आदि अर्जित करके देश और धर्म की रक्षा करता है, सेवा करता है। अब यह सोचना होगा कि विद्या से विनय कहां चली गई। अब वह विद्या नहीं रही जो मानव निर्माण करती थी, मानवता को सिंचित करती थी। छोटी-छोटी बातों पर आज के युवा विद्यार्थी आंदोलन करते हैं, उनका आक्रोश सड़कों पर ही नहीं फैलता अपितु राष्ट्रीय संपदा को भी भारी हानि पहुंचा देता है और कहीं-कहीं तो वे जेएनयू के छात्रों की तरह देश के विरूद्ध ही आवाज उठाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। इस सारी अराजकता में क्या केवल छात्र-छात्रएं ही दोषी हैं, अध्यापक दोषी हैं अथवा देश की शिक्षा नीति आज भी दिल्ली सरकार के दरवाजे तक हमारे किशोर छात्र-छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं। इसे आंदोलन न कहें तो अच्छा, वे अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए चीख-पुकार करते सुनाई दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रबंधक के शिखरों पर बैठे कुछ धन लोलुप और सिफारिशी अधिकारियों के कारण परीक्षाओं से पहले प्रश्न पत्र मार्केट में पहुंच जाते हैं जिसमें सोशल मीडिया सहयोगी हो रहा है। दिन-रात मेहनत करने वाले विद्यार्थी तो पीछे रह जाते हैं और सिफारिश और नोटों के बल पर परीक्षा से पूर्व ही प्रश्नों के उत्तर पाने वाले परिणाम में सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। दोष सरकारों का है, सरकारी नीति का है। एसएससी परीक्षा के लिए बड़ा आंदोलन और व्यापमं घोटाले के दुखांत चीख-चीख कर बता रहे हैं कि शिक्षा और परीक्षा की क्या दुर्गति हो गई।

परीक्षाओं में नकल की बीमारी भी दीमक की तरह पूरी शिक्षा प्रणाली को खा रही है। नकल करना करवाना अब छोटा काम लगता है। बड़ा काम तो वह है जो सी बीएसई की परीक्षाओं में देखा गया। कुछ लोग असहमत हो सकते हैं पर कटु सत्य यह भी है कि स्कूलों और कॉलेजों में अपने खिलाड़ियों को बिना पढ़ाई किए ही उत्तीर्ण करवाने की जो बीमारी आधी सदी से चली आ रही है वह भी नियंत्रित नहीं हो सकी । हमारे शिक्षा पाठयक्रम में उन महापुरूषों का जीवन चरित्र भी धीरे-धीरे गायब कर दिया गया जिनसे प्रेरणा लेकर आज के बच्चे सचरित्र बन सकते हैं। क्या यह विडंबना नहीं कि पंजाब के और देश के जो सैकड़ों लोग भरी जवानी में काले पानी की यातनाएं सहते-सहते केवल भारत की आजादी का लक्ष्य लिए ही संसार से चले गए उनको आज देश न जानता हो। भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों ने यह प्रयास ही नहीं किया कि शिक्षा मंदिरों से ही विद्यार्थी उन हुतात्माओं से प्रेरित और परिचित होकर निकलें जिनके कारण आज राष्ट्र स्वतंत्र है, तिरंगा लहराता है और विश्व हमारी शक्ति का लोहा मानता है। एक संकट का संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहा है न जाने क्यों शिक्षा शास्त्री, प्रबुद्ध वर्ग और सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। पहले जाति और संप्रदाय के नाम पर बंटते जा रहे देश को दंश सहना पड़ रहा है। 2 अप्रैल को जातीय सांप्रदायिकता का घिनौना खेल भारत भर में देखने को मिला । अब गरीब और अमीर शिक्षा का अधिकार नाममात्र के लिए दिया गया। कुछ शिक्षालय उनके लिए हैं जो धन, सत्ता संपन्न परिवारों के बच्चे हैं। उनकी उड़ान तो पूरी दुनिया में रहती है, पर आज भी अधिक संख्या उन बच्चों की है जो गरीब हैं, शिक्षा मंदिर की दहलीज से बाहर हैं या शिक्षा मंदिर के अंदर पहुंचकर भी अभावों से जूझ रहे हैं। सरकारी उदासीनता और लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। बहुत अच्छा हो सरकार पूरे देश के लिए एक नीति तय करे। विद्यार्थियों के लिए ऐसे शिक्षा मंदिर बनें जहां गरीब-अमीर का जाति वर्ग का कोई भेदभाव न हो सबको एक सी शिक्षा मिले। सभी सुविधाएं मिलें और आत्मसम्मान के साथ वे भारत के गौरवमयी इतिहास से परिचित होते हुए सुदंर भविष्य बनाने के लिए तैयार होकर ही विद्या मंदिरों से कर्मक्षेत्र में आएं।

सड़क बनी आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक

हर रोज सुबह-सवेरे समाचार पत्रों के पन्ने पलटते ही हमें हादसों की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। टीवी चैनल देखें हादसों के दिल दहला देने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। कुछ क्षण बाद कोई बड़ी खबर पुरानी खबर की जगह ले लेती है और इस भी हादसा तो हादसा है यह बुदबुदाकर कामकाज में जुट जाते हैं। सड़क हादसों के करीब खड़े लोग यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि अनहोनी को कौन टाल सकता है। ईश्वर ने इसकी मौत ऐसे ही लिखी थी। सुबह लोग घर से दफ्तर के लिए निकलते हैं, या बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकलते हैं, कोई घूमने

के लिए निकलता है लेकिन वह सड़कों पर तेज रफ्तार कारों, ट्रकों या अन्य किसी वाहन से कुचल दिए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा लोग बस-चलते-चलते ही मारे जाते हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सड़क परिवहन राज्यमंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि 2015-2017 के दौरान देश में हुए सड़क हादसों में करीब 4.45 लाख लोगों की मौत हो गई और 14.65 लाख लोग घायल हुए हैं। 2015 में 5 लाख से अधिक हादसे हुए जिनमें 1,46,133 लोग मारे गए, 2016 में भी डेढ़ लाख से ज्यादा 2017 में भी, 1,47,913 लोगों की मौत हुई। क्या सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या देश की यातायात व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े कर रही? देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, प्राकृतिक आपदाओं, अपराध या बीमारी से इतने लोग नहीं मरते जितने सड़क हादसों में मर जाते हैं। पहाड़ी राज्यों में बसों का गहरी खाई में लुढ़क जाने की घटनाएं लगातार सुनने को मील रही हैं। सर्दियों में धुंध के चलते दर्जनों वाहन आपस में टकरा जाते हैं तो लोग मर जाते हैं। आखिर हमारी संवेदनाएं सड़क हादसों को लेकर क्यों ठण्डी पड़ी रहती हैं? दरअसल सड़क हादसों को हम इसलिए नजरंदाज कर देते हैं क्योंकि इसके पीछे छिपा है नियतिवादी मनोविज्ञान।

आमतौर पर आम भारतीय सड़क हादसों को महज हादसा मानकर संतोष कर लेता है। सड़क हादसे होते क्यों हैं? इस सवाल के जवाब में लोग सड़क परिवहन व्यवस्था को कोसते हैं और कहते हैं कि सड़क पर गढ्ढे हैं, न रोशनी है, ड्राइवरों को पूरी ट्रेनिंग नहीं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाना, बस ड्राइवर शराब पीकर लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं। लोग 100 कारण गिनवा देते हैं लेकिन समाज कभी खुद अपने भीतर झांककर नहीं देखता कि आखिर वह सड़क हादसों से बचने के लिए स्वयं क्या कर रहा है? धनी परिवारों के बच्चे शराब के नशे में धुत्त होकर सड़क के किनारे सो रहे गरीब मजदूरों पर अपनी उत्साही कालेज छात्र ओवरटेक करने के चक्कर में दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उनकी कार की टक्कर से लोग मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं। अब स्कूलों और कुकुरमुत्तों की तरह उग आए कोचिंग सैंटरों के बाहर स्कूटी सवार छात्र-छात्राओं को तेज रफ्तार से रेस लगाते देखा जा सकता है। कभी-कभी सड़कें इन बच्चों को भी निगल जाती है। जिन्दगी में रफ्तार उतनी ही अच्छी होती है जिस पर नियंत्रण रखा जा सके। जब रफ्तार नियंत्रणहीन हो जाए तो फिर यह मौत का कारण बनती है। बड़े-बड़े घरों के नाबालिग बच्चे जब 100-125 की स्पीड से सड़कों पर कारों को दौड़ाते हैं तो उनके परिवारों को सोचना होगा कि यह रफ्तार उनके बच्चों को देती क्या है?

भारत के दो रूप हैं। एक धनी इंडिया है तो दूसरी तरफ गरीब भारत है। तेज रफ्तार के चलते कुचलने वाला भी भारतीय है और कुचला जाने वाला भी भारतीय है। मामूली सी टक्कर होने पर गोलियां चल जाती हैं और लोगों को मार दिया जाता है। रफ्तार की हवस ने लोगों को अंधा बना दिया है। रोडरेज की घटनाएं भी खतरनाक ढ़ंग से बढ़ रही हैं। सड़क सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी ढ़ांचे की जरूरत है। सड़क परिवहन पर नियंत्रण रखने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 को लागू किए भी तीन दशक बीत गए लेकिन यह कानून आज भी हकीकत से परे है। 1990 के दशक में भारतीय सड़कों पर वाहनों की संख्या 3 करोड़ से पार थी जो आज बढ़कर 15 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या ने भी भारतीय सड़कों को मृत्युपथ बना डाला है।

हैरानी इस बात की है कि डेढ़ लाख लोगो का हर वर्ष मौत का शिकार होना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता। यह संख्या एक छोटे से कस्बे के बराबर है। इसका अर्थ यही है कि हम हर वर्ष एक कसबा सड़क हादसों में खो देते हैं। जनता और राजनीतिक दल इसे चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनाते? डेढ़ लाख मौतों का अर्थ इतने ही परिवारों में जीवन भर के लिए मातम का छा जाना है। आज हालत यह है कि घर से बाहर जा रहा व्यक्ति सकुशल वापस आएगा या नहीं, यह विश्वास कोई नहीं दिला सकता। 80 फीसदी सड़क दुर्घटनाएं वाहन चालकों की गलती से होती हैं। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए वाहन चालकों को प्रशिक्षण के साथ-साथ सड़क सुरक्षा नियमों की पालना बहुत जरूरी है। युवा पीढ़ी को चाहिए कि वह गति सीमा का पालन करें और ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। अभिभावकों को भी नाबालिगों को सख्त बनाया जाए। विदेशों की तर्ज पर ही दुर्घटना होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बित किए जाने के नियम लागू किए जाने चाहिए। फतुहा भाजपा मीडिया शोभा कुमारी ने कहा कि सड़क आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है।

★ मुफ्तखोरी, नशे के तरह खतरनाक :- भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में मुफ्तखोरी का दुश्चक्र काफी व्यापक हो चुका है। देश में सब्सिडी की व्यवस्था है, लेकिन समुचित प्रबन्ध न और प्रशासकीय लापरवाही के कारण उसका पूरा लाभ इसके वास्तविक हकदारों को नहीं मिलता। चीजों का सस्ते में मुफ्त बांटने की नीति की वजह से राजकोष पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और विकास की योजनाओं के लिए धन की कमी तो हो ही रही है। भारत में चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल मुफ्तखोरी को हथियार बनाते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बावजूद मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुफ्त पानी, सस्ती बिजली, चावल से लेकर रंगीन टीवी, लैपटॉप तक देने के वाद किए जाते हैं। लोक-लुभावन घोषणाओं और मुफ्तखोरी सिर्फ एक विकृत संस्कृति या समस्या भर नहीं है, बल्कि यह अफीम जैसे खतरनाक नशे की तरह है। दक्षिण भारतीय राज्यों के चुनावों में बहुत कुछ बंटता ही रहता है। लोगों में मुफ्त खाने-खिलाने की एक आदत सी बन गई है। जिसे देखो वही जनता को कुछ न कुछ बांटे जा रहा है। जब खैरात बांट-बांटकर वोट हासिल करते हैं तो फिर राज्य कर्ज के बोझ तले दबेंगे ही।

इस सारी स्थिति पर मद्रास हाईकोर्ट ने करारी टिप्पणी की है कि सभी राशनकार्ड धारकों को मुफ्त पीडीएस चावल दिए जाने से लोग आलसी हो रहे हैं। पीडीएस चावल और दूसरी चीजें केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों को दी जानी चाहिएं। यह जरूरी है कि गरीबों और जरूरतमंदों को चावल और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएं लेकिन सरकारों ने राजनीति की वजह से इस तरह की सुविधाएं सभी वर्गों को देनी शुरू कर दी हैं। हर वर्ग को मुफ्त चावल दिए जाने का नतीजा यह निकला कि लोग अब सरकार से हर चीज मुफ्त में चाहते हैं। अब वे आलसी हो रहे हैं और छोटे-छोटे कामों के लिए भी बाहर से मजदूर बुलाने पड़ते हैं।

पीठ ने यह सवाल भी किया कि क्या कोई ऐसा सर्वे किया गया है कि जिसके जरिये बीपीएल परिवारों की पहचान की जा सके। अगर यह योजना गरीब परिवारों के अलावा दूसरों को फायदा पहुंचाती है तो यह जनता के पैसे से अन्याय है।

मद्रास हाईकोर्ट ने जो भी कहा वह वास्ताविकता है। देश में पहले रसोई गैस पर हर किसी को सब्सिडी दी जाती थी। धनी और उच्च वर्ग भी इसका फायदा उठाते थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपील की थी कि जो लोग आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं उन्हें स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों द्वारा सब्सिडी छोड़ देने से करोड़ों रुपए की बचत हुई और इन रुपयों से ही गरीबों को मुफ्त में गैस कनैक्शन देने की उज्ज्वला योजना साकार रूप ले सकी। तमिलनाडु की लोक-लुभावन राजनीति का इतिहास 1977 में एम.जी. रामचन्द्रन के मुख्यमंत्री बनने के साथ शुरू हुआ था, जब उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए मिड-डे-मील स्कीम की घोषणा की थी। उद्देश्य यह था कि अभिभावक अपने बच्चों का स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित कराएं। यह एक कल्याणकारी योजना थी, लेकिन इससे मुफ्त वितरण की संस्कृति आरम्भ हुई। वर्ष 2006 में करुणानिधि ने रंगीन टीवी का वादा कर चुनावी जीत हासिल कर ली

थी। अम्मा जयललिता ने महामुफ्तवाद चलाया। हर कल्याणकारी योजना को 'अम्मा-8 के नाम से जोड़ा गया। 1.91 करोड़ कार्डधारकों को मुफ्त चावल, मिनरल वाटर, नमक और सीमेंट पर सब्सिडी दी गई। छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के लिए मुफ्त बिजली के पंखे, इंडक्शन चूल्हे, धोती, साड़ी, लैपटॉप, साइकिल तथा दुधारू गाय, बकरियां और भेड़ें बांटी गईं। घरेलू ग्राहकों को 100 यूनिट और बुनकरों के लिए 750 यूनिट मुफ्त बिजली दी गई। फिर ऐसी ही योजनाओं का अनुसरण अन्य राज्यों ने किया। आंध्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों ने भी मुफ्तखोरी की संस्कृति को प्रोत्साहित किया। अगर लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं मुफ्त में मिलने लगेंगी तो फिर काम कौन करेगा? आम आदमी मेहनत-मजदूरी अपना और परिवार का पेट पालने के लिए करता है। अगर उसे मुफ्त या सस्ते में सब कुछ उपलब्ध होगा तो वह निठल्ला ही बन जाएगा।

दूसरी ओर बड़ी-बड़ी कम्पनियां और बड़े-बड़े पूंजीपति सबसे ज्यादा मुफ्तखोर है। सभी बड़ी कम्पनियों और पूंजीपतियों को सस्ते में जमीन चाहिए, टैक्स में छूट चाहिए, हर चीज में सब्सिडी चाहिए, बैंकों से ऋण चाहिए। सरकार दिल खोलकर कार्पोरेट सैक्टर पर धन लुटाती है। आज भी देश की आबादी को बड़ा हिस्सा कुपोषण का शिकार है। देश मे पूंजी निवेश से कहीं ज्यादा पैसा मुफ्तखोरी पर लुटाया जा रहा है। कोई सरकार एक सीमा के बाद किसी को कुछ नहीं दे सकती। राज्य सरकारों को चाहिए कि गरीबों को मुफ्त में सामान मिले लेकिन आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों को ऐसा कुछ नहीं दिया जाए ताकि देश के लोग मुफ्तखोर न बन जाएं। जितना धन ऐसी योजनाओं में लुटाया जा रहा है उसमें अस्पताल, स्कूल बनाए जा सकते हैं। सरकारों की सोच यह होनी चाहिए कि देश के लोग पढ़-लिखकर खुद सक्षम बनें मगर विडम्बना यह है कि राजनीति की मुफ्तखोरी को खत्म करने की इच्छुक नहीं। देश मुफ्तखोरी के दुश्चक्र में फंसा हुआ है। इस दुश्चक्र से निकलने के लिए नई नीतियों को बनाया जाना जरूरी है। कठिन मार्ग अपनाना होगा ताकि सरकारों के राजकोष सपर अधिाक दबाव न पड़े।

★ अपराध रोकने के लिए अधिकारियों पर अंकुश रखना होगा? भ्रष्टाचारियों को सजा कानून से नहीं काउण्टर से देना होगा। :- आज अपराध और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट चुकी है, इन्हें रोकने के लिए हालांकि पहले से कानून बना हुआ है। किन्तु उस कानून से अपराध और भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, जो कानून पहले से बना हुआ है उस कानून से अपराधी और भ्रष्टाचारी ही पैदा हो रहे है। मैकाले शिक्षा नीति से समाज को संस्कार हीन बनाया जा रहा है। संस्कारवान बनाने के लिए गुरूकुल पद्धति लाना होगा। अपराध रोकने के लिए जो कानून बना हुआ है, वह चोर को पकड़ने के लिए डाकु तैनात है तथा भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़े भ्रष्टाचारी तैनात है, साथ ही जनसेवक को पाठ धन सेवक अदा कर रहे है।

भ्रष्टाचारियों द्वारा बनाये गये कानून से भ्रष्टाचार रोका नहीं जा सकता है। इस हाथ रिश्वत, उस हाथ कागज, सरकारी दफतरों में सभी काम दलालों के हवाले हर काम का रेट तय। बिचौलिय के बिन जमीन के कागजात खतियान निकलवाने का काम जितना मुश्किल, रिश्वत देने पर उतना ही आसान, इसी तरह गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ऑनरबुक ट्रांसफर, बाहर की गाड़ी की एंट्री और फिटनेश जांच के लिए ली जाती है। मोटी रकम। यह सब बड़े-बड़े अधिकारियों के आस-पास ही होता है। जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए तबादला, सस्पेंड, निलंगन जैसे उपहार बंद कर काउण्टर करने जैसे कठोर कानून बनाना होगा तथा निर्दोष को जेल भेजना तथा दोषी को छोड़ने वाले पुलिस अधिकारियों को भी बर्खास्त और जेल जैसे कानून बनाना होगा। 70 साल में समाज को एतना जहरीला बना दिया गया है वह जहर समझा बुझा कर दिमाग से नहीं निकाला जा सकता है।

भ्रष्ट अधिकारियों, विधायकों, सासंदों, मंत्री का सुधार कानून और जेल भेजने के कानून से नहीं किया जा सकता है। चीन के तरह एक दो हजार काउण्टर हुआ कि भारत भी सुधर जाएगा। शिक्षा में मैंकाले पद्धति हटाना होगा तथा सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना होगा। समाज में सुधार लाने के लिए धन सेवक नहीं जन सेवक विधायक सांसद चुनना होगा। वैसे विधायक और सांसद बनाना होगा जो अपने क्षेत्र में नित्य दिन जन्ता दरवार लगा कर जनता को न्याय करते रहे। अन्यथा महात्मा गांधी, राममनोहर लोहिया, पं दीनदयाल उपाध्याय तथा सुभाष चन्द्रबोस, चन्द्रशेखर आजाद, भंगत सिंह जैसे शहीदों के सपनो का भारत नही बनाया जा सकता है सुभाष चन्द्रबोष ने कहा था कि भारत एक हजार साल तक गुलाम रहने के कारण दिमाग में इतनी गुलामी का जहर घोल दिया गया है कि आजादी के बाद भी गुलामी पंसद करने वालो की संख्या अधिक होगी। उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद 20 साल भारत की सत्ता सेना के हाथ में सौपना होगा। अन्यथा देश को सुधारा नही जा सकता है। ●

आप भी बनें पत्रकार

भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टों के खिलाफ बेझिझक कलम उठाईये। बेरोजगारी के अभिशाप को मिटायें। देश के सभी प्रदेश की राजधानी और देश के सभी प्रदेश के शहरों में संवाददाता की आवश्यकता है। कर्मचारी नहीं हिस्सेदार बने। जितना श्रम उतना पारिश्रमिक पायें।

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308

आखिर कब पकड़ा जाएगा कुख्यात वीरप्पन

ऐसा नहीं है कि जमुई जिले में अपराध और नक्सलवाद का परचम है। पुलिस ने नक्सलवाद और अपराध पर लगाम बहुत पहले ही लगा चुका है। जरूरत है तो उसे बरकरार रखने की। पर कुछ छुटभैये अपराधी मानो पुलिस को नाकोदम कर रखा है। उसी में एक है जमुई सदर थानान्तर्गत का कुख्यात बन चुका सुभाष महतों उर्फ वीरप्पन। वीरप्पन के नाम का आतंक ऐसा है कि काकन पंचायत के पूर्व मुखिया समेत गॉव के करीब दो दर्जन परिवार गांव छोड़ कर पलायन कर चुके हैं। भूमिहार को मानो गॉव छोड़ने का फतवा जारी कर रखा है वीरप्पन। आखिर कब जेल के सलाखों में होगा वीरप्पन? किसकी हत्या का इंतजार कर रही है पुलिस? मात्र 15 वर्ष के उम्र से ही अपराध की दुनियां में कदम रखने वाला वीरप्पन को जिले के पुलिस कप्तान ने दो माह पहले अक्टूबर में ही केवल सच के साक्षात्कार में कहा था कि हम लगे हुए हैं पर आज फिर उसके नाम एक और हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका हैं। जमुई से हमारे जिला ब्यूरो **अजय कुमार** की रिर्पोट :-

विगत माह जिले में जिस प्रकार से हत्या का सिलसिला जारी रहा उससे तो साफ दिखता है कि जमुई में अपराधियों का मनोबल काफी उॅचा हो गया है। पुलिस और कानून का तो मानो खौफ ही नहीं रह गया है अपराधियों में। एक नक्सल घटना में दो लोगों की मौत। बम मार कर अति व्यस्ततम जमुई-झाझा रोड के बीच में स्कॉपियो सवार राजेश यादव और मनोज यादव की बम और गोली मार हत्या। सदर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर में कथित बालू माफिया राधेश्याम यादव की हत्या। समेंत छः हत्याएं हो चुकी है एक माह में। पर हम इन सब पर नहीं जा रहे। जिला प्रशासन चाहे जो माने पर इतना तो तय है कि जिले में अपराध का ग्राफ विगत दिनों कॉफी बढ़ गया है। नक्सली तो नक्सली अपराधी भी दिनदहाड़े रोड पर तो कहीं घर से खींच कर तो कहीं घर के दरवाजे पर सरेआम हत्या कर दे रहा है। हम बात कर रहे हैं 31 जनवरी के शाम पॉच बजे काकन गॉव के 21 वर्षीय बिनोद सिंह के पुत्र मणिकांत की हत्या का। जिसका हत्या सुभाष महतो उर्फ वर्तमान का वीरप्पन ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर दिया। वीरप्पन बचपन में सुभाष नाम से जाना जाता था पता नहीं कौन सा फिल्म और कहॉ से उसे वीरप्पन बनने का शौक चढ़ा कि वह आज आतंक का प्रयाय वीरप्पन बन बैठा। हालांकि गॉव के लोगों से जमुई के वीरप्पन के बारे में अलग-अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष को वीरप्पन सुनने में अच्छा लगता था तथा शाथियों से सुभाष नहीं वीरप्पन बोलने को कहता था तो कुछ ग्रामिण बताते हैं कि पुलिस वाले ही वीरप्पन नाम दिया है। हालांकि हम काकन में वीरप्पन को ठूंठने का भरसक प्रयास किया पर वीरप्पन नहीं मिला। हालांकि हम केवल सच का अक्टूबर अंक में प्रकाशित खबर जो मुख्य रूप से जमुई के आतंक का प्रयाय की खबर थी उसे ग्रामिणों को वीरप्पन तक पहुॅचा देने की बात कही। खबर को ग्रामिण बड़े मन से पढ़ रहे थे। कुछ वीरप्पन के सहयोगी तो कुछ खौफजदा लोग भी थे। जब उनसे सुभाष महतों के बारे में पूछा गया तो कोई सुभाष के बारे में नहीं जानता पर वीरप्पन को सभी जानते थे। वीरप्पन को जब एक ने चोर-चुहाड़ बोला तो ग्रामिणों में एक अजीब का मुखड़ा बन

जे. रेड्डी
पुलिस अधीक्षक, जमुई

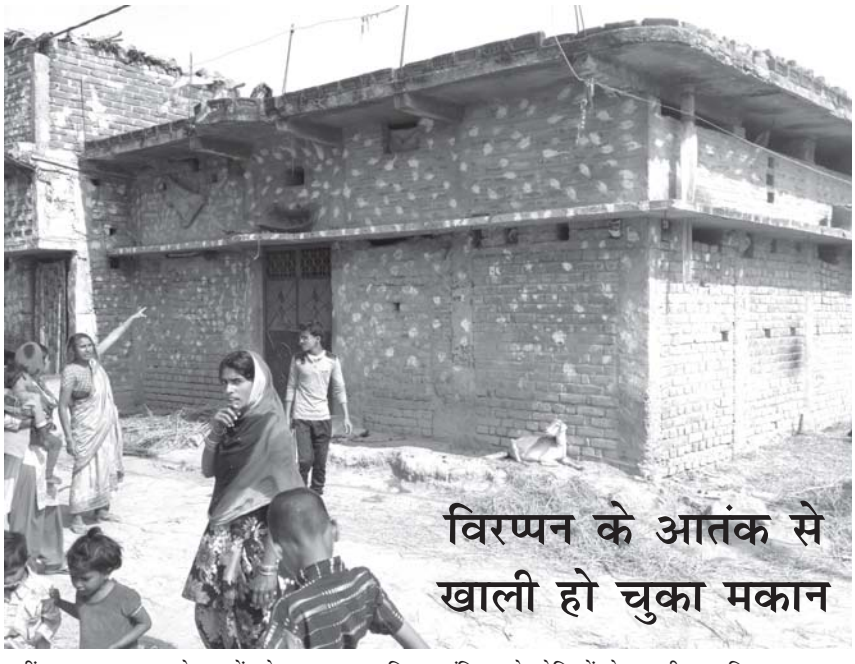

विरप्पन के आतंक से खाली हो चुका मकान

गया क्योंकि वीरप्पन चोर नहीं वास्तव में वीरप्पन था और उसका खौफ न सिर्फ काकन अपितु जमुई पुलिस में भी देखा जा सकता है। क्योंकि वीरप्पन इस प्रकार से कुख्यात हो गया है कि वह मुंह से नहीं गोली से बात करता है।

डीजीपी से लेकर एसपी तक बताते हैं कि घटना कभी भी कहीं भी घट सकती है उसे रोका नहीं जा सकता। इस बात को हम भी मानते हैं और आप भी। दुश्मनी से और बदले की भावना से घटित घटना हो सकती है पर जब कोई छोटी-छोटी सी बात को लेकर गोली से बात करता हो और पुलिस उसे कुछ भी बिगाड़ नहीं सक रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? जमुई जिला मुख्यालय से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है काकन गॉव। यह गॉव जैन सर्किट से भी जुड़ा है। भगवान महावीर का एक भव्य जैन मंदीर है यहॉ जो देशवासियों को शांति और अहिंसा का संदेश वर्षो से देते आ रहा है पर यहॉ एक अपराधी सुभाष महतों पिता पैक्स अघ्यक्ष जलधर महतों कब चन्दन तस्कर वीरप्पन बन गया जिसे जमुई जिले की पुलिस करीब एक वर्षो से ठूंठ रही है पर आज तक पुलिस के पकड़ में नही आया। कांस्टेबल राजेन्द्र मिश्रा की माने तो तीन माह पहले पुलिस 15 दिनों तक काकन में रह कर वीरप्पन को ठूंठती रही पर वीरप्पन पकड़ में नहीं आया। जिस दिन केवल सच प्रतिनिधि काकन में रिर्पोटींग कर रहे थे उस दिन भी एसआई विजय कुमार के साथ पुलिस की टीम गॉव का खाक छान रही थी। राजेन्द्र मिश्रा बताते हैं कि हमलोग तीन माह पहले भी इस गांव में 15 दिनों तक केम्प किया था पर वीरप्पन पकड़ा नहीं गया। वे बताते हैं कि इस बार हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। वही एसआई विजय कुमार ने बताया कि हमलोग ग्रमिणों से उसका टोह पता कर रहे हैं पर ग्रामिण सहयोग नहीं कर रहा। उनके बातों से स्पष्ट था कि ग्रामिण वीरप्पन का सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने हमसे वीरप्पन का फोटो का डिमांड किया और हमें रिर्पोटिंग के दौरान वीरप्पन से मुलाकात पर खबर देने की भी बात कही ।

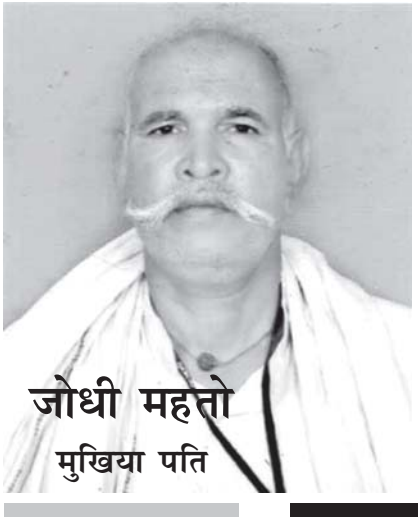

जोधी महतो
मुखिया पति

गौरतलव है कि काकन वर्षो से बर्चस्व के आग में जल रहा है। बताया जाता है कि यहॉ अबतक 18 मर्डर हो चुका है। अकेले वीरप्पन पर पांच-छ: हत्याओं का मामला दर्ज है। बात-बात पर गोली चला देना और दहशत फैला कर रंगदारी वसूलना वीरप्पन का मुख्य पेशा है। कुछ जाति विशेष के ग्रामिणों में वीरप्पन का खौफ ऐसा कि वह वीरप्पन के बारे में बात करने से भी कतराते हैं। 20 घर की आबादी वाले भूमिहार जाति के लिए गॉव छोड़ने का फरमान जारी कर रखा है वीरप्पन। काकन गॉव में कुल 800 घरों की आबादी है। 400 घर सिर्फ वीरप्पन के महतों जाति के हैं। 200 घरों वाला मांझी परिवार में आज भी शराब की घंघा फल-फूल रहा है और वर्तमान में हुए हत्या का बीज भी यहीं बोया गया बताया जाता है। सूत्र बताते हैं कि एक दिन पहले काकन में ग्रामिणों द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया था। जिसमें जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप और चकाई के पूर्व विधायक सुमित कुमार सिंह शामिल हुए थे। इस समारोह में ऐसा तय किया गया था कि सबकुछ ठीक हो जाएगा। पर अगले ही दिन वीरप्पन ने वह कर दिया जिसका अंदेशा शायद किसी को नहीं था। आज से पॉच माह पूर्व 25 अगस्त 2018 को भी वीरप्पन ने एक रिटायर्ड शिक्षक सत्यनारायण पंडित को गोलियों से छलनी कर दिया था। आज यह परिवार गॉव छोड़ चुका है। वीरप्पन गॉव के ही प्रसिद्ध सिंह का करीब चार कट्ठा जमीन पर तलाव खुदबा कर खुद के कब्जे में रखे हुए है। यह जमीन जैन मंदीर के ठीक समीप कोई भी देख सकता है। यही नहीं वेवजह ही ट्रेक्टर घुमाने के विवाद में मो0 नेहाल के घर पर जाकर गोली चला दिया जिसमें वह घायल हो गया तथा घर में बंधा एक खस्सी गोली का शिकार हो गया। वहीं गॉव का ही अशरफ मिंया के घर पर गोलीबारी का निशान साफ देखा जा सकता है। अशरफ मिंया वर्षो से घर छोड़ कर जा चुका है। दहशत का प्रयाय बन चुका वीरप्पन का नाम सबसे पहले वर्ष 2014 में आया था। उस समय वह नावालिक था जब ठेकेदार नीरज सिंह की हत्या हुई थी। उसके बाद तो मानो वीरप्पन का अपराध से नाता ही जुड़ गया। वर्ष 2018 में ही वह इतना घटना का अंजाम दे दिया कि ग्रामिण अब गांव में रहना मुनासिब नहीं समझते है। 26 जनवरी के दिन में सतायन हाई स्कूल में गोली चला दिया तथा एक मांझी परिवार के साथ मारपीट किया। 2015 की बात है जब पंचायत भवन में आम सभा हो रहा था तो वीरप्पन कृष्णनंदन सिंह पर गोली चला दिया। गोली उनके कनपट्टी को छूकर चला गया वे घायल हो गये। वीरप्पन ने जितनी बार भी गोली-बारी किया सरेआम किया। उसे किसी बात का कोई पचताबा नही कि उसने हत्या जैसे जघन्य अपराध क्यों किया है। वह एक सनकी साइकोकिलर है जिसे हत्या तथा गोली-बारी करने में मजा आता

है। अक्टूबर माह में ही केवल सच ने लिखा था कि अगर वीरप्पन का अपराध का इलाज नहीं कराया गया तो उसे अपराध का दुनियां का दूसरा वीरप्पन बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसे उसने विनोद सिंह का 21 वर्षीय पुत्र की हत्या कर साबित भी कर दिया। बिनोद सिंह बताते हैं कि हमारे सामने से वीरप्पन सहित अन्य ने हमारे बेटे को हमारे घर से खींच कर ले जाने लगा तो हम हमारी माँ और पत्नी मुखिया पति जोधी महतो और वीरप्पन के पैर में लटक गये कि इ कि करब करो हो मुखिया जी पर वह जल्लाद नहीं मारा हमारा बेटा का हत्या कर दिया। वे बताते हैं कि कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन जिस प्रकार से पहला हत्या एक बच्चे का उसके माँ से छिन कर गोली मार कर कर दिया उसी प्रकार से हमारा बेटा का हत्या भी वीरप्पन हमारे गोदी से छीन कर कर दिया। वे बताते हैं कि पूर्व के थानाध्यक्ष संजय विश्वास वीरप्पन को बचा रहे थे। वे बताते हैं कि वर्तमान मुखिया मालती देवी का पति जोधी महतो, जयराम महतो, वीरप्पन का पिता सौदागर महतों यहाँ का पूर्व का सबसे बड़ा अपराधी रहा है। आंकड़ो पर गौर करें तो 1998 में चन्द्रदेव पासवान, 2001 में भाषो मिंया, 2005 में दशरथ सिंह, 2004 में लाटो मांझी, सिझौड़ी का नरेश महतों, पुरसंडा का दानी सिंह की हत्या में इनलोगों का नाम है। वर्ष 2014 में नीरज सिंह की हत्या में जोधी महतों का बेटा कमलेश महतों, सौदागर महतो का बेटा सुभाष महतों का नाम मुख्य रूप से आया था। वर्ष 2017 में तत्कालिन एसपी जयंतकांत के समय में वीरप्पन बड़े ही नाटकीय ठंग से पकड़ा गया था पर वर्ष 2018 में जेल से निकलने के बाद से ताबरतोड़ अपराध का अंजाम देते जा रहा है और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। दो दर्जन ग्रामिण घर छोड़ कर पलायन कर चुके हैं। दिनोदिन वीरप्पन का मनोबल बढ़ता जा रहा है और कभी भी किसी की भी हत्या करने को आतुर है। जमुई पुलिस पता नहीं कब वीरप्पन की चुनौती को स्वीकार करता है? कब ग्रामिणों में सुशासन का असर दिखता है। गॉव से ही सटा है एमएलसी संजय सिंह का गॉव और आज वहाँ के भूमिहार गॉव छोड़कर पलायन को मजबूर है। एमएलसी संजय सिंह का भी गॉव का मुखिया गीता मंडल से अदाबत चल रहा है। आज गीता मंडल जेल में है। कहीं इसका परिणाम स्वरूप भी तो वीरप्पन ऐ हत्या नहीं कर रहा है? सबाल कई है? कब होगी इस क्षेत्र में शांति और कौन होगा शांति दूत?

प्रसिद्ध सिंह का यह जमीन, जिसपर विरप्पन ने तालाब खुदवा दिया

जब मुखिया पति जोधी महतों से किसी दूसरे के मोबाईल से बात की गई तो वे बताते हैं कि वीरप्पना और उ लड़का सब जौरे रहता था। हमलोग का बिनोद सिंह आर से कोई दुश्मनी नहीं रहा है। मुशहरी में सब दारू पिया और वहीं कुछ हुआ जिसका सूचना वीरप्पना को मिल गया और फिर उ आकर के बुतरूआ को पकड़ के ले गया फिर लास्ट में गोली मार दिया। हमलोग के पूर्व मुखिया नारो सिंह बिनोद सिंह आर से कोई दुश्मनी नय रहा है। हॉ नारो सिंह और नीरज सिंह में पहले से दुश्मनी रहा है। वर्ष 2013 में होली के दिन मेरा बेटा कांग्रेस के साथ नीरज सिंह मार-पीट किया। हमरा चचेरा भाई जदू महतों के 2011 में उसके बाद गोतिया में प्रकाश महतों कृष्णा महतो के मर्डर कर दिया गया तब से हमलोग के नीरज सिंह से अदावत हो गया। फिर नीरज सिंह के मर्डर हमलोग किया। नीरज सिंह नारो सिंह के बेटा प्रमोद सिंह उर्फ बगोरन सिंह को भी मारा। इस बार के पंचायत चुनाव में हमको प्रशासन उठा लिया। हमको जनता ने चाहा तो हम जीत गये। फिर सब अच्छा चल रहा था और इ बीरप्पना झगड़ा कर लिया। हमसे वीरप्पना का पटरी नहीं खाता है। हमारे इस सबाल पर कि क्या वीरप्पन अगला पंचायत चुनाव लड़ेगा तो आप मैदान छोड़ दीजिएगा। वीरप्पना हमको मानबे नहीं करता है, उ पागल कुत्ता हो गया है अब उसको धराना जरूरी है। जहॉ हम पंचैती करते हैं वहा उ दहशत पैदा कर देता है। सब पदवा उहे लेगा उसका बाप तो पहले से पैक्स अध्यक्ष है और उ मुखिया के चुनाव कैसे लड़ेगा। तभी किसी ने कहा कि उ जिला परिषद् का चुनाव लड़ेगा। यहॉ एक बात स्पष्ट कर दूं कि मुखिया पति जोधी महतों भी आपराधिक छवि का रहा है। कुख्यात वीरप्पन का पिता सौदागर महतों पैक्स अध्यक्ष है। मुखिया जोधी महतों के घर से पता चला कि वीरप्पन का भी लालसा जिला परिषद् चुनाव लड़ना है। पर क्या आज के सुशासन की सरकार में भी चुनाव लड़ने के लिए दहशत पैदा करना जरूरी है यह एक यक्ष प्रश्न है? अब सबाल यह उठता है कि जिला के पुलिस कप्तान कहते हैं कि अपराध नहीं बढ़ा है। क्या ऐसे अपराधी जिला प्रशासन को चुनौती नहीं दे रहा है। इधर नये डीआईजी मनु महाराज जमुई में अमन-चैन कायम करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। जिले के तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खुद जाकर मुआयना कर रहे हैं ताकि नक्सलवाद को जमुई से समाप्त किया जाय। पर नक्सलवाद तो समाप्त हो ही जाएगा पर अपराध सुसाशन को मुंह चिड़ा रहा है। और उसमें वीरप्पन को उसका असली स्थान दिखाने के लिए कब तक एक जिले की पुलिस चुनौती के रूप में लेता है यह देखना अभी बाकी है। ●

लक्ष्य एक मार्ग भिन्न

● **प्रो० रामजीवन साहु**

30 नवम्बर 2018 को मैं महाराष्ट्र की उपराजधानी कहा जानेवाला शहर नागपुर पहुँचा। वहाँ जाने के पीछे दो उद्देश्य रहा है। प्रथम कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ० केशव राव बलिराम राव हेडगेवार और डॉ० भीमराव अंबेदकर की दीक्षा भूमि को नमन करना था। दोनों महामानव का लक्ष्य एक था परन्तु मार्ग भिन्न था।

डॉ० हेडगेवार :– सर्वप्रथम मैं केशव राव बलिराम राव हेडगेवार के स्मारक '' स्मृति मंदिर'' का दर्शन किया। डॉ० साहब का जन्म 1 अप्रैल 1889 में नागपुर में हुआ। ये जन्मजात राष्ट्रभक्त थे। मेडिकल की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का एक स्वयंसेवी संगठन खड़ा किया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। तत्कालीन समय में डॉ0 साहब को छोड़कर किसी को यह विश्वास नहीं था कि एक स्वयंसेवक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बनेगा। ऐसे युगनायक के दर्शन से राष्ट्रभक्ति का भाव जाग्रत हो इसलिए रेशमबाग में स्मृति मंदिर बनाया गया है। स्मृति मंदिर के परिसर में ही नावनुमा विशाल भवन बना हुआ है। इसमें एक बहुत बड़ा सभागार भी है। इसके निचले तल में भोजनालय है, जिसमें पालथी मारकर एक साथ पन्द्रह सौ व्यक्ति भोजन कर सकते हैं। इसके ऊपरी तल पर तृतीय वर्ष करनेवाले स्वयंसेवकों का बौद्धिक वर्ग होता है। संघ में भी शैक्षणिक शिक्षा की तरह इसके कई स्तर होते हैं। जैसे प्रतिदिन का शाखा वर्गकक्षा के समान होता है। प्राथमिक वर्ग मैट्रिक के समान होता है। प्रथम वर्ष इन्टरमीडिएट के समान होता है। द्वितीय वर्ष ग्रेजुएट के समान होता है। तृतीय वर्ष मास्टर डिग्री के समान होता है। तृतीय वर्ष कर चुके स्वयंसेवकों का भी प्रशिक्षण होता है जो पी०एच०डी० डिग्री के समान है। तृतीय वर्ष प्रतिवर्ष नागपुर में ही होता है। इस वर्ग में भारत के अतिरिक्त विदेश के स्वयंसेवक भी आते हैं।

वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक माननीय मोहनराव भागवत जी से मेरी मुलाकात हुई। उनसे जब साक्षात्कार के लिए समय मांगा तो, वे हँसते हुए कहा कि इसके लिए आपको अरूण जी से अनुमति लेनी होगी। फिर मैं वहाँ के लोगों से कुछ जानकारियाँ प्राप्त कीं जो निम्न हैं।

☞ संघ की स्थापना 27 सितम्बर 1925 विजयादशमी के दिन हुआ।

☞ 17 अप्रैल 1926 में संघ का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा गया।

☞ सर्वप्रथम शाखा 28मई 1926 में नागपुर के मोहिते के बाड़ा में लगा।

☞ आरंभ में ब्राह्मण ही शाखा आया करते थे इसलिए सरसंघचालक उन्हीं में से हुआ करते थे परन्तु यह कोई परिपाटी नहीं है। प्रो० राजेन्द्र सिंह उपाख्य रज्जू भैया भी सरसंघचालक बने, जो ब्राह्मण नहीं थे।

☞ इसे स्वयंसेवी संगठन कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका गणवेश (ड्रेस) अपने पैसा से बनाया जाता है। कहीं प्रशिक्षण होता है तो भोजन व्यय और आनेजाने का मार्ग व्यय भी स्वयं वहन करता पड़ता है। इतना ही नहीं सप्ताह में एक दो दिन अधिकारी या प्रचारक को अपने घर का सदस्य समझकर चाय, अल्पाहार और भोजन भी कराना पड़ता है।

★ **डॉ० भीमराव अंबेदकर :–** 2 दिसम्बर 2018 दिन रविवार को दीक्षा भूमि का दर्शन किया। दीक्षाभूमि का दर्शन कर मैं फूले नहीं समाया। इसे देखकर सचमुच में एक नयी अनुभूति प्राप्त हुई। जानकारी करने के बाद पता चला कि परम पूज्य बोधित्व बाबा साहब डॉ० भीमराव अंबेदकर का 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 1935 में ही उन्होंने एक सभा में कहा था कि मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ हूँ परन्तु हिन्दू धर्म में मरूँगा नहीं। साथ हीं उन्होंने यह भी कहा कि हम भारत के मूल निवासी हैं और हम किसी ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारा भारतप्रेम बाँटकर या छीनकर विदेश में ले जाने का कारण बने। यह राष्ट्रभक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। धर्मान्तरण से राष्ट्रन्तर से उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं था। 14 अक्टूबर 1956 को सुबह 9 बजे से हीं बौद्ध दीक्षा समारोह नागपुर में प्रारंभ हुआ। 2 लाख से अधिक दलित धर्मान्तरण के लिए इकट्ठा हुए और हजारों की संख्या में दलित लोग समारोह को देखने जमा हुए थे। डॉ० अंबेदकर के अलावे उनकी पत्नी डॉ० सविता अंबेदकर पुत्र श्री यशवन्त राव अंबेदकर, नागपुर हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भवानी शंकर नियोगी और औरंगाबाद के मिलिन्द कॉलेज के प्राचार्य चिटनिश बौद्ध धर्म की दीक्षा लिये।

डॉ0 अंबेदकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के महु कैन्ट में 14वाँ रत्न के रूप में हुआ। 1897 में कैम्प स्कूल सतारा में नामांकन करवाया गया। 1907 में मैट्रिक पास किये और उसी साल रामाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। 1912 में उन्होंने बी०ए०

पास किये 1915 में एम०ए० कोलम्बिया विश्वविद्यालय से पास किये। 1917 में भारत में जातिभेद नामक एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। उसके बाद ये भारत की अर्थव्यवस्था पर एक और प्रबन्ध लिखा, जिस पर कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने इनको पी०एच०डी० की डिग्री प्रदान की। 11नवम्बर 1918 को डॉ0 अंबेदकर 425 रू0 प्रतिमाह पर सीडेनहोम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। ख्याति प्राप्ति तक ये स्पर्शयता का मार झेले साथ ही इस समाज के लोगों ने भी खूब झेला। इसके फलस्वरूप इस कोढ़ को समाप्त करने के लिए अप्रैल 1925 में महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के मालवन नामक गाँव में बम्बई प्रान्तीय स्पर्श्य परिषद् का पहला अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अम्बेदकर जी ने की। लक्ष्य की प्राप्ति तक यह आन्दोलन चलता रहा। 15 अगस्त 1947 में भारत दो टुकड़ों में बँटकर स्वतंत्र हुआ तो 29 अगस्त 1947 को विधान का संविदा तैयार करने के लिए एक समिति बनी, जिसका अध्यक्ष डॉ0 अंबेदकर को बनाया गया।

स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमण्डल में डॉ0 अंबेदकर और डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे योग्य परन्तु कांगेस विरोध नेताओं को शामिल कर नेहरू जी ने उदारता का एक मिसाल कायम किया। अंबेदकर जी के जीवन में 14 का बड़ा हीं महत्व है। अपने माता–पिता की चौदहवीं संतान, 14 अप्रैल जन्म, 14 वर्ष में हाई स्कूल में प्रवेश, 1914 में अमेरिका में लाला लाजपत राय से मुलाकात, नाम में मात्राओं को मिलाकर 14 अक्षर हैं। 14 के कारण हीं लगता है ये राजनीति में चौदहवीं के चाँद के जैसे चमकते रहे। शीर्षक देखने में आपको अटपटा लगता होगा परन्तु बात बिल्कुल सत्य है। दोनों समाज सुधारक के जन्मकाल में मात्र् 2 वर्ष 3 महीने 13 दिन का अन्तर है। इतना अन्तर होने के बाद भी दोनों युगपुरूष 1925 में क्रान्तिकारी मार्ग का श्रीगणेश किये। डॉ0 हेडगेवार का सोच था कि संपूर्ण समाज की कुरीतियों को दूर कर संगठित हिन्दू समर्थ भारत का निर्माण कर भारत माता को परम वैभव पर लाना है तो डॉ0 अंबेदकर का सोच था कि स्पृश्यता को मिटाकर भारत को सोने की चिड़िया बनाऊँगा। 1925 में डॉ0 हेडगेवार नागपुर में अपने घर पर 15–20 आदमी बैठकर समाज की कुव्यवस्था पर विचार–विमर्श कर रहे थे वहीं दूसरी ओर डॉ0 अम्बेदकर 1925 में त्रावणकोर रियासत के बाइकाम में अछूतोद्धार आन्दोलन का शुरूआत कर रहे थे। जहाँ डॉ0 हेडगेवार ने कहा मैं हिन्दू में जन्म लिया और हिन्दू में मरूँगा भी। वहीं डॉ0 अंबेदकर ने कहा कि मैं हिन्दू में जन्म लिया हूँ परन्तु हिन्दू में मरूँगा नहीं। ●

किसानों पर राजनीति जायज नहीं : रामजीवन सिंह

● **मणिभूषण तिवारी**

आर.जे.डी. के कैडर नेता रहे रामजीवन सिंह जो कि कभी कांति सिंह के मुँहबोले बड़े भाई हुआ करते थे। उनका राजनीतिक ह्रास होने के बाद आज किसान कार्य कर रहे हैं और उन्होंने किसानों, मजदूरों के उपर हो रहे दोहरी राजनीतिकरण के खिलाफ एक प्रेस रिलिज कर केवल सच प्रतिनिधि को बताया कि कैसे आज किसानों के उपर राजनीति किया जा रहा है। आज किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं क्या पहले भी किसान आत्महत्या करते थे। आजादी से पहले अंग्रेजों ने किसानों पर और उनके फसलों पर कब्जा जमा कर उनका शोषण किया करते थे। और जब वे कमजोर हो जाते तो उन्हें मार देते थे। आज किसानों पर थोड़ा रहम कर के धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा फायदा पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में जो किसान आंदोलन का रूपरेखा अख्तियार कर रहा है, वो कुछ राजनीतिक लोग और किसान लोग द्वारा किया जा रहा है, ऐसा होना चाहिए लेकिन राजनीति और दलबन्दी दोनों अलग-अलग चीजें होंती है। राजनैतिक दलबन्दी से किसान आंदोलन को हानि होता है, जबकि राजनीति से किसान आंदोलन को बल मिलता है। किसान आंदोलन में जहाँ अधिकार पाने, व्यवस्था परिवर्तन करने और सुव्यवस्था कायम करने के प्रयास का नाम हीं राजनीति है। अत: किसान आंदोलन को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। बुनियादी तौर पर राजनीति में किसान शक्ति की भूमिका अदा करती है। 60 से 65% जनता गाँवों में निवास करती है है। अत: किसान जब तक राजनीति से अलग रहेगा तब तक राजव्यवस्था सही ढंग से नहीं चल सकती। दरअसल किसानों को एक सजिश के तहत चतुराई से राजनीतिक परिदृश्य से परे आजतक ढकेला जाता रहा है। उसकी भागीदारी राजनीति में जो होना चाहिए वह नहीं है। यही कारण है कि वर्तमान राजनीति सीमित दृष्टिकोण की राजनीति में तब्दील हो गई है। व्यवस्थापक राजनीति नहीं है। राजनैतिक दलबन्दी उसपर हावी है। सिद्धान्त: बहुसंख्यक वर्ग हम किसानों के तबके के ही हैं और भागीदारी नहीं के बराबर है, जो राजनीति में होनी चाहिए और नेतृत्व भी किसानों से उभरना चाहिए। जिसके चलते हम किसानों को विभिन्न राजनैतिक दलबन्दी में बाँट कर रखा गया है। इस देश के कोई भी सरकार के पास किसान के किसी भी समस्या का समाधान आजतक नहीं किया गया है। किसान आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में आज भी उतने ही पिछड़े हैं, जितने आजादी से पहले थे। अन्तर सिर्फ इतना है कि आज बैलगाड़ी के जगह अपना बोगी के जगह ट्रैक्टर ने अपनी जगह ले ली है। और हमारे कुछ बालकों के देशी खादी के कपड़ों के स्थान पर टेरीकॉट आ गया है। इस बदलाव को देखकर असमझदार फिर भी चतुर राजनीति कहते हैं कि मैं कुलक है और वह व्यक्ति किसान आंदोलन के हमदर्द व नेता नहीं बल्कि बड़े किसानों व कुलकों का नेता है। इस तरह से जगह-जगह चौपाल लगा कर किसानों में दरार डालते हैं। किसानों के एकता को तोड़ना चाहते हैं, ताकि किसान आगे आने वाले समय में उनका चुनौती देने के स्थिति में ना आ सके। सच्चाई ये है कि हममें से कोई बड़ा किसान है ही नहीं। बिहार और उत्तर प्रदेश के औसतन प्रति किसान अगर आँकड़ा लिया जाए तो 12 एकड़ से ज्यादा जमीन शायद ही किसान के पास होगा। इस तरह के किसान आंदोलन को बड़े किसानों का आंदोलन बताना एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारे ट्रैक्टर और बालकों के टेरीकॉट के कपड़े हमारे मजदूर के निशानी है। इनमें से शायद ही कोई ऐसा किसान होगा, जिसने अपनी खेती व पारिश्रमिक के मुनाफे से ट्रैक्टर खरीदा हो। हमारे ट्रैक्टर बैंक के कर्ज से लिए गए हैं और अपने काम के अलावे श्रम, मेहनत, मजदूरी करके हमलोग बड़ी मुश्किल से कर्ज की किस्त भरते हैं। रूखा-सूखा खाते हैं फिर भी कर्ज चुका नहीं पाते हैं। यही नहीं बैंक का कर्ज तथा शहर व गाँव के साहूकारों, दुकानदारों का उधार हम किसान पर कितना है। इस बात को गुलछर्रे उड़ाने वाले ये राजनैतिक दलबन्दी के खिलाड़ी नहीं जानते हैं और न जानना ही चाहते हैं। कुर्सी पाते हैं और फिर हमें भुल जाते हैं। इनके पास लम्बे-चौड़े वादे हैं। ●

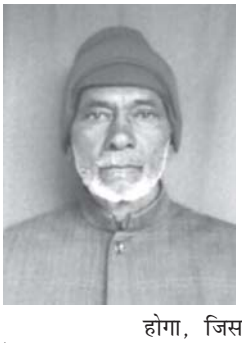

एकता में रामको परिवार बिहिया बिहार में

● बिन्ध्याचल सिंह

हां थी नपाता कर देब जा'' उपर्युक्त भोजपुरी कहावत को चरितार्थ करते हुये रामको में पदस्थापित कम्पनी के उच्च पदाधिकारी डब्लू0एम0 पंकज कुमार वरिष्ठ प्रबंधक श्री चन्द्रशेखर सिंह सहायक प्रबंधक श्री अमरेन्द्र कुमार 'बख्शी' सुपरवाइजर और सिक्युरिटी गार्ड रामको कम्पनी को सालाना करोडो रूपये की क्षति पहुँचाकर अपनी जेब भरने में लगे हुये है। जिसकी जानकारी मुख्य पदाधिकारी श्री नागेद्रम् की पहुँच की बाहर है। प्रिय पाठकगण आपको बताते चले कि जनवरी–2019 में रामको के प्रधान कार्यालय चेन्नई से कम्पनी के उच्च पदाधिकारी बिहिया में स्थित रामको में दस्तक दिये उसी समय यानि जनवरी–2019 में रामको कम्पनी से 15/पन्द्रह टन लोहे की चोरी हुई थी, उसी समय प्रधान कार्यालय के उच्च पदाधिकारी श्री नागेन्द्रम बाबु आये थे। नागेन्द्र की जानकारी को होते ही प्रतिनिधि उच्च पदाधिकारी से मिलने के लिये जाते रहे परन्तु गेट पर डियूटी दे रहे गार्ड हर बार बताया कि नागेन्द्रम साहब नही आये है जबकि श्री नागेन्द्रम रामको में उपस्थित थे। जैसा कि श्रमिको ने प्रतिनिधि को बताते रहे जब तीन बाद नागेन्द्रम बिहिया से चले गये तो गार्डो का सुपवाइजर बिटटू लाल ने प्रतिनिधि को बताया कि नागेन्द्रम साहब चले गये है। जब प्रतिनिधि ने बोले कि डब्लू0 एम0 से बात कराई तो सिक्यूरिटी सुपरवाजर बिटटू लाल ने बोले कि कम्पनी के एच0 आर0 बोले है कि केवल सच के पत्रकार को अन्दर नही आने देना है। आपलोगो को जानकार आश्चर्य होगा कि कम्पनी के गार्ड जो गेट पर डियूटी देते है केवल सच प्रतिनिधि को देखते ही गेट बन्द कर लेते है और गेट में बनी छेद से बात करते है। नागेन्द्रम के बारे में सूचना न देना। सिक्यूरिटी की 15 टन लोहे की चोरी में संलिप्ता जाहिर करता है। दुसरा– लोहे की चोरी की जानकारी जब प्रतिनिधि सुपरवाइजर से लेनी चाही तो एक सुपरवाजर ने अपने को कम्पनी मे न रहने की बात बताई और तीन दिन तक दुहराते रहा। दुसरा–सुपरवाइजर तीनो दिन कॉल ही नही रिसिव किया। जिससे 15 टन लोहे की चोरी में सुपरवाइजर की संलिप्तता का प्रमाण है। 'ऐसा चोरी करता कि खुद न जाने'' की मुहावरा को चरितार्थ करते हुये उच्च पदाधिकारी पंकज कुमार, चन्द्रशेखर सिंह और बख्शी साहब के द्वारा 15 टन की चोरी कोई नई नही है बल्कि रामको के इतिहास में चौथी सबसे बडी चोरी है जो चोरी होने का नाटक करते है। ये सब रामको के पदाधिकारियो के द्वारा घोटाला है। जैसे– सैकडो ट्क टुटा हुआ सिमेंट का चादर, जो कम्पनी परिसर में जमीन के अन्दर दबाया गया है। मशीनो में लगा घटिया समान/जो जॉच का विषय है।/रामको परिसर मे स्थित तालाब के पास से विद्युत मोटर, चार पहिया वाहन/जो कबाडी को औने–पौने दाम पर बेची गई है।/प्रत्यके माह श्रमिको को दी जाने वाली सुविधा। वैसे प्रधान कार्यालय द्वारा दी जाने वाली कोई भी सुविधा श्रमिको को नही दी जाती है। सुविधा नही दिये जाने की जानकारी एक श्रमिक ने प्रधान कार्यालय चेन्नई के उच्च पदाधिकारी नागेन्द्रम बाबु को दिया तो उस श्रमिक को तीन–चार दिन बादं कम्पनी से सदा के लिये पदाधिकारियो ने कार्य से निकाल दिया है जो जॉच का विषय है। जनहित में खर्च की जाने वाली राशि आधे से अधिक अपने पॉकेट में रख लेते हैं प्रत्यके माह श्रमिको के मजदुरी में 100–500/रू0 की गडबडी की जाती है।●

मुझे पैसों का लालच नहीं : मुखिया पूनम देवी

● मणिभूषण तिवारी

प्रखण्ड चरपोखरी के ग्राम पंचायत सियाडिह के मुखिया पूनम देवी ने एक प्रश्न के जवाब में बताई की मुझे सरकार से या पब्लिक से या किसी से भी मुझे पैसों की लालच नहीं। हमारे पंचायत के लोग खुशहाल हैं, ये ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सरकारी फंड में पैसा नहीं भी रहता है, तो भी हमारे पंचायत में विकास कार्य अपनी तीव्र गति से चलता रहता है और अब भी जारी है। मैं अपने घर से भी पैसे लगाकर पंचायत का कार्य करवाती रहती हूँ। आप बताइए और खुद ही देख लिजिए हमारे पंचायत के गाँवों में कैसा और किस तरह का कार्य किया जा रहा है। आप चाहें तो लेवर मिस्त्री और दुकानदार जहाँ से सीमेंट गिट्टी, बालू आता है, वहाँ भी पता कर सकते हैं। वर्षों से खाली पड़े लड़कियों के स्कूल के फिल्ड को मैंने मिट्टी भराई का कार्य करवाया, कन्या उच्च विद्यालय चरपोखरी में इसका पैसा जब मिलेगा तब मिलेगा, परन्तु मैंने ये कार्य करवाया, क्योंकि बच्चियों को इतने लम्बे अरसे से खेलने-कुदने में परेशानी हो रही थी। ये कार्य पंचम योजना से करवाया गया है। हमारे पंचायत के 04 नम्बर वार्ड एवं 07 नम्बर वार्ड में सभी कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है। वार्ड संख्या-02/13/14 में कार्य प्रगति पर है। वार्ड नं.-06 में भी कार्य प्रगति पर है। 07 और 11 में भी कार्य पूर्ण हो चुका है। आंगनबाड़ी केन्द्र 05 नं. वार्ड चरपोखरी में लगभग बनकर तैयार है। 12 नं. वार्ड में भी कार्य प्रगति पर है। सात निश्चय योजना के फंड में पैसा नहीं रहने के बावजूद भी कार्य करवा रहे हैं और ये देखकर विरोधियों के हौसले पस्त हैं। जनमानस के हित में कार्य करते हुए मुझे खुशी

है कि हमें ये मौका मिला, लोगों के सेवार्थ। ●

जहानाबाद लोकसभा का चुनावी समर

लोकतंत्र का महापर्व अर्थात लोकसभा चुनाव 2019 अब हमारी दहलीज पर है। लोकसभा का चुनाव सिर पर है और पिछले चार वर्षो से देश के गरीब जनता सपनों में ही जी रही है। आजकल इस महापर्व के दौरान एक आम नागरिक की भुमिका मेले में खड़े तमाशबीन की है। बड़ी पार्टिया अपने बड़े-बड़े तम्बु वाली दुकान लगाती है। हम-आप बड़ी दुकानों के बड़ी शमियाने निहारते है। अंदर घुस नही सकते, क्योंकि उतने पैसे नही हैं। छोटी-बड़ी पार्टिया जब चाहे जिससे हाथ मिलाती हैं। कल तक एक दुसरे का दुश्मन बता रही थीं, और आज उसे गले लगाती है। और हम आप घर बैठे कमेंटरी करते है, हमारी बाते कोई सुनता है नहीं। हमारी दु:ख-सुख, हमारी समस्या तथा इसका कैसे निवारण हो इन सभी को छोड़कर पार्टिया कुछ दूसरे ही सवालों का बाजा बजाती रहती हैं। हम अपना दर्द भूलकर उनकी धुन पर नाचने लगते है। कभी-कभी अपने कान ढ़ंक भी लेते है। और मेले के अंत में हमलोगों से पूछा जाता है कौन से दुकान सबसे अच्छी थी? और हम किसी बड़ी दुकान पर उंगली रख देते है। विजय उस दुकानदार की होती है, अर्थात उस पार्टि की होती है। और हम बेवजह अपने आप को शहंशाह सा महसूस करने लगते हैं। और फिर अगले दिन से जिंदगी बदस्तूर चलने लगती है। पैसे से सता, फिर सता से पैसा। क्या इसे बदला नही जा सकता? क्या पॉच साल में एक बार बटन दबाने के अलावा भी हम इस चुनाव में कुछ भूमिका नही निभा सकते? क्या इस चुनाव के मुद्दे, उम्मीदवार और निर्णय तय करने में हम कोई प्रभावी भूमिका अदा नही कर सकते? लोकसभा 2019 का चुनाव साधारण चुनाव नही होगा। लेकिन इस चुनावी मेले में इस देश के असली मुद्दों की परछाई भी नही दिखती। बहुत दिन बाद देशभर के किसान एक मंच पर आए है। सिर्फ अपने लिए नही, पूरे ग्रामीण भारत के भविष्य को बचाने के लिए। दूसरी तरफ देश भर के नौजवान अपने लिए शिक्षा और रोजगार मांग रहे है। साथ ही साथ वे देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देना चाहते है। किसानों और नौजावनों का इस लोकसभा चुनाव में निणार्यक भूमिका रहेगा। आज तक नेतागण विकास की बाते छोड़ कर हिदू-मुसलमान, मंदीर-मस्जिद, जात-पात और आरक्षण का मुददा उठाते रहे है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में लोक-लुभावने घोषणाएं की है। जो पहले से ही अपेक्षित थीं। केन्द्र सरकार को किसानों, नौकरीपेशा, मजदूर और महिलाओं के वोट पर नजर थी। और इनसभी की झोली में कुछ न कुछ डालने की कोशिश की। किसानों को आर्थिक मदद 6000 रूपये हर साल मिलेंगें दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को। नौकरीपेशा को कर छूट 500000 तक सालाना कमाई करने वालों को अब कर नहीं देना होगा। मजदूरो को पेंशन 3000 प्रति माह असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की उम्र में। तथा महिलाओं पर 29165 करोड़ विभिन्न योजनाओं के लिए महिला कल्याण मंत्रालय को मिला। इस अंतरिम बजट में 65 से 70 फीसदी आबादी को साधने की कोशिश की है। वही जन आकांक्षा रैली पटना के गॉधी मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गॉधी ने भी कई घोषणाएं किए। सत्ता आई तो पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। साथ ही साथ एलान किया कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही देश के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इन तमाम बातों पर प्रस्तुत है **विकास कुमार** एवं **संतोष मिश्रा** की चुनावी रिपोर्ट :-

लोकसभा 2019 का महार्पव की धमक आप महसुस कर रहे है। चुनावी समर में कौन होंगें उम्मीदवार यह लोंगों में चाय की दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर चर्चा का विषय हो गया है। इस बार जहानाबाद से किसकी भाग जगती है यह तो आने वाला एक दो महिने में साफ हो जायेगा। एनडीए,यूपीए तो आमने-सामने होंगे ही इस महासागर में। लेकिन इन सब के बीच अब बहस का विषय यह भी बन गया है कि वर्तमान सांसद डॉ अरूण कुमार महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे की एनडीए से यह लोगो में सवाल बना हुआ? जहानाबाद में मुख्य मुकाबला दो जातियो के बीच होता रहा है। क्योकि भूमिहार बहुल सीट माना जाता है। और राजनितिक दल भी यहॉ से भूमिहार उम्मीदवार को ही तरहीज दे रहे है। क्षेत्र में इन दिनों चर्चा बहुत जोर शोर से है कि जहानाबाद सिट जदयू के खाते में चला गया और कई नाम सामने आ रहा है। भुमिहार से रामजतन सिन्हा, और उद्योगपति नरेंद्र कुमार दावा कर रहे

है। नरेन्द्र कुमार सिंह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और समाज सेवी भी है। वही शिक्षा मंत्री कृष्णनन्दन वर्मा भी पीछे नही है। वही यूपीए से भी इस हॉट सीट पर कई दावेदार है। पूर्व सांसद सुरेन्द्र प्रसाद यादव तथा पूर्व सांसद रामाश्रय प्रसाद यादव के पुत्र के अलावे हम पार्टी से राहुल शर्मा, अनिल कुमार, और रालोसपा से नागमणी दावा ठोक रहे है। वही वर्तमान सांसद अभी अपना पता नही खोले है कि वे यूपीए से लड़ेगे की एनडीए से या लोकसभा जहानाबाद के बजाये किसी और क्षेत्र से। क्योकि जहानाबाद क्षेत्र की जनता में इनके प्रति रोष ज्यादा देखा जा रहा है। सांसद महोदय के कार्य से जनता में अविश्वास हो गया है। क्योकि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में विकास कोसो दूर है। सांसद निधि से गॉवो में ट्रांसफर्मर तो एमपी साहब दे दिए लेकिन लगभग गॉव में शोभा की बस्तु ही बन कर रह गया है। इनके द्वारा पीसीसी कार्य भी संतोष जनक नही दिखाई दे रहा है। किसी भी क्षेत्र में सांसद महोदय जनता का दिल जित नही पाये। सांसद महोदय कही भी दावा से नही कहने की स्थिति में है कि मेरे

कारण इस गॉव में कार्य हुआ। दो-तीन वर्षो तक तो सांसद महोदय यह भी कहते नही थकते थे कि उन्हें मोदी लहर में वोट मिला है। लेकिन जब जनता हिसाब पूछ रही है तब एमपी साहब कुछ कहने की स्थिति में दिखाई नही दे रहे है। ऐसे तो जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में मुलभुत बहुत सारी समस्या है जिस पे अब बात करने से भी कोई भायदा नही होने बाला है।

कांग्रेस राज्यसभा सांसद डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह जो लोकसभा चुनाव 2019 में अहम भुमिका निभाने बाले है। उनसे बात किया तो उनका दावा है कि जहानाबाद सिट एक हॉट सिट है और इस सिट से महागठबंधन की हि जीत होगी। क्योकि बिहार में कांग्रेस बहुत तेजी से अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ इस बार कांग्रेस बड़ी भुमिका में नजर आयेगी। तथा केन्द्र में राहुल गॉधी की सरकार होगी और मोदीजी को जाना तय है। छतीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान के हालिया नतीजों से कांग्रेस को पैर जमाने की जगह मिल गई है। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रति जनता में रूझान बढ़ गया है। बीजेपी नेता अजेन्द्र शर्मा का कहना है कि देखिए जहॉ तक बात जहानाबाद की है तो यहॉ से हर हाल में बीजेपी को अपना उम्मिदवार उतारना चाहीए। जहानाबाद की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता चाहते है कि यहॉ से बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करे। अगर बीजेपी अपना उम्मीदावार खड़ा करती है तो हर हाल में वह उम्मीदवार जीतेगा। साथ ही साथ जहानाबाद के कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ेगा। इसलिए जहानाबाद लोकसभा सिट बीजेपी के खाते में होना चाहीए। यहॉ से बीजेपी के उम्मीदवार ही अपना किस्मत आजमाऐ। अजेन्द्र शर्मा का दावा है कि यहॉ के कार्यकर्ता तथा इस क्षेत्र के जनता से बात करने के बाद मै कह रहा हुँ की जहानाबाद लोसभा से बीजेपी को ही टिकट मिलना चाहीए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश महासचिव पप्पु वर्मा का कहना है की महागठबंधन से यह सिट राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जायेगा तथा रालोसपा का जीत सुनिश्चीत है।

जहानाबाद के जनता का मानना है की पुर्व विधायक राहुल शर्मा को टिकट मिली तो जीत पक्की है। राहुल शर्मा पुर्व सांसद डॉ जगदीश शर्मा के पुत्र हैं। डॉ जगदीश शर्मा जहानाबाद के राजनीति के पितामह माने जाते है। राहुल शर्म पुर्व में घोषी से विधायक रह चुके है। जहानाबाद की राजनीति में राहुल शर्मा को महागठबंधन से टिक्ट मिलने पर बड़े सियासी समीकरण बन और बिगाड़ सकती है। साथ ही एनडीए के लिए भी बड़ी चुनौती होंगी। राजद में भले ही सुरेन्द्र यादव का सिटींग सिट होने की

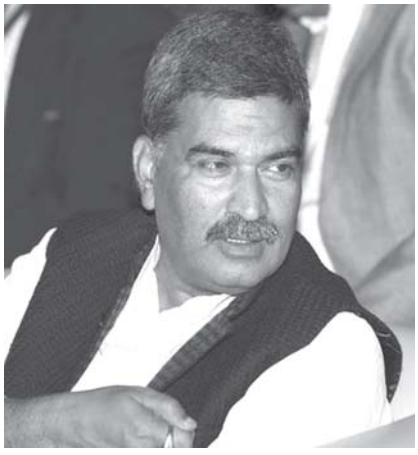

बात कही जा रही है लेकिन राहुल शर्मा को मिलने से एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। राहुल शर्मा एक युवा नेता है तथा राजनीति युवाओं के बिना संभव नही होती है। इनका देश व समाज के प्रति सच्ची निष्ठा युवाओं को प्रेरित करती है। फेसबुक के माध्यम से राहुल शर्मा को लोकसभा चुनाव लड़ने की बात लंबे समय से हो रही है। इसकी वजह भी है। ये घोषी विधानसभा से विधायक रह चुके है। तथा इनके पिताजी डॉ जगदीश शर्मा लंबे समय तक घोषी से विधायक और जहानाबाद से सांसद रह चुके है। साथ ही साथ अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य भी किये है। शर्मा अपने क्षेत्र में परिवार से जुड़े लोगो के लगातार संपर्क में रहे है। इलाके में परिवार हो, जनता हो या फिर नव युवक हो सभी से उनका संवाद का अलग अंदाज रहता है। जहानाबाद की बुजुर्ग हों, या आम ग्रामीण, सभी में वे सर्वमान नेता के रूप में स्थापित रहे है। राहुल शर्मा को उनके पिताजी के छवि को देखते हुऐ टिक्ट मिलने की संभावना दिख रही है। जहानाबाद लोकसभा चुनाव हर बार की तरह इस बार भी दिलचस्प दिख रहा है। प्रो0 राम जतन सिन्हा को जदयू के सदस्य बनने से यह साफ होता है कि जदयू से प्रो0 राम जतन सिन्हा को टिक्ट मिलने की संभावना बन रही है। लोकसभा चुनाव के पहले राम जतन सिन्हा का जदयू में शामिल होना अहम माना जा रहा है। भूमिहार जाति से आने वाले राम जतन सिन्हा का जदयू में शामिल होना नए सियासी समीकरण गढ़ सकता है। यदी प्रो0 राम जतन सिन्हा और डॉ अरूण कुमार इस चुनाव में आमने-सामने होंगे तो कुछ नेता निर्दलीय भाग्य आजमाने की कोशिश करेगें। ●

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से बदलेगी गांव की तस्वीर : श्रवण

बिहार के विकास के लिये संकल्पित बिहार के विकास पुरूश नीतिश कुमार सुबे के प्रत्येक जिलों में विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिये दृढ़संकल्पित है। बिहारवासियों को न्याय के साथ विकास मिले इसके लिये सभी वर्ग, समुदाय, के लिये योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से बिहार के गॉवों की तस्वीर बदल जायेगी। गॉव के लोग भी स्मार्ट हो जायेगें। शहरों जैसी सुविधा गॉव में उपलब्ध हो जायेगी। उक्त बातें बिहार विधान मंडल के सदस्य सह संसदीय कार्य मंत्री नालंदा के विधायक एवं बिहार के चर्चित ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र परिभ्रमण के दौरान महावीर की धरती कुंडलपुर के प्रांगण में आयोजित अपने दिनचर्या में शामिल जनता दरबार में भेंटवार्ता के दौरान कही। श्रवण कुमार नालंदा विधानसभा से लंबे अर्से से प्रतिनिधित्व कर रहे है। तथा बिहार के मुखिया नीतिश कुमार के विश्वसनीय पात्रों में एक है। पार्टी एवं बिहारवासियों के प्रति समर्पण की भावना ने इन्हें आमलोगों का मुरीद बना दिया है। अपने मृदुभाशी विचार एवं कुशल व्यवहार से लोगों का दिल जीतने वाले श्रवण कुमार के क्षेत्र में महागठबंधन की कोई औकात नही कि श्रवण कुमार को किसी भी परस्थिति में पटखनी दे सके। वैसे तो नालंदा विधानसभा क्षेत्र इनके प्राथमिकता सूचि में तो है ही परन्तु इन्होनें अपने विभाग के माध्यम से पुरे बिहार में ग्रामीणों के विकास के लिये कोई कोर कसर नही छोड़ा है। अगामी लोकसभा चुनाव और बिहार में एनडीए गठबंधन के कार्यकाल की उपलब्धियों पर लंबी बातचीत का दौर चला। बिहारवासियों के सपनें को साकार करने के लिये संकल्पित श्रवण कुमार से कई बिंदुओं पर बातचीत करते हुये पत्रिका के ब्यूरो चीफ **ललन कुमार** एवं **मिथिलेश कुमार** के साथ प्रतिनिधि **मनीष कमलीया** के बीच वार्तालाप के प्रमुख अंशः–

★ केवल सच पत्रिका परिवार की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनायें।

आपकों भी ,नया वर्ष केवल सच के लिये उन्नति का हो प्रगति का हो, नये साल में केवल सच गॉव के गरीब और बेबस लोगों की आवाज बन कर काम करे। हमारी शुभकामनायें केवल सच के साथ है।

★ आप लंबे अर्से से नालंदा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तथा आपको क्षेत्र के लोगों का प्यार भी मिलता रहा है। सरकार की खास उपलब्यिों के बारे में कुछ बतायें।

देखिये सरकार की उपलब्धि बहुत है विस्तारपूर्वक बताने में कई घंटे लगेंगें। खास कर मेरा जो विभाग है उसके साथ पंचायती राज विभाग में जो कार्य हो रहा है। ग्रामीण विकास पर ग्रामीणों का काफी भरोसा है अभी जो गरीब लोग समझते है कि ग्रामीण विकास के जरिये ही गॉव की तरक्की हो रही है जिन्हें रहने के लिये आवास नही है जिन्हे प्रधानमंत्री आवास के जरिये उन्हे आवास मुहैया करायी जा रही है। एक लाख बीस हजार रूपया एवं शौचालय निर्माण के लिये 12 हजार तथा जो मनरेगा के मजदुर है उन्हें 177 रूपयें के हिसाव से उन्हें कार्यो की मजदूरी भी मिलता है, मिलाजुला कर 1 लाख 75 हजार के अलावे मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब आवास के लिये बैंक से भी लोन ले सकते है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री का दुसरा महत्वपूर्ण कार्य 1 जनवरी 1996 के पहले जिनके घर बने है और जीणर्शीण अवस्था में है वैसे लोगों को भी जो दलित समाज एवं अतिपिछड़े है वैसे लोगों को 1लाख 20 हजार रूपये देने के लिये जा रहे है जो अपने मकान को पुनःबना सके।

★ आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो दे रहें है परन्तु जिनके पास जमीन नही है, बिल्कुल भूमिहीन है, उनके लिये आपकी सरकार क्या कर रही है?

आपने सही सवाल किया है। वास्तव में बिहार में कई गरीब परिवार ऐसे है जिनके पास घर बनाने के लिये जमीन नही

है। नितिश कुमार ने एक योजना चलायी है जिन्हे जमीन नही है उन्हें जमीन के लिये 60 हजार रूपये मिलेगें तथा उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें मकान बनाने के लिये राशि आवंटित की जायेगी। बिहार में जितने भी गरीब है उन्हें आने वाले दिनों में चिन्हित कर उन्हें सरकारी सुविधा दी जायेगी। तथा उसके लिये जिनका नामजातीय आधारित जनगणना के अनुसार आवास योजना की सूचि मे ंनाम नही है उन्हें आवास नही मिलेगा। वैसे परिवारों को भी चिन्हित कर केन्द्र सरकार के यहॉ सूचि भेजने का कार्य किया जा रहा है वैसे करीब दो लाख परिवार राज्य में है जिनकी सूचि बना कर केन्द्र सरकार को भेजी जायेगी।

★ बिहार में मनरेगा योजना किस रूप में कार्य कर रही है यह मजदूरों के लिये सफल है या असफल?

देखिये मनरेगा योजना केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है इसमें रोजगार की गारंटी दी गयी है। यह योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा योजना जो मजदूर चाहे साल में जितने दिने चाहे कार्य मिलता रहे। इसके लिये व्यापक रूप से कार्य किया जा रहा है। खेल मैदान जहॉ– जहॉ है वहॉ मिनी स्टेडियम के तौर पर बनायेगे। सरकारी विधालय प्राइमरी या मध्यविधालय जहॉ है,विधालय परिसर में मिट्टी भराई का कार्य भी किया जायेगा। या वैसे सरकारी जमीन उपलब्ध है जैसे ग्रामीण क्षेत्र में चेक डैम का निर्माण, जलसंचय योजना, को राष्ट्रीय योजना के तहत कार्य करेगें। पुरे देश में भारत सरकार ने लागू किया है किसान के लिये पईन की उड़ाही करा देगें। यानि की उनके खेतों में पानी के ले जाने की व्यवस्था की जायगी। किसान पशुपालकों के लिये गौशाला बनाने के लिये भी योजना बनाई गयी है जो मुर्गी पालन करना चाहते है उन्हे मुर्गी पालन, बकरीपालन के साथ साथ सूअर पालन तथा ग्रामीण क्षेत्रों कच्ची सड़क का निर्माण आदि कई कार्य इसके तहत किये जाने है प्रधानमंत्री आवास का लाभुक है उसका जमीन गढ़ा है उसकों भरने के लिये भी मनरेगा के माध्यम से व्यवस्था की गयी है। पौधारोपन की भी व्यवस्था की गयी है 50 लाख पौधे लगाने की योजना है। इसे भी पुरा किया जायगा। सरकार इच्छुक व्यक्ति को पौधा लगाने की सारी व्यवस्था की जायेगी।

★ केन्द्र सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण कार्य की क्या स्थिति है?

देखिये शौचालय योजना के लिये गरीबी रेखा में नाम नही है उसे केन्द्र सरकार पैसा नही देती है हम एपीएल परिवार को भी राज्य के खजाने से पैशा दे रहे है। एक करोड़ उनसठ लाख परिवारों को लाभ मिला है 67 प्रतिशत शौचालय का निर्माण हो चुका है। महात्मा गॉधी के जन्म दिन के पूर्व सभी कार्य पुरा कर लिया जायेगा। यह कार्य में व्यवहार परिवर्तन की भी बात चल रही है गर्वनेस की बात हो रही है समाज का हर तबका को इसमें सहयोग करने की जरूरत है।जैसे मान लिजिये किसी गॉव मे ं200 घर है जिसमें करीब 25 परिवारो ंके पास शौचालय की जमीन नही है हमलोग उसके लिये कलस्टर पर निर्माण कराने की व्यवस्था कर रहें है। 25 शौचालय बना कर सभी परिवारों को ताला लगा कर चाभी सौप दी जायेगी।

★ गॉव में देखा जा रहा है कि सरकारी व्यवस्था के बावजूद गॉव की गलियों में सफाई नही रहती है तथा लोग पेयजल एवं बिजली का दुरूप्योग करते है?

देखिये इसके लिये जन जागरूकता का अभाव है ग्रामीण स्तर पर बुद्विजीवीयों को इसके लिये सोचने एवं सरकार को सहयोग करने की जरूरत है। हमलोग इसके लिये भी कार्य कर रहे हैं।कचरा प्रबंधन के लिये गॉव में कचरे को कई केटोगरी में बॉट उसकी व्यवस्था की जायेगी।

★ महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये आपकी सरकार क्या कर रही है?

बिहार में महिलाओं के लिये माननीय मुख्यमंत्री श्री नितीश कमार जी ने कई योजनाएं चला रखी है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं कों जिवीका के माध्यम से गॉव की महिलायें जो गरीब है स्वयं सहायता समूह से आठ लाख से ज्यादा स्वय सहायता समूह बना हुआ है जिसमें करोड़ो महिलाओं को इससे जोड़ा गया है आज गॉव में चटाई बनाने,डेली बनाने जैसे कार्य जो लुप्त हो रही थी उसके लिये भी व्यवस्था कराई जा रही है। इन सबों कार्यो सहित कई परम्रागत कार्यो को इससे जोड़ा जायेगा। आज जहॉ भी प्रर्दशनी लगाया जाता है गॉव का आदमी प्रर्दशनी में अपना सामान बेच रहा है। दुनिया के मार्केट चीन के उत्पादन को रोकने के लिये सकल घरेलु उत्पाद को बढ़ाबा दे रहे है ताकि हमारा राज्य समृद्व हो गॉव के लोग समृद्व हो। उसके लिये भी व्यवस्था की जा रही है। गॉव में जो गरीब कोलसार के माध्यम से भुंजा भुंजने का कार्य कर रहे उसके लिये खेतो में खरपतबार चुनकर शाम में भुंजा भुंजता है। वैसे व्यक्ति को भी बैंक से सहायता दिला कर कार्य कराने की योजना है। जैसे सतू बनाने का कार्य जो किया जा रहा है सतू को बढ़िया से पैकेजींग कर बाजारों में बेचा गया तो आज काफी प्रचलित हो गया है। छोटे छोटे लधु उघोग के माध्यम से कार्य कराने की योजना है। जो पैसा् लोन बैंक से लिया जाता है। बड़े बड़े लोग जो इंडस्ट्रीज से पैसा लेते है वह जल्दी नही भुगतान करते है। लेकिन बिहार में आज भी किसान बैंक से लोन लेने के बाद कम दिनों में इसका भुगतान कर देते है। महिलाओं के लिये हमारी सरकार नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया है। तथा महिलाओं के लिये कई कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

★ आप एक दशक से ज्यादा सरकार में है। क्या आपकों लगता है कि बिहार में वर्तमान परिवेश में जो विकास कार्य हो रहा है, नाकाफी नही है?

देखिये बिहार का पशुपालन विभाग द्वारा फ्री में मुर्गी के बच्चे को बॉटा जाता है। सतत जीवीकोपार्जन योजना है जो लोग ताड़ी और दारू बेचने वाले थे उनके जीवीकोंपार्जन के लिये एक लाख का लोन मुहैया उनके इच्छा के अनुसार उन्हें वाहन के लिये दुकान खोलने के लिये कई योजनायें पर कार्य किया जा रहा है। इस तरह का कार्य पुरे बिहार में हो रहा हैं दुसरा कार्य सात निश्चय में शौचालय योजना तीन निश्चय गॉव के लिये गॉव के गलियों के लिये हर घर में बिजली और पानी की व्यवस्था कराना है। गॉव के सभी परिवारों के बीच कार्य करना है। गॉव में प्रदूषण मुक्त पानी पिलाना है इसके लिये सरकार कार्य कर रही है। पचास लाख से पौधा से कार्य नही चलेगा। इसके लिये हरियाली क्षेत्र को बढ़ाने के लिये कार्य करना जरूरी है वायु प्रदुषण को रोकने के लिये हमलोगों ने अपील किया है हर व्यक्ति एक पॉधा लगायी जाय। खेतों में जो पराली जला रहे है इससे खेतों के बैक्टरिया खत्म होता है तथा पौधा पर भी प्रभाव पड़ रहा है। मकई गेहूँ, चना आदि कई फसलों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिये पर्यावरण को संतुलित करने के लिये पौधा लगाना जरूरी हैं सात निश्चय के जरिये बेहतर बनाया जा रहा है गॉव के लोगो ंको इसके लिये भी बदलना पड़ेगा। गॉव में नल का जल को बचाने के लिये गॉव

में प्रगतिशील लोग को उन्हे नल जल की योजना से पानी एवं विजली को बचाने का कार्य करना पड़ेगा। गॉव में कम्यूनिटी बनाकर जागरूकता लाना होगा। लोगों को भी अपना सोच बदलने की जरूरत है। अपव्यता को रोककर व्यवस्था मे सुधार किया जा सकता है।

☆ गरीब परिवार के बच्चों के शिक्षा के लिये आपकी क्या योजना है?

बच्चों की पढाई के लिये चार लाख रूपये की बैंक गारंटी दिया गया। शिक्षा वितनिगम बनाया गया। छात्रों को उच्चशिक्षा के लिये स्टुडेंड क्रेडिट कार्ड के तहत चार लाख का लोन देने के व्यवस्था की गयी है। साथ ही साथ छात्रवृति, पोशाक राशि, पुस्तक के लिये राशि, साइकिल के लिये राशि सहित कई प्रकार के लाभ छात्रों को दिया जा रहा है। यहॉ हमारी सरकार महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया हैं लड़की के पैदा होते ही दो हजार रूपया उसके खाते में दिया जाता है। मैटीक में दस हजार अगर ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसे पच्चीस हजार रूपया दिया जाता है। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ कई कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना क्या है। क्या इससे गरीबों का कल्याण होगा?

पंचायत स्तर पर अनुसूचित जातियों एवं पिछडे लोगो के लिये वाहन की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक पंचायत में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत यातायात को सुगम बनाने एवं बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिये यह योजना चलाई जा रही हैं इससे जुड़कर लोग सरकार से लाभ ले रहे है। इतना ही नही हमारी सरकार जो व्यक्ति लधु उघोग लगाना चाहता है उसके लिये दस लाख की लोन की व्यवस्था की गयी है। उसमें पॉच लाख रूप्या सब्सीडी दिया जा रहा है। सरकार बेहतर कार्य कर रही है।

☆ किसानों के लिये आपकी सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। देश के दो कॉग्रेंस की सरकारों ने शासन संभालते ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। क्या बिहार में भी इस प्रकार की कोई नीति अपनाये जाने की संभावना है?

देखिये बिहार में किसानों के लिये 97 तरह के कार्य किये जा रहे है। फसल क्षति पूर्ति के लिये लाभ दिया जा रहा हैं देश का पहला राज्य बिहार है जहॉ इस तरह का लाभ दिया जा रहा हैं बिहार का कोई ऐसा व्यक्ति नही है जिसे सरकारी योजना का लाभ नही मिल रहा हैं किसी न किसी रूप से सरकारी लाभ सभी परिवारों को मिल रहा है। परन्तु आज भी कई लोग ऐसे है जो कहेगें कि सरकारी लाभ नही मिल रहा हैं इसके लिये विचार की परिवर्तन करना चाहिये। सरकारी लाभ जो प्राप्त कर रहे है। हम किसानों को कर्जा माफ करने के लिये नही हम उसके आय में वृद्वि के लिये ठोस योजना पर कार्य कर रहे है। कृषि विभाग के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम सिर्फ किसानों के लिये किये जा रहे है। देश का पहला राज्य बिहार है जहॉ किसानो को पटवन के लिये सब्सीडी दी जा रही है। साथ ही साथ कई प्रकार की योजना किसानों के लिये चलायी गयी है।

☆ बिहार में अपराध एवं भ्रष्टाचार में इजाफा हुआ है। आपकी सरकार न्याय के साथ विकास एवं अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, पर हो रहा कुछ और है।

भ्रष्टाचार के मामले में पूरे राज्य में कार्य चल रहा हैं बिहार सरकार लगी हुई है सरकार ने कानून बनाया है निगरानी के द्वारा कार्य किया जा रहा हैं। घुसखोर जेल भेजे जा रहे है। अपराध में इजाफा नही हुआ है । लेकिन जो घटनायें घटी है इसकी जितनी भी निंदा की जाय कम है। सरकार अपराध पर लगाम लगाने के लिये कटिबद्व है। जहॉ तक भ्रष्टाचार की बात है आपही बताईये ईमानदार होने की कोई दवा बनी है। अगर कोई दवा बनी होती तो इसकों सारे कर्मियों को खिला दिया जाता। घुस लेने की बीमारी ज्यादा चाहत रखने वाले लोगों को होती है। लेकिन भुगतना भी उसे ही पड़ता है। देखिये लोक शिकायत निवारण कानून के मामले में बिहार इकलौता राज्य है जहॉ 60 दिनों के अंदर मामले का निस्पादन किया जा रहा है। लेकिन अपराधिक मामले जमीन से संबधित भी मामले आ रहे है। हमारे मुख्यमंत्री का सपना है अपराधमुक्त बिहार अपराधी मुक्त बिहार बनाने की इसके लिये कार्य किये जा रहे हैं।

☆ तीन राज्यों में भाजपा की करारी हार हुई है नयी सरकार ने गठन होने के बाद ही सरकार ने किसानो का कर्जा माफ कर दिया है। क्या बिहार में भी इस प्रकार की योजना है?

देखिये राजस्थान एवं मध्यप्रदेश में कॉग्रेंस की सरकार बहुमत में नही है अजेय नही है। छतीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश की सरकार की स्थिति भी ठीक नही है। किसानों का कर्जा माफ करने से कुछ नही हो सकता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने पर उपाय कर रहे है। किसानों को कर्जा लेने की नौबत नही आयें । हमलोग किसानों के हितों के लिये सब्सीडी दे रहे है इससे किसानों को बहुत फायदा नही मिल रहा है परन्तु किसानों के मायूस चेहरों पर मुस्कान लाने के लिये ही कई प्रकार की योजनायें चलायी जा रही हैं किसान को सम्मान देने के लिये किसान सम्मान योजना, किसान श्री योजना सहित कई तरह के योजनाओं पर विचार कर रही है। सरकार कृषि के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रही है।

☆ रालोसपा के एनडीए से अलग होने पर अगामी चुनाव में क्या असर हो सकता है। आप बतायें।

गॉव में कहावत है बेटी जाती है पुतोहु आती है बात बराबर है। नेता को इधर से उधर जाने से कुछ नही होगा। जनता फैसला करेगी। जनता जिसके पक्ष में जायेगी। जनादेश उसी को मिलेगा। बिहार की जनता को गुमराह करने वाले स्वंय हासियें पर आ गये है। चुनाव में एनडीए और मजबूती से लौटेगा।

☆ केवल सच के माध्यम से बिहारवासियों को क्या संदेश देना चाहते है।

देखिये आपकी पत्रिका के माध्यम से हम बिहारवासियों को पुनः नववर्ष की शुभकामना देते हुये कहना चाहेगें। बिहार विकास के रास्ते पर चल पड़ा है बिहार के विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री श्री नितिश कुमार ने बिहार के गॉवों की तस्वीर बदलने की ठानी हैं ग्रामीणों को उनका हक और सम्मान दिलाने की बात पर ही सात निश्चय योजना को पुरे बिहार में लागू किया गया है। बिहारवासी इसमें सहयोग करें। साथ ही साथ शराबबंदी कानून, दहेज प्रथा, एवं बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरितियों के खिलाफ गोलबंद होकर सरकार के द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों को जनजनतक पहुॅचायें एवं बिहार की गंगाजमुनी सभ्यता एवं अपनी परम्परा को कायम रखें । ताकि बिहार देश ही पुरे विश्व के मानचित्र पर अपनी अमिट छाप छोंड़े। आने वाले चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री के हाथों को मजबुत करने के लिये उन्हें सहयोग करें। केवल सच समाज की आवाज बनती रहे।

बड़े-बड़े बोल्डर बिछाकर छोड़ दिया सड़क मार्ग पर चलना हो रहा दुभर

● अरबिन्द मिश्रा

सरकार ग्रामीणो की यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के उदेश्य से लाखों रूपये पानी की तरह बहा रही है, वावजूद विभागीय अधिकारियो व अभिकर्ता के उदासीनता के कारण ग्रामीणो के सपने का पंख नही लग पा रहा है। विवशता वश ग्रामीण सड़क मार्ग मे बिछे बड़े बड़े बोल्डर पर गुजर कर अपनी मंजिल तय कर रहे है। सड़क का निर्माण का कार्य अधूरा पडा रह गया, एक वर्ष गुजर गये,लेकिन सड़क का निर्माण कार्य पूरा नही हो पाया। अभिकर्ता के माध्यम से रास्ते में बड़े बडे बोल्डर बिछा कर छोड़ दिया गया। जिससे आवागमन की समस्या बनी हुई है।

☞ ग्रामीणो की समस्या के समाधान के लिए विभागीय अधिकारी को अवगत कराया जायेगा। ताकि ग्रामीणो को आवगमन की सुविधा बहाल किया जा सकें।

राजीव रंजन, बीडीओ

★ क्या कहते है ग्रामीण एवं अधिकारी :–

☞ यह सड़क का निर्माण कार्य सालभर पहले शुरू हुआ था, तब ग्रामीणो की आस जगी थी,अब गांववाले पक्की सड़क होकर गुजरेगे,रास्ते मे बड़े बड़े बोल्डर बिछाकर छोड दिया गया है,ग्रामीणो के लिए आवागमन के लिए मुसीबत बनी हुई है। कोई भी सुध लेने को तैयार नही है। गाव मे पीसीसी किया गया है,लेकिन गाव आने बाली मार्ग जहो से भुरू हुई है,और गांव के पीछे मार्ग में बोल्डर बिछाकर अभिकर्ता गायब हो गये है।

प्रदीप मालाकार, सुल्तानपुर

☞ तकरीबन दो किलोमीटर सड़क का निर्माण होना था,रास्ते बिछा हुआ बडे बडे पत्थर खतरनाक बना हुआ है। वाहन तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। अधिकारी चाहेगे तो ग्रामीणो के आवागमन की सुविधा वहाल कर देगे।

राजेन्द्र चौहान, सुल्तानपुर

☞ विभागीय अधिकारियो के अनदेखी के कारण सड़क का निर्माण कार्य अधूरा पडा हुआ है। सड़क का निर्माण कार्य की अवधि भी पूरा हो गया,लेकिन सडक का हाल बदहाल बनकर रह गया है। कोई भी देखनहार नही है।

मुन्ना मालाकार, सुंल्तानपुर

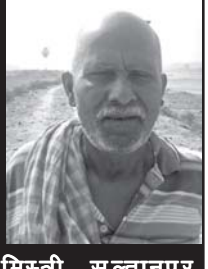

☞ सरकार लाखो रूपये पानी की तरह बहा दिया,लेकिन हमसब के गांव की सडक का कालीकरण नही हो पाया है,रास्ते मे बिछा हुआ पत्थर ग्रामीणो के लिए आवागमन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इसके लिए अधिकारी के साथ अभिकर्ता भी जिम्मेवार है। अगर डीएम साहब चाहेगे,तो सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा। तब ग्रामीणो के आने जाने की परेशानी से निजात मिल जायेगी।

राजकुमार मिस्त्री, सुल्तानपुर

स्थिति यह है कि संविदा की कार्य अवधि भी 3 माह 15 दिन पहले ही पूरी हो गयी, लेकिन सड़क मार्ग का कालीकरण नही हो पाया है। ग्रामीणो का कहना है कि अभिकर्ता सड़क का निर्माण का कार्य पूरा किये बिना ही गदहे की सिंग की तरह गायब हो गये,और सड़क का हाल जानने के लिए भी नही पहुंचें है । यहां चर्चा हो रही है नारदीगंज प्रखंड के इचुआकरणा पचायत की सुल्तानपुर गांव जाने बाली मार्ग की। यह सड़क मार्ग सैदपुर जाने बाली सड़क मार्ग से जुडा हुआ है । ढाढर नदी के किनारे से तकरीबन देा किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है । इस सम्पर्क पथ का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा किया जा रहा है । योजना के अनुसार पथ की लम्बाई 1 दशवल 750 किलोमीटर है। इस पथ का प्राक्कलित राशि 87 दशवल 989 लाख है। सड़क का निर्माण कार्य 3 नवम्बर 2017 से प्रारंभ हुई,और 19 अक्टुबर 2018 तक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाना था। लेकिन संविदा की अवधि पूरा होने के

☞ बदहाल सड़क मार्ग ग्रामीणो के आवागमन मे बाधा बनी हुई है। विभागीय अधिकारी व अभिकर्ता के अनदेखी के कारण सरकार की योजना धरातल पर उतर नही पा रहा है । जो काफी खेद का विषय है।

अजय सिंह, रजौर

☞ विभागीय अधिकारी व अभिकर्ता इस पथ के लिए जिम्मेवार हैं, कही सड़क का निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, तो कही लोग सड़क के लिए टकटकी लगाये हुए हैं।

अरबिन्द मिश्र, समाजसेवी

बाद भी मार्ग अधूरा ही रह गया। रास्ते मे बडे बड़े बोल्डर दुर्धटना का संकेत दे रही है। इस पथ के निर्माण के लिए विभाग ने संवेदक श्री सीता राम कंन्स्ट्रशन कंकडबाग,पटना को जिम्मेवारी सौंपी थी,वही कार्यकारी एजेन्सी के रूप में कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास कार्य प्रमडल,नवादा,ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संपोशित था। विभागीय अधिकारियो के अनदेखी के कारण यह स्थिति बनी हुई है। इस मार्ग के निर्माण होने से सुल्तानपुर गांव के ग्रामीणो के अलावे कई गाव के ग्रामीणो के लिए आवागमन की सुविधा वहाल होती। यह सम्पर्क पथ की तस्वीर ही व्यां कर रही है कि ग्रामीण उस बदहाल सड़क मार्ग से कैसे गुजरते होगे? कल्पना कीजीए, दिन मे तो लोग किसी तरह गुजर जाते होगे,लेकिन अंधेरी रात में उस रास्ते से सफर करना सीधा आफत मोल लेना साबित होता होगा ? स्थिति यह है कि सबकूछ भगवान भरोसे छोड़कर ग्रामीण अपनी दिनचर्चा को निपटना उनके लिए नियति बनी हुई है। अब ग्रामीणो के लिए अहिल्या की तरह उंद्वार करने के लिए किसी राम का इंतजार है। ●

पीड़िता परिवार को बचाने के लिए समाज हो रहा एकजुट

● **सुमित राज यादव**

बीते दिनो भाजयुमो जिलाध्यक्ष अमित सिन्हा और जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो गुड्डू सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पदस्थापित एक पुलिस कर्मी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए निर्दोष व्यक्ति को फंसाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक गलगलिया निवासी कृष्णदेव महतो के पुत्र की शादी जिले के सदर थाना में ही पदस्थापित दरोगा की बेटी से हुई थी। लेकिन विवाह के दो साल बाद ही अज्ञात कारणों से लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। जिसके बाद दरोगा ने पहले तो समधी और समधन तथा उसके बेटी को फंसाने की कोशिश की। लेकिन, क्योंकि मामला दिल्ली पुलिस के अधीन था। तो उनकी दाल वहां नहीं गली। तो मामला यहाँ पर शांत नहीं हुए और अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने समधी कृष्णदेव महतो के ऊपर थाना कांड संख्या-577/18 दर्ज करवा दिया और परिजनों के मुताबिक ना सिर्फ मामला दर्ज करवाया। बल्कि, अपने पुत्री के मामले को आड़ में लेकर थाना बुलवा कर गिरफ्तार भी करवा दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ अत्यधिक नाराजगी देखी जा रही है। भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष स्थानीय निवासी सह समाजसेवी गुड्डू सिंह ने बताया कि पुलिस की वर्दी होने के नाते एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से मुकदमें में फंसा कर जेल भेज दिया गया। श्री सिंह का कहना है कि पुलिस का काम इंसाफ दिलवाने का है। लेकिन, यहाँ दरोगा के द्वारा वर्दी का रौब दिखलाकर जिस तरह से कृष्णदेव महतो को बुला कर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया जाता है। वो पुलिस के कार्यशैली पर सवालिया निशान तो खड़े करता ही है। साथ ही सिंह ने बताया कि जिले के पुलिस कप्तान से उन्हें उम्मीद है कि पीड़ित कृष्णदेव महतो और उनके परिवार को न्याय मिलेगा वहीं दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताकि, पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे। पुलिस जल्द ही अगर पीड़ित परिवार न्याय और दबंग दरोगा पर कार्रवाई नहीं होती तो वृहत धरना प्रदर्शन के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह कि प्रकरण ठाकुरगंज सर्किल के गलगलिया थाना क्षेत्र से जुड़ा है। लेकिन, इसकी आज तक न कोई गलगलिया क्षेत्र से जाँच हुई और न ही किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त हुई है। जबकि, वादी घटना के दिवस दिल्ली में पुलिस के समक्ष मौजूद थे। जिसका प्रमाण पुलिस अधीक्षक किशनगंज को पूर्ण साक्ष्य के साथ दी जा चुकी है। एक तरफ पुलिस महानिदेशक बिहार के बार-बार निर्देश के बाद किशनगंज पुलिस अधीक्षक सीधे जनता के बीच जाकर जनता दरबार से लेकर अपराध गोष्ठी व अन्य कार्यक्रम में सीधे संवाद कर रहे हैं। लेकिन, किसी खास वर्दीधारी के कारण पुलिस महकमें में सवालिया उठना गंभीर जाँच का विषय बन चुका है। ●

डॉ. पी.पी. सिन्हा को देश और विदेशों में मिला सम्मान

किशनगंज जिले के बहादुरगंज रहमानगंज के निवासी डा. पी.पी. सिन्हा अपने सरकारी सेवा काल व सेवानिवृति के बाद उत्कृष्ट कार्यों के लिए समय मिलता रहा। सेवा काल के भद भी लोक जीवन में अनेकों सम्मान प्राप्त किए। समाजसेवा, लोगों के लिए सेवाभाव की भावना अनेकों कार्य के लिए प्रेरणा तब बनता चला गया। जब ईलाज से लेकर किसानों के खेतों तक से खेल के मैदान तक पहुँचने के लिए प्रेरित कर दिया। पूर्व कृषि उपनिदेशक भारत सरकार डा. पी.पी. सिन्हा से साक्षात्कार के दौरान उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए पत्रिका ब्यूरो चीफ बिहार/झारखंड **सुमित राज यादव** एवं संवाददाता **प्रवेज आलम** की एक खास रिपोर्ट:-

भारत सरकार में रहते हुए बेहतरीन कार्य के लिए पाँच बार बोनेरेरियम देकर सम्मानित कर चुकी है। इस सम्मान के लिए डा. पी.पी. सिन्हा 35 बार बसंत एयरक्राफ्ट, वीभर एयरक्रॉफ्ट और मेस्को एयरलाइंस के हेलीकॉप्टर द्वारा पाकिस्तान मुल्क से आये हुए टिड्डी कीड़े का हवाई सर्वेक्षण सीमा क्षेत्र में किए और कीटनाशक द्वारा हवाई छिड़काव में सहयोग भी किए। डॉ. सिन्हा सेवाकाल के दौरान शिक्षण संस्थानों, सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों में रहकर उत्कृष्ठ कार्य के लिए लगभग 70 से अधिक सम्मान प्राप्त किए। जिसमें देशों और प्रदेशों में कार्य कर चुके हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, एम.पी., यूपी., असम, प. बंगाल, त्रिपुरा, नेपाल, बंग्लादेश, वर्मा, भूटान, पाकिस्तान, रोम, मिश्र, यूके है।

☞ वर्ष 2003 में अंतर्राष्ट्रीय हर्वल अनुसंधान संस्थान लखनऊ (उ.प्र.) द्वारा अच्छे कार्य हेतु सम्मानित हुए।

☞ कई समाचार-पत्रों के पन्नों के माध्यम से समाज सेवी के खिताब मिलने के उपरांत वर्ष 2015 में ही किशनगंज में दैनिक जागरण के द्वारा आयोजित कृषि क्षेत्रों में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सम्मान प्राप्त किए। वहीं वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान समाचार-पत्र में प्रतिभा सम्मान के खिताब से समाजसेवा के लिए नवाजा गया।

☞ वर्ष 2014 में ही सुरजापुरी भाषा विकास मंच रहमानगंज, बहादुगंज का अध्यक्ष एवं संस्थापक के लिए आर.सी.एस. एवं मीडिया कम्यूनिकेशन के निदेशक द्वारा सम्मानित हुए।

☞ वर्ष 2015 में बंगाल से प्रकाशित होने वाली जल ढाला दर्पा पत्रिका में प्रधान संपादक के पद पर नियुक्ति और वर्ष 2016 में आध्यात्मिक त्रैमासिक पत्रिका अमर संदेश में भी प्र.स. के पद पर, और अतर्राष्ट्रीय महर्षि मेही योगाक्रम का आजीवन संरक्षक बनाया गया।

☞ वर्ष 2017 में सुरजापुरी फिल्म इंस्टीच्यूट रहमानगज, बहादुरगंज, किशनगंज, बिहार के फिल्म निर्माता व निर्देशक के लिए नार्थ बंगाल फिल्म इंस्टीच्यूट वेलफेयर एसोसिएशन, सिल्लीगुड़ी द्वारा मान्रूता के साथ सम्मानित होने का गौरव मिला।

☞ वर्ष 2016 में भारतीय लेखक विकासशील मंच के राष्ट्रीय संरक्षक चुने जाने पर सम्मानित।

☞ वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय लेखक संघ के डिप्टी जेनरल सेक्रेट्री चयन होने पर सम्मानित।

☞ वर्ष 2016 में सीमा सुरक्षा बल, अररिया व ढ़ेढ़ागाछ द्वारा समाजसेवी सम्मान प्राप्त।

☞ वर्ष 2016 में साहित्य श्री सम्मान से भी नवाजे गए।

☞ वर्ष 2016 में किशनगंज पब्लिक स्कूल द्वारा समाजसेवी का सम्मान प्राप्त किया।

☞ वर्ष 2017 में अररिया, बिहार में फनीश्वर नाथ रेणु सम्मान से नवाजा गया।

☞ वर्ष 2017 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान समारोह दिल्ली में केवल सच पत्रिका के कार्यक्रम में समाजसेवी व पर्यावरणविद् का खिताब दिया गया।

☞ वर्ष 2017 में साहित्य के क्षेत्र में पंडित अमोध स्मृति सम्मान से नवाजा गया।

☞ वर्ष 2017 में ग्लोबल पब्लिक इंग्लिश स्कूल, किशनगंज द्वारा समाजसेवी का खिताब पुरस्कार।

☞ वर्ष 2016 में बी.पी. मंडल जयंती समारोह, कटिहार के श्रीकृष्ण आस्था मंच कटिहार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाजसेवी का खिताब प्रशस्ति-पत्र दिया गया।

☞ वर्ष 2016 में प्रख्यात साहित्यकार भोला पंडित प्रणय जी के अभिनंदन मंच में संपादक मंडल संयोजक मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर सम्मानित किया गया।

☞ वर्ष 2014 में किसान क्लब महासंघ किशनगंज द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में प्रतीक चिन्ह् व प्रशस्ति-पत्र के साथ समाजसेवी के लिए सम्मानित किए गए।

☞ वर्ष 2017 में भारतीय जन लेखक संघ मधेपुरा द्वारा निकाली गई पत्रिका जन-आकांक्षा में प्रधान संपादक बनाए जाने पर संघ के महासचिव के हाथों सम्मानित हुए।

☞ वर्ष 2017 में महानायक बी.पी. मंडल जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण आस्था मंच कटिहार द्वारा आयोजित समारोह में नवोदित साहित्यकार का सम्मान प्राप्त किए।

☞ वर्ष 2018 में देहाती अभिनंदन यंग समिति जगन्नाथपुर पूर्णिया में साहित्य श्रृजन सम्मान।

☞ वर्ष 2017 में भारती सेवा सदन ट्रस्ट अररिया में आयोजित बाल विवाह व दहेज प्रथा पर उत्कृष्ट वक्ता के लिए सम्मानित किया गया।

☞ वर्ष 2017 में तरूणादेय सांस्कृतिक विकास परिषद् में कवि-सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के साथ सम्मानित किया गया।

☞ वर्ष 2016 में भारतीय अविकसित साहित्य समय के राष्ट्रीय पैटर्न पर बंगाल में सम्मानित किया।

☞ वर्ष 1996 में टिड्डी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रसारण जोधपुर द्वारा किया गया और जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर के निदेशक द्वारा सम्मानित किया गया। भारत-पाकिस्तान के बीच टिड्डी पर वार्ता नियंत्रण को लेकर 1976 से 1999 तक 22 बाहर हुई। जिसमें 12 बार पाकिस्तान में हुई। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त किया हैं

☞ भारत सरकार में सेवा के दौरान 1976, 1978, 1983, 1989, 1993 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा और गुजरात सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया। सेवा काल के दौरान राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के चुनावी समर में 2 बार पीठासीन पदाधिकारी, दो बार जेनरल मजिस्ट्रेट और एक बार एरिया मजिस्ट्रेट के साथ-साथ तीन बार काउंसिलिंग एजेंट भी रह चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित।

☞ वर्ष 2018 में अररिया के फारविसगंज में प्रत्येक वर्ष दो व्यक्ति को दी जाने वाली सम्मान ने बिहार गौरव सम्मान संवदिया के संपादक के द्वारा साहित्यकार के लिए सम्मान दिया गया।

☞ वर्ष 1979 में एफ.आर.ई.यस (लंदन) की उपाधि मिली। वहीं 1997 में ईडी चालू एमके प्रशिक्षण के उपरांत मिश्र के हीरा में सम्मानित किया गया, सिमें 117 देशों के वैज्ञानिक अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारत देश के ओर से डा. पी.पी. सिन्हा प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

☞ वर्ष 1979 में राष्ट्रीय सुदुर संवेदन प्राधिकरण, हैदराबाद में भू-उपग्रह द्वारा टिड्डी सर्वेक्षण पर गहन प्रशिक्षण पर रोम (ईटली) के डा. जे.यू. हेलक्रिमा द्वारा हैदराबाद में प्रथम पुरस्कार।

☞ इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में वर्ष 1980 में चार माह की सेटेलाइट पर प्रशिक्षण के उपरांत प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया।

☞ विश्व खाद्य संगठन रोम (ईटली) द्वारा वर्ष 1981 में सुदूर संवेदन द्वारा टिड्डी की खोज पर एक माह के प्रशिक्षण के उपरांत प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किए गए।

☞ वर्ष 2012 में नेपाल के उप प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय गंगई गणेश महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर के लिए शुभकामना, बधाई।

☞ वर्ष 2016 में किशनगंज में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मौसम और जलवायु परिवर्तन पर वर्कशॉप में श्रेष्ठ वक्ता के लिए समाजसेवी के खिताब से नवाजा गया।

☞ वर्ष 2016 में ली एकादमी फारवीसगंज अररिया में समाजसेवा के लिए रेणु स्मृति सम्मान से नवाजा गया।

☞ वर्ष 2016 में पूर्णियां में नव निर्माण मंच द्वारा आयोजित टाउन हॉल में अच्छे कार्य समाजसेवा को लेकर फनीश्वरनाथ रेणु सम्मान से नवाजा गया।

☞ वर्ष 2015 में प्रभात खबर समाजसेवी, दैनिक जागरण के कवि सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया।

☞ वर्ष 2015 में प्रभात खबर समाजसेवी, दैनिक जागरण के कवि सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया।

डॉ. पी.पी. सिन्हा इसके अलावे अनेकों सम्मान प्रशस्ति-पत्र के साथ-साथ शॉल और मेमोंटो के रूप में प्राप्त किए हैं। केशव भवन संस्थान में अनेकों सम्मान सजाकर आज सुरक्षित रखे हैं। डॉ. सिंहा समाजिक हर क्षेत्रों के कार्यक्रम में शामिल होकर युवाओं और बुजुर्गों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके समाजसेवा की भावना को शब्दों में पिरोना कठिन है। केवल सच पत्रिका लगातार कई अंकों में पूर्व में भी इनके समाज-सेवा और उपलब्धियों को प्रमुखता से प्रकाशित कर चुकी है। किसान पाठशाला के माध्यम से समाजसेवा की अंतिम इच्छा बतलाते हुए कहा हे कि हम रहें या न रहें, ये देश रहना चाहिए।

पुलिस कप्तान के नेतृत्व में चला रातभर छापेमारी अभियान

● **धर्मेन्द्र सिंह**

मात्र दो दिनों की सफलताऐं एवं लगातार मिल रही उपलब्धियां किशनगंज पुलिस के नेतृत्व को आदर्श स्थान दिलाती महसूस की जा रही है। पिछली उपलब्धियां निश्चित तौर पर किशनगंज पुलिस जिला के लिए सराहनीय एवं प्रशंसनीय साबित हो सकता है। जहां पांच थानाओं से कुल कांडों के ग्यारह ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है। जिसकी संलिप्तता जघन्य अपराधों में पायी गयी है। बहादुरगंज थाना कांड सं0 27/19 के अभियुक्त मनोज कुमार दास पे0 संतलाल दास सा0 सीतागाछ को 01 ली0 देशी शराब व 01 मोटरसाइकिल एंव कांड सं0 25/19 के अभियुक्त सादिक उर्फ गड्डू पे0 स्व0 जलालुद्दीन सा0 लौचा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वही कोचाधामन थाना कांड सं0 154/17 ओपना टूडू पे0 राम टूडू साव मौजाबाड़ी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। ठाकुरगंज थाना कांड संख्या 169/18 के अभियुक्त 1. ताहिर 2.जहांगीर 3.तस्लीम 4.मुस्लिम पे0 खुर्शीद अली सा0 अमलझाड़ी एंव कांड संख्या 13/19 के अभियुक्त कादिर पे0 तोसीम सा0 नूरी चौक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। फतेहपुर थाना कांड संख्या 05/19 के अभियुक्त 1.मिथुन यादव पे0 गयानंद यादव सा0 कनखुदिया पलासी अररिया 2.विजय मांझी पे0 योगिन्दर मांझी सा0 चिचोरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। इन दोनो के पास से पुलिस ने 43 ली0 200 एमएल देशी शराब, एक मोटरसाइकिल व दो मोबाइल फोन भी बरामद किए। वही किशनगंज थाना कांड संख्या 600/18 के अभियुक्त बीरु राजभर उर्फ दीपक पे0 मदन राजभर सा0 तेघरिया एंव थाना कांड संख्या 751/18 के अभियुक्त 1. जुबेर आलम पे0 अब्दूल खलील सा0 बनबारी उ0दि0 पश्चिम बंगाल 2.एकरामूल हक पे0 सोहराब अली सा0 वकील पारा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वही पहाड़कट्टा थाना 03 वारंटी, कुर्लीकोट थाना 02 वारंटी, गलगलिया थाना वारंटी, कोढोबाड़ी थाना 01 वारंटी, टेढागाछ थाना 02 वारंटी व पोठिया थाना 04 वारंटी को गिरफ्तार किया गया।

☞ **समकालीन अभियान के तहत कार्यवाही एक नजर में :**-कांड में कुल गिरफ्तारी-13, वारंटी में कुल गिरफ्तारी-14 कुल 27 गिरफ्तारी। जेल में भेजे गए अभियुक्त की कुल संख्या-16, ज़ब्त-44 लीटर 200 एमएल देशी शराब 03 मोबाइल फोन 02 मोटरसाइकिल 04 ओवरलोड ट्रक व 02 ट्रेक्टर शामिल है। पुलिस कप्तान किशनगंज के अनुसार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में ऐसे अभियान लगातार चलाएं जाएगें।

नाबालिक का अपहरण कर किया दुष्कर्म और हत्या

● धर्मेन्द्र सिंह

पूर्णिया मुफस्सिल थानाक्षेत्र व चांदी पंचायत के दुर्गापुर गांव में एक 15 वर्षीय नाबालिक लड़की की हत्या कर शव को घर से महज 75 मीटर की दूरी स्थित एक पोखर में नग्न अवस्था में फेंक दिया। लड़की गुरुवार 14.02.2019 की संध्या 7:30 बजे के आसपास से गायब थी। शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की को पहले किसी नशीली पदार्थ खिलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है उसके बाद हत्या कर दी गई है। शव मिलने की सूचना के 45 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचे मुफस्सिल थानाध्यक्ष। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने जब यहां का नजारा देखा हरकत में आ गए, उन्होंने आनन-फानन में वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी, वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर मौके पर पहुंचे डॉग स्क्वायड और टेक्निकल सेल की टीम पहुंचकर छानबीन में जुट गई। थानाध्यक्ष ने कहा प्रथम दृष्टया यह मामला दुष्कर्म के बाद की गई हत्या का है, कहा कि यहां से मिले इनपुट पर पुलिस जांच कर रही है, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधी किसी भी सूरत पर बक्से नही जाएंगे। घटना के संदर्भ में लड़की के पिता सत्यनारायण मंडल ने बताया कि उनको और उनके छोटे बेटे बंटी को लड़की खाना परोसी उसके बाद वह चापाकल से पानी लाने गई फिर जब उन्हें प्यास लगा तो अपनी पत्नी से पानी मंगवाया, जब बहुत देर तक लड़की आसपास नही दिखी तो वे अपनी पत्नी से लड़की के बारे में पूछा तो वह बताएं कि लड़की पढ़ रही होगी। फिर जब उसकी मां ने देखा कि लड़की घर में नही है तो खोजबीन शुरू हो गया। करीब 8:00 बजे के आसपास लड़की का चप्पल उसके घर से दक्षिण पश्चिम स्थित शौचालय के पास मिला। उसके बाद रात्रि 12:00 बजे के आसपास मुफस्सिल थानाध्यक्ष को फोन कर इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि आप भी अपने स्तर से छानबीन कीजिए हम भी अपने स्तर से छानबीन कर रहे हैं। फिर माता-पिता और आसपास के लोग रात्रि 3:00 बजे तक खोजबीन की है पर कही पता नही चला। फिर जब सुबह खोजबीन होने लगी तो, घर से महज 75 मीटर की दूरी पर बांस की झाड़ी के नीचे स्थित घर में नग्न अवस्था में शव डूबा हुआ मिला। शव जब उनके चाचा निकालने लगे तो उसके नग्न अवस्था में होने का पता चला, फिर पोखर में ही कपड़ा बदल कर उन्हें बाहर निकाला गया। वही घटना स्थल के पास ही लड़की की अंतरंग कपड़े मिले। इधर, मौके पर पहुंचे डॉग स्क्वायर टीम के ब्रजकिशोर बिहारी व नरेश कुमार मोहन तथा टेक्निकल सेल के आदित्य नाथ झा अपनी टीम को लेकर पहुंचे। बांस की झाड़ी के पास मिले, लड़की के अंडर गारमेंट के साथ मिले किसी लड़के का अंडर गारमेंट को लेकर डॉग मुरली को सुंघाया गया, मुरली पूरब की दिशा में भागते हुए मंगल मंडल व महेश मंडल के घर के दरवाजे तक पहुंचा, उसके बाद फिर दूसरे साक्ष्य को मुरली को सुंघाया तो दूसरी बार भी उसी आस पास पहुंचे। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी कहने से

कतरा रही है। उनका कहना है जांच चल रही है अभी वह किसी निष्कर्ष पर नही पहुंचे हैं। लड़की के घर के पीछे से मकान खेत से 4 कफ सिरप कोडीन की खाली बोतल बरामद की है उनका मानना है कि यहां कफ सिरप को नशा के रूप में इस्तेमाल करने वाला युवक आता जाता था। हत्या की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, इसके बाद पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा, समाजसेवी प्रताप सिंह, जदयू नेता जितेंद्र यादव आदि भी सत्यनारायण मंडल के घर पर पहुंचकर सांत्वना दी और इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह काफी जघन्य अपराध है इसके अपराधी कभी भी नही बचने चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि यह घटना आसपास के ही किसी ने अंजाम दिया है। क्योंकि किसी के घर के पास से उसकी लड़की को उठाने का साहस बाहरी लोग नही कर सकते हैं। अगर इसमें बाहरी लोग भी होंगे तो, गांव के लोग जरूर सहयोग किए होंगे। अपराधी जो भी होंगे, वह बच नही सकेंगे। मुफस्सिल थाना पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है हत्या के अनुसंधान में जुटी मुफस्सिल थाना पुलिस ने दुर्गापुर गांव के ही 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिससे सघन पूछताछ की जा रही है, इस दौरान मुफस्सिल थाना पुलिस लड़की के कोचिंग के टीचर मनोज कुमार को भी थाना ले गई थी और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लड़की की सहेलियों से भी लड़की के बारे में पूछताछ की जा रही है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष मनीष कुमार झा ने कहा कि प्रथम दृष्टया दुष्कर्म के बाद की गई हत्या का लग रहा है। पुलिस हत्यारे को डिटेक्ट करने के लिए परिजनों व घटनास्थल से मिले इनपुट पर काम कर रही है हत्यारा जो भी हो, बक्से नही जाएंगे। ●

विश्व मानचित्र पर जिले की प्रतिष्ठा बढ़े : राजेश दुबे

● धर्मेन्द्र सिंह

किशनगंज लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहा है वैसे-वैसे संभावित उम्मीदवारों ने क्षेत्र भ्रमण तेज कर दिया है। उसी क्रम में लोकसभा उम्मीदवार राजेश दुबे भी लगातार क्षेत्र का भ्रमण करके मतदाताओं को अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश में लगे हुए है। दुबे ने बीते 16 जनवरी से ही क्षेत्र भ्रमण आरंभ कर दिया है और अभी तक जिले के सातों प्रखंड का दौरा किया है। दुबे ने क्षेत्र भ्रमण के बाद बताया की युवा पीढ़ी के मतदाताओं में उनके चुनाव लड़ने कि घोषणा के बाद से उत्साह का माहौल है और भ्रमण के बाद पूरे क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। दुबे ने बताया कि इलाके का जितना विकास होना चाहिए था आज तक नही हुआ और उनकी उम्मीदवारी से लोगो में आस जगी है कि अगर मै चुनाव जीतता हूं तो लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा। दुबे ने बताया कि हर साल आने वाली बाढ़ के वजह से हजारों आशियाने उजड़ जाते है लेकिन इसका समाधान की कोई कोशिश यहां के जन प्रतिनिधियों ने नही की है साथ ही बताया कि हमारा क्षेत्र गरीब और पिछड़ा हुआ है यहां पर रोड मैप बना कर काम किया जाना चाहिए जो वो करेंगे। दुबे ने बताया कि चाहे शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ व्यवस्था दोनों की स्थिति खस्ताहाल है जिसपर दुबे ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यहां के कुछ नेता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवरसिटी के नाम पर हंगामा करते है लेकिन जिले में स्थित दो सरकारी महाविद्यालय है उसमे शिक्षकों की कमी है उसपर कभी आवाज़ बुलंद नही करते आखिर क्यों। दुबे ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति पूरी तरह हावी है और बाहर से आकर कुछ नेता हवा हवाई बाते करते है लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पलायन की समस्या रुके यहां भी टेक्नोलाजी पार्क बने जैसे मुद्दों पर मुकदर्शक बने रहते है। दुबे ने कहा कि अगर जिले के जागरूक मतदाता उन्हें अपनी आवाज़ बनाते है और एक मौका देते है तो उनके द्वारा यहां पर प्राथमिकता के साथ उद्योग स्थापित करवाया जाएगा जिससे कि जिले के लोगो को रोजगार यही मिले और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र जाकर धुल ना खाना पड़े साथ ही कहा कि चिकित्सा व्यवस्था कारगर हो उसके लिए ऐम्स लाया जाएगा और मरीजों का खून चूसने वाले चिकित्सको के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। दुबे ने कहा कि जांच के नाम पर मरीजों कि गाढ़ी कमाई यहां लूटी जा रही है इसके खिलाफ जनप्रतिनिधियों का मौन धारण बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। दुबे ने बताया कि जिले में अफसरशाही चरम पर है और गरीबों का शोषण आम बात हो चुका है सभी विभाग भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगाते नजर आते है जो कि चिंता का विषय है राज्य सरकार को भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे कि विकास का सपना साकार हो सके और गरीबों की गाढ़ी कमाई लूटने से बच सके। दुबे ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि यह लोकसभा विकसित सुरक्षित और स्वच्छ बने और विश्व मानचित्र पर जिले की प्रतिष्ठा बढ़े ऐसा वो करके दिखाएंगे अगर मतदाताओं ने उन पर भरोसा जताया तो। ●

पुलिस गिरफ्त में आये तस्करों का संबध नागालैंड के उग्रवादी संगठनों से

● धर्मेन्द्र सिंह

आखिर किस शहर को दहलाने की थी साजिश। उस वक्त पूर्णिया में चल रहा था भाजपा के स्टार प्रचारक एवं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम। पूरा शहर हाई सिक्योरिटी ज़ोन में था तब्दील। चप्पे-चप्पे पर थी पुलिस की नजर। बताते चलें कि दिनांक-07.02.2019 पूर्णिया में भाजपा का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन था। जिसमे पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज के 10 हजार से अधिक कार्यकर्ता को सम्बोधित करने यूपी के सीएम एवं भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आने वाले थे। पूरा शहर हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील था। चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दालकोला चेक पोस्ट पर पुलिस और एक्साइज की टीम सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। शाम के ठीक 4 से 5 बजे के बीच एक कार को एक्ससाइज विभाग वालों ने रुकने का इशारा किया। कार रुकी तो एक्साइज विभाग वालों ने कार की तलाशी लेनी शुरू की। उन्होंने देखा कि कार के दरवाजे पर कोई कपड़ा ठूंसा हुआ है। एक्साइज वालों ने कपड़ा को फाड़ा तो देखा कि कुछ चीजें नीचे गिर गई। जब उसे गौर से देखा तो उसमें गोलियां दिखाई पड़ी गोलियां देखते ही तुरन्त वही पर खड़ी पुलिस टीम की नजर पड़ी। नजर पड़ते ही बायसी थाने की पुलिस टीम ने अविलम्ब उस कार में बैठे तीन लोगों को

गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक कार नागालैंड से पटना जा रही थी। जिसमे 576 गोलियों के 7 पैकेट थे। गिरफ्तार तीनो लोगों में दो लोग नागालैंड और एक लोग गोरखपुर के रहने वाले बताये जा रहे है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इतने अधिक मात्रा में गोलियां किसे डिलेवरी देने जा रहे थे। कौन है इसके पीछे का किगपिन। क्या करने वाले थे इतने गोलियों का। ऐसे कई सवाल है जिसका जबाब अभी मिलना बांकी है। फिलहाल पुलिस उन तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है। पूर्णिया पुलिस ने खुलासा किया है कि गिरफ्तार तस्करों के संबंध नगालैंड में सक्रिय उग्रवादी संगठन नैशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (आईएम) यानी एनएससीएन (आईएम) से जुड़े हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान विशाल शर्मा ने कहा कि 7 फरवरी को ही बायसी थाना क्षेत्र में सफारी गाड़ी से जा रहे तीन हथियार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस समय उनके गाड़ी से कुल 600 कारतूस बरामद हुआ था। लेकिन जब रिमांड पर लेकर तीनों तस्करों से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उनके गाड़ी में अन्य अत्याधुनिक हथियार भी हैं। जब गाड़ी के बॉक्स को खोला गया तो उसमें बने तहखाना में 01 से 47 राइफल, 02 यूबीजीएल लॉचर और 1200 कारतूस बरामद हुआ। पुलिस कप्तान ने कहा कि ये तस्कर इन अत्याधुनिक हथियारों को पटना में कुख्यात अपराधी मुकेश सिंह को सप्लाई करने वाले थे। उन्होंने कहा कि इन तस्करों ने पहले भी मुकेश सिंह को कई अत्याधुनिक हथियार और कारतूस सप्लाई किया है। पुलिस कप्तान के मुताबिक ये सभी हथियार म्यांमार के बने हैं। गिरफ्तार तीनों तस्करो में सूरज सिंह गोरखपुर, वीआर कहोरनगम मणिपुर और क्लीयरसन कावो मणिपुर के रहने वाले हैं। ये तस्कर नागालैंड से हथियार लेकर पटना जा रहे थे। पुलिस कप्तान ने कहा कि पूछताछ में इन तस्करों ने बताया कि पहले भी चार अत्याधुनिक हथियार ये बिहार में सप्लाई कर चुके हैं। ये लोग नक्सलियों को भी हथियार की सप्लाई करते थे। इनका संबंध नगालैंड में सक्रिय उग्रवादी संगठन नैशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (आईएम) यानी एनएससीएन (आईएम) से जुड़ा था। ●

पुलिस की कार्रवाई से इंट्री माफिया में मचा हड़कंप

● धर्मेन्द्र सिंह

10 फरवरी को किशनगंज थानाध्यक्ष मनीष कुमार के निर्देश पर एएसआई नागेन्द्र प्रसाद ने 12 ओवरलोड ट्रक को पकड़ जिसमे 5 ओवर लोड बालू गाड़ी, एवं 7 कोयला गाड़ी को जब्त कर जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गौर करे अगर अधिकारी प्राईवेट कर्मी को रहते हुए भी ओवरलोड ट्रक नही पकडते तो इसमे दोमत नही है कि अधिकारी और इंट्री माफिया दोनो एक ही पहलु के दो सिक्के है। नाम नही छापने की शर्त पर एक कर्मी ने बताया कि सरकार द्वारा फाइन करने का टारगेट फिक्स है पच्चीस लाख या अधिक वो पुरा होते ही अधिकारी वाहवही लूटने को तैयार रहते है। गौर करे जब इंट्री माफिया प्रत्येक दिन लाखो-लाख रूपया कमा रहे है सरकारी राजस्व को चुना लगाते हुए तो अधिकारी कैसे नही राजस्व को बढा सकते है ? आपने सुना होगा कि पदाधिकारी अगर एक्टीव हो तो बिना ईजाजत मक्खी भी प्रवेश नही कर सकता पर यहा तो 10 चक्का 18 चक्का 06 चक्का पार हो रहा है। बिना अधिकारी के मर्जी से ? कुछ लोग कह रहे है कि प्राईवेट लोग को तनख्वा कौन देता है वो कैसे पता चलेगा तो किसी ने कहा कि सुचना के अधिकार के तहत सुचना परिवहन विभाग से मांग करे तो पता चल सकता है। पर यहॉ तो सुचना का अधिकार

अधिनियम का उल्लंघन करने मे जरा सा भी देर नही लगाते लोक सुचना पदाधिकारी (संबधित विभागो का) तो कैसे पता चलेगा।गौर करे तो किशनगंज मे ओवरलोड ट्रक का परिचालन कभी नही रूक सकता और जिला प्रशासन का कहना है कि किसी भी सुरत मे ओवरलोड ट्रक नही चलने देंगे। फिर भी चलता है तो इसमे क्या किया जाये। जिला पुलिस तो पुलिस कप्तान के निर्देश मे ओवरलोड पर कार्रवाई करती ही है। पर संबधित विभाग 8-10 ओवरलोड ट्रक पकड़ सुस्त क्यो हो जाती है...इसमे क्या राज है। केवल सच मे छपी रिर्पोट के बाद परिवहन विभाग द्वारा जनवरी माह मे ठाकुरगंज, गलगलिया, कुर्लिकोट, बहादुरगंज आदि जगहो से कुछेक ट्रकों से फाइन वसूल किया है। वहीं किशनगंज पुलिस एक ही दिन में 12 ओवरलोड ट्रक पकड़ इंट्री माफियाओं मे हरकम्प मचा दिया है। अब तो आलम ये है कि किशनगंज थाने के ईमानदार दारोगा नागेन्द्र प्रसाद कि गस्ती जब निकलती है तो इंट्री माफियाओं मे चर्चा का बिषय बन जाता है कि गस्ती पे निकल चुके है नागेन्द्र प्रसाद और जब तक गस्ती गाड़ी वापस थाने नही आ जाती तब तक दोनों ओर ओवरलोड ट्रकों की लाइन लग जाता है। ये नागेन्द्र प्रसाद ऐसे दारोगा है जिससे अपराधी बच नही सकता है। इन्होंने किशनगंज जिले मे अपराधियों को मकई के खेत मे दौरा दौरा कर पकड़ा है। पर जब से एएसआई नागेन्द्र प्रसाद की लड़की की हत्या हुई है तब से श्री प्रसाद बहुत ही डिपरेशन मे रहने लगे है। जिसकी चर्चा आम लोगो मे भी है। क्या क्या है इंट्री माफिया का कोड:- नेता जी, वकील साहब, सिंह जी, प्रधान साहब, बाबा, भाई जी, मिश्रा जी, डॉक्टर साहब, मेजर, इंट्री माफिया प्राय चावल मंडी खगड़ा रेल गेट पे हुजुम लगाये हुए रहता है। नोट:-अभी इंट्री का खेल ठाकुरगंज, गलगलिया, कुर्लिकोट, बहादुरगंज मे जोरो पर है। जिसका मास्टर मांइड चक्करमारी का टिंकु राय, मेजर, और मास्टर टायर दुकान एलआरपी चौक बहादुरगंज है। आपको मालूम हो कि किशनगंज में ओवर लोड का फ़ाइन में किशनगंज पुलिस आगे है।अगले मे दी जायेगी शिक्षा विभाग मे डिपटेशन का खेल किस तरह से हावि है। प्रधान सचिव का आदेश का कैसे उड़ाया जा रहा है धजिया...। ●

सगाई की खुशी में युवक ने लगायी शराब में डुबकी फिर पहुंचा जेल

06 फरवरी की शाम शहर के खगड़ा मार्केट के एक युवक ने जमकर शराब पी। शराब का नशा इतना चढ़ने लगा की नशे में आकर वह मोबाइल दुकानदार से हाथापाई पर उतारू हो गए। मामला किशनगंज टाउन थाना का है। बता दें कि युवक की सगाई अगले ही दिन बड़े ही धूमधाम से हुई थी। सगाई की खुशी में युवक ने जमकर शराब में डुबकी लगाई। ऐसे में सगाई हुए लुगाई ने युवक को मिस कॉल दिया युवक ने मिस कॉल देखकर फोन करना चाहा। इत्तेफाक से उनका मोबाइल में रिचार्ज नही था। युवक आनन-फानन में मोबाइल दुकान में जाकर रिचार्ज करने को कहा। मोबाइल दुकानदार ने कुछ देर बाद कर देने की बात कही चूंकि युवक शराब पिया हुआ था। इसलिए वहां पर नही रुका और रुपए देकर वहां से एक दो तीन हो गए। बार बार मिस कॉल आ रहे थे परंतु वह कॉल नही कर पा रहा था। चंद मिनट के बाद युवक ने दोबारा मोबाइल दुकान पहुंच गए और दुकानदार को जल्द से जल्द रिचार्ज करने की बात कहने लगे। दुकानदार ने कुछ नेटर्वक प्रोबलम बताया और बोला थोड़ी देर में हो जाएगी। मोबाइल दुकानदार का इतना ही बोलना था कि युवक गुस्से से लाल पीला हो गए और फिर क्या था उसने दुकानदार के साथ हाथापाई पर उतर गए। दुकानदार समझदारी से काम लिया और प्रशासन को इसकी सूचना दे दी। कुछ ही देर बाद पुलिस आई और युवक को ससुराल के जगह मेडिकल कराकर जेल भेज दिया। **प्रस्तुति :- धर्मेन्द्र सिंह**

दुष्कर्म के सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में

● धर्मेन्द्र सिंह

किशनगंज दिघलबैंक के पथरघटी में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जिला पुलिस कप्तान कुमार आशीष द्वारा गठित एसआईटी की लगातार छापेमारी एवं दबिश से अन्य शेष बचे दो आरोपियों ने सोमवार 11 फरवरी को किशनगंज न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। जिसे किशनगंज पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी जिससे मामले से संबंधित कई नई जानकारियां सामने आ सकती है। गौरतलब है की मध्य रात्रि को घर मे सोई एक 19 वर्षीय युवती को आस-पड़ोस के ही आधा दर्जन अपराधियों ने घर से जबरन उठा कर उसके बुजुर्ग पिता को बंधक बनाकर, मुंह और आंख पर काली पट्टी बांध कर उसके सामने ही सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद जिला पुलिस कप्तान कुमार आशीष ने स्वयं घटना स्थल का जायजा लेकर पीड़िता से आवश्यक पूछताछ के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित कर लगातार छापेमारी के आदेश जारी किए। इस टीम में घटना स्थल के समीप के सभी थानों के पुलिस अधिकारियों को इस कार्य में लगाया और तुरंत नतीजा भी निकला 36 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि पुलिस कप्तान की सटीक रणनीति एवं कुशल नेतृत्व में एसआईटी की लगातार छापेमारी एवं दबिश के कारण शेष बचे दोनों आरोपियों ने सोमवार 11 फरवरी को माननीय न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया। सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर आगे की कार्रवाई

करेगी। पीड़ित को मुआवजा दिलाने को लेकर पुलिस कप्तान कुमार आशीष कर रहें हैं पहल, आपको बताते चले कि सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत किशनगंज पुलिस अब पीड़िता को जिला पीड़ित प्रतिकर निधि के माध्यम से समुचित मुआवजा प्रावधान के अनुसार 3-5 लाख रुपये दिलवाने के प्रयास भी शुरू कर रही है। इसके लिए जिला अपराध क्षति प्रतिकर बोर्ड को आवेदन करवाया जा रहा है। सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत कर कठोरतम सज़ा दिलाने का होगा प्रयास। और सभी अभियुक्तों पर स्पीडी ट्रायल चलेगा, ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। क्या कहते है किशनगंज वासी, आपको बताते चलें कि अपराधियों के लिए कहर है पुलिस कप्तान कुमार आशीष।किशनगंज पुलिस कप्तान के नेतृत्व में मिली बड़ी सफलता के लिए पुलिस बल बधाई के पात्र है। समाज मे ऐसे हवसी दरिंदों के लिए बड़ी सबक है।जनता के लिए पुलिस का विश्वास एकबार फिर बरकरार रखने में सफल किशनगंज पुलिस कप्तान कुमार आशीष बहुमुखी प्रतिभा के धनी और शांत स्वभाव के मृदुल भाषी आईपीएस अधिकारी है। गर्व है ऐसे पुलिस कप्तान हमारे जिला के पुलिस कप्तान है। ●

पुलवामा के शहीदों को पुलिस कप्तान कुमार आशीष ने दी विनम्र श्रद्धांजलि

जम्मू कश्मीर में अबतक के सबसे बड़े आतंकी हमले मे 44 जवानों की शहादत ने देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश अपने वीर जवानों की शहादत से मर्माहत है।गुरुवार 14.02.2019 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2500 से अधिक कर्मी 78 वाहनों के काफिले में जा रहे थे। इनमें से अधिकतर अपनी छुट्टियां बिताने के बाद या फिर ट्रेनिग पूरी कर अपने काम पर वापस लौट रहे थे। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर पुलवामा के अवंतिपोरा इलाके में इस बड़े काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले ने हर भारतवासी को झकझोर कर रख दिया है। पुलवामा के शहीदों को बिहार के किशनगंज जिले के पुलिस कप्तान कुमार आशीष ने भी कर्तव्य की बलि वेदी पर अपने प्राणों को न्योछवार कर शहादत की मिसाल पेश करने वाले जवानों को अपने लरजते शब्दो के माध्यम विनम्र श्रधांजली दी है।

कांडो के निष्पादन में प्राप्त कुर्की जब्ती को प्रभाकारी बनाये : डीआईजी

● धर्मेन्द्र सिंह

कोचाधामन थाना में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी में पूर्णियाँ प्रक्षेत्र के डीआईजी श्री राजेश त्रिपाठी ने कही। जहाँ किशनगंज पुलिस कप्तान कुमार आशीष पूर्व से ही गोष्ठी को संचालित करते अपराध नियंत्रण को लेकर जिले भर के पुलिस पदाधिकारियों को एक एक विषय पर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। पूर्णियाँ प्रक्षेत्र डीआईजी के आगमन की अगुवाई पुलिस कप्तान कुमार आशीष ने की।डीआईजी के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जिसके बाद वे सभाकक्ष पहुंचे जहाँ इन्होने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को पुलिसिग के आवश्यक गुर बताये और कहा कि अनुसंधान के क्रम में अगर भेसरा मिला है तो उसे तुरंत फोरेंसिक लैव में जांच के लिए भेजकर रिपोर्ट प्राप्त कर कांडो को निष्पादित करें। फरारी पंजियों का हमेशा अवलोकन कर फरारियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करें। शराब पीने या बेचने वाले अभियुद्रों का नाम गुंडा पंजी में दर्ज करें। उन्होंने साफ लहजों में कहा की ऐसे निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाही करें। इस बीच माह जनवरी माह में प्राप्त फलाफल की प्रेस विज्ञप्ति पुलिस कप्तान के द्वारा साझा किया गया। जिसके मुताबिक इस माह में कुल अंरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।जिसमें से हत्या के एक, कांडों के 101 एवं कुल 119 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। वही कांडों के निष्पादन लक्ष्य 229 के विरुद्व 235 कांडों का निष्पादन किया गया। जबकि जुर्माना के विभिन्न शीर्षो से कुल 34,04,350 रु0 का जूर्माना वसूल कर सरकारी खजाने में जमा किया गया। जिसमे किशनगंज नं0-01 गलगलिया नं0-02 और बहादुरगंज थाना तीसरे स्थान पर रहकर अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इस कड़ी में जप्ती इस प्रकार की गयी:- कट्टा 01, गोली 02, चार पहिया छोटे बड़े वाहनो में दोपहिया वाहन सहित 35 की जप्ती। विदेशी शराब 3431 लीटर 190 एमएल, देशी शराब 91ली0 200 एमएल, मवेशी 108, स्मेक 620 मि.ग्राम साथ तीन पुड़िया अलग से, गांजा 04 किलो साईकिल, 01 फोन 13, धान 13 क्वींटल, 80 किलो, चावल 04 क्वीं गेहूं 02 क्वीं 80 किलो की कुल जप्ती की गयी है।

किशनगंज पुलिस कप्तान कुमार आशीष ने अपने व्यसतम समय में कोचाधामन प्रखंड के सरपंचों से भी मिलकर उनसे पुलिस को सहयोग कर अपराध पर नकेल डालने में उनके मदद की अपील भी की। जबकि जिले को मिले 04 जिप्सी और 05 सूमो गाड़ियों की चाभी डीआईजी श्री त्रिपाठी के माध्यम से संबंधित थानाध्यक्षों को सौंपी गई। जहाँ से डीआईजी को रवाना कर पुलिस कप्तान कुमार आशीष बिशनपूर में आयोजित क्रिकेट में बल्लेबाजी कर लोगों का मन मोह लिया। इस बैठक में किशनगंज के एसडीपीओ डा0 अखिलेश कुमार, डीएसपी मुख्यालय, पी0एन0 सिंह, प्रमोद कुमार राय और राजकुमार सहित पुलिस निरीक्षक सह सर्जेंट मेजर रंजन कुमार, ओ एसडी ईरशाद आलम,राजेश कुमार तिवारी, यातायात प्रभारी, सहित अंचल पुलिस निरीक्षक आफताब अहमद, आशिफ वेग, बिजय कुमार थानाध्यक्ष ठाकुरगंज, मेराज हुसैन थानाध्यक्ष कोचाधामन, सुमन कुमार सिंह, थानाध्यक्ष बहादुरगंज सहित जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों सहित बीएसएफ 167 बटालियन के उप सेनानायक नीरज कुमार, 19वीं बटालियन, एसएसबी के श्रृषि कुमार (निरीक्षक) ईन्सपेक्टर वीसी विश्वास, मिलेट्री खुफिया शाखा के विशेष सहित बिहार उत्पाद के निरीक्षक मनोज कुमार मनोज बैठक में मौजूद थे। ●

शराब माफिया चढ़ा बायसी पुलिस के हत्थे

● धर्मेन्द्र सिंह

पूर्णिया बायसी थाना की पुलिस के हाथ लगी एक बड़ा कन्साइनमेंट पटना के मुस्लहपुर हाट में किसी बड़े शराब माफिया को देनी थी डिलेवरी। बायसी थानाध्यक्ष सुनील कुमार द्वारा विगत दो महीने में 12 हजार शराब को पकड़ने से शराब माफियाओं में हड़कम्प मच गया है। बताते चलें कि बायसी थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर UP-65 R 9129 नम्बर की ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर ने पुलिस के रुकने के इशारे को अनदेखी कर ट्रक को लेकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने ट्रक को भागने नही दिया और ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया।

जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में 350 कार्टून विदेशी शराब की बोतलें मिली। ट्रक की पूरी तलाशी लेने के बाद ब्लेंडर्स प्राइड और रॉयल स्टेज की 3118.6 लीटर शराब बरामद हुई। पुलिस की पूछताछ पर ड्राइवर ने बताया कि स ५।। कार्टून पटना के मुस्सलहपुर हाट में किसी बड़े शराब कारोबारी को डिलेवरी करने की बात थी। ड्राइवर ने बताया कि सभी शराब के कार्टून दालकोला से लेकर पटना जाना था। मुझे एक मोबाइल नम्बर दिया गया था। मुझे कहा गया था कि पटना के मुस्सलहपुर हाट पहुंचकर इस मोबाइल नम्बर पर फोन करना। फोन करने के बाद लोग आएंगे और ले लेंगे। गिरफ्तार ड्राइवर जीतन कुमार राय और मंटू कुमार राय है जो कि छपरा जिले के रहने वाले है। ●

वाहन चोरो के गिरोह का हुआ उद्‌भेदन

● अब्दुल कय्यूम

अररिया जिले के नरपतगंज क्षेत्र से पुलिस ने सघन छापेमारी अभियान में एक बहुत बड़ा वाहन चोर के रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस छापेमारी अभियान में अररिया पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जहाँ से पुलिस ने गिरोह के कब्जे से चोरी के नौ बाइक, तीन ट्रैक्टर, दो दर्जन पुरानी वाहन की डिग्गी, अलग की गई वाहन के पार्ट्स व तीन बोरा नेपाली शराब बरामद की है।

जानकारी के अनुसार फारबिसगंज डी.एस.पी. मनोज कुमार के नेतृत्व में 08 फरवरी को नरपतगंज के फुलकाहा थाना क्षेत्र के मानिकपुर गाँव से रात्रि सघन छापेमारी अभियान चलाकर चोरी के नौ बाइक, तीन ट्रैक्टर, एक टेलर, दो दर्जन बाइक की डिग्गी, बाइक के पूर्जे सहित तीन बोरा नेपाली शराब बरामद किया है। इस क्रम में रैकेट के सरगना गृह स्वामी राजीव यादव, अनमोल यादव, संजीव यादव, रंजीत यादव, मोनू यादव तथा रानीगंज के विजय कुमार सहित सात व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

फरबिसगंज डी.एस.पी. मनोज कुमार ने केवल सच प्रतिनिधि का वार्ता के क्रम में बताया कि हिरासत में लिए गए वाहन चोरों के गिरोह से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार राजीव यादव का एक संगठित गिरोह था। राजीव यादव गिरोह का सरगना था। इस गिरोह द्वारा अररिया, पूर्णियाँ, सुपौल, नेपाल से चोरी की गई गाड़ियों को खरीदा व बेचा जाता था। चोरी की गाड़ियों का प्रयोग शराब तस्करी में किया जाता था। डी.एस.पी. श्री कुमार ने बताया कि राजीव यादव एक टूटे फूटे घर में रहकर पूरे रैकेट को चलाता था। वह चोरी की वाहनों को पुआल व भूसा के ढेर व आंगन के इर्द-गिर्द छुपाते थे। ये नेपाल, अररिया, सुपौल सहित अन्य जिलों के चोरी की वाहन को यहाँ ठिकाना लगाकर बेच देते थे। छापेमारी में फारबिसगंज थानाध्यक्ष पी. के. प्रवीण, नरपतगंज के थानेदार सुनील कुमार, घूरना ओ.पी. के पवन कुमार पासवान सहित सात थाना के थानेदार शामिल थे। इधर वाहन चोरी के रैकेट का पर्दाफाश होने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।

इधर एस.पी. धूरत सायली ने नरपतगंज के मानिकपुर गाँव के वाहन चोरी के गिरोह का उद्‌भेदन करने को पुलिस की एक बड़ी सफलता मानते हैं। उन्होंने बताया कि वाहन चोरी का एक संगठित गिरोह था। जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था। एस.पी. धूरत सायली ने बताया कि फारबिसगंज एएस.पी. मनोज कुमार व थानाध्यक्ष सुनील कुमार के द्वारा गठित टीम को इस कार्य के लिए सम्मानित किया जायेगा। ●

अररिया जिला के पलासी सी.ओ. चढ़ा निगरानी के हत्थे

● अब्दुल कय्यूम

अररिया जिला के पलासी अंचल में पदस्थापित सी.ओ. बीरेन्द्र कुमार सिंह को भूमि अधिग्रहण के नाम पर रिश्वत लेना महंगा पड़ गया। पटना से आई निगरानी टीम ने सात फरवरी को एक लाख रूपये रिश्वत के साथ उनके अररिया आवास स्थित शिवपूरी से रंगे हाथ दबोचा। सी.ओ. बीरेन्द्र कुमार सिंह ने पलासी प्रखंड के बलुआ कलियागंज के निवासी सत्यनारायण यादव से जमीन व मकान को अतिक्रमणमुक्त कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। निगरानी टीम ने गिरफ्तार सी.ओ. बीरेन्द्र यादव को आवास के बाद जिला परिषद् डाक बंगला व पलासी अंचल ले गया। पलासी अंचल पहुँचकर निगरानी के डी.एस.पी. गोपाल प्रसाद ने प्रधान अंचल सहायक रतन कुमार से मामले की पूछताछ कर उक्त मामलों से संबंधित दस्तावेज को अपने कब्जे में लेकर पटना वापस लौट गए। इस क्रम में निगरानी के डी.एस.पी. गोपाल पासवान ने बताया कि पलासी के बलुआ

कलियागंज निवासी सत्यनारायण यादव का मकान सड़क के किनारे है। सी.ओ. ने 04 जनवरी 2019 को उक्त जमीन सरकारी है तथा उनके द्वारा अतिक्रमित है, खाली करने का नोटिस भेजा था। सत्यनारायण यादव ने सी.ओ. के खिलाफ ए.डी.एम. को आवेदन दिया था। ए.डी.एम. ने सी.ओ. को मामले की जाँच कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया था। सत्यनारायण यादव ने सी.ओ. व कर्मचारी से मिलकर सरकारी जमीन का अतिक्रमण नहीं बनने के मामले का प्रतिवेदन ए.डी.एम. को भेजने के लिए आग्रह किया। इसके बदले सी.ओ. ने उनसे एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की। निगरानी के डी.एस.पी. श्री पासवान ने बताया कि सत्यनारायण यादव ने इसकी शिकायत 17 जनवरी को निगरानी विभाग में की थी। आवेदन की जाँच के बाद मामले का सत्यापन किया गया और 07 फरवरी को सी.ओ. को रिश्वत लेते हुए आवास पर गिरफ्तार किया गया। निगरानी टीम में इंस्पेक्टर संजय चतुर्वेदी, मिथिलेश जयसवाल, उमा शंकर सिंह, जहाँगीर अंसारी आदि शामिल थे। ●

भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबकी लगा रहे पदाधिकारी व कर्मचारी : अमर सिंह

राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य गाँव में पंचायतों में विकास योजनाओं को सही रूप में उतारना है। जब तक गाँव के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं को सही रूप में उतारना है। जब तक गाँव के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाएँ नहीं पहुँचेगी तब तक गाँवों व पंचायतों में विकास नहीं दिखेगा। इसके लिए अधिकारियों के साथ-साथ पंचायत जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है। राज्य के पंचायत प्रतिनिधि ऐसे मिले सिने अपने पंचायत की दशा और दिशा दोनों बदल दी। कल तक गाँवों में गंदगी का अंबार दिखता था, अब वहाँ सुव्यवस्थित तरीके से नालियाँ व सड़कें बनी है और क्षेत्र साफ-सुथरा दिखने लगा है। इसके अलावा कई जनप्रतिनिधियों ने अपने ही गाँवों व पंचायतों में रोजगार के उपाय ढूँढ़ निकाले हैं। इन सबके इतर मुखियागण कार्य तो युद्ध स्तर पर कार्य तो करा रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से काम हो रहा है उस रफ्तार से मजदूरों का भुगतान नहीं हो पाया। मनरेगा के मजदुर, ईंट भट्ठा मालिक व वनपोषक सभी जनप्रतिनिधियों का भुगतान हेतु नाक में दम कर रहे हैं। सरकार की मंशा काम कराने की नहीं अपितु परेशानी का सबब बनाकर रखना है। स्वास्थ्य केन्द्र बिमार हो चुके हैं एक अदद-सा एम्बुलेंस तक नहीं है। विद्यालयों में एम.डी.एम. की लूट मची है। जन वितरण के दुकानदार राशन, किरासन की धड़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं। अधिकारी वर्ग के लिए ये सभी प्रोटीन वर्ग बन चुके हैं। एक ओर सरकार की नियति में खोट तो दूसरी ओर अधिकारियों की तुमाफेरी ने प्रखंड कार्यालय में मची लूट-खसोट से जन प्रतिनिधियों में झोभ व्याप्त है। सरकार की ढुलमुल नीति, वनपोषकों के बकाये भुगतान के अभाव लगे पेड़ सूख रहे हैं। कबीर अन्त्येष्टि तथा अन्य योजनाओं के भुगतान अधर में है। सरकार सिर्फ कागजों में विकास दिखाकर अपना पीठ थपथपा रही है। जबकि हकीकत में कुछ और ही हो रहा है। उपरोक्त तथ्यान्वेषण के मद्देनजर मुखिया संघ के अध्यक्ष, व मुखिया मशरक पूर्वी के प्रतिनिधि **अमर सिंह** का साक्षात्कार केवल सच राष्ट्रीय मासिक पत्रिका के विशेष प्रतिनिधि बिहार **आनन्द प्रकाश पाण्डेय** व छाया प्रतिनिधि **अशोक तिवारी** ने किया। प्रस्तुत है खास अंश :-

★ आपके पंचायत में विकास की गति कैसी है?

जितने भी विकास कार्य अब तक हुए हैं। उसका भुगतान आधा-अधूरा ही हुआ है। मनरेगा के मजदूर, वनपोषक भट्ठा मालिक सभी बकाया भुगतान के लिए मुखिया पर दबाव बना रहे हैं। कार्य करने के छह माह तक भी पैसा मजदूरों को न मिले तो वे क्या करेंगे? मजदूर कब तक भूखे पेट दिन काटेंगे? उनके भी बाल-बच्चे हैं। मुखिया कब तक इस सरकारी तुमाफेरी का दंश झेलेंगे? मनरेगा के अन्तर्गत आठ-नौ योजनाओं में कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन भुगतान अधूरा है, जिसके वजह से विकास कार्य अवरूद्ध हो रहा है। जितने वृक्ष लगे थे वे उचित देख-रेख के अभाव में सूख रहे हैं। वनपोषक भुगतान की राह देख रहे हैं। मुखियागण कब तक जिल्लत का मार झेलेंगे?

★ आपके प्रखंड में सतरह पंचायत हैं, उनमें वृक्षारोपण की क्या स्थिति है?

देखिए, आपलोग सच छापते हैं तो मैं सच ही बयां कर रहा हूँ। वनपोषकों को 6 माह से भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पौधे सूख रहे हैं। उचित-रख-रखाव के अभाव में सब कुछ अधर में है। मुखिया क्या करे? सरकार की दोषपूर्ण नीति से मुखियागण आजिज आ गए हैं।

★ आपके यहाँ मशरक में स्वास्थ्य केन्द्र व मीड-डे-मील योजना की क्या स्थिति है?

मशरक में एम.डी.एम. बिचौलिए के बीच ही सिमट कर रह जाता है। अधिकारी से लेकर हेडमास्टर तक ''छूट के लूट'' की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। बच्चे आकर खड़े रहते हैं। शिक्षक नदारद रहते हैं। स्वास्थ्य केन्द्र की बात करें तो सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। स्वास्थ्य सेवा के नाम पर मरीजों का आर्थिक शोषण हो रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है। एक अदद एम्बुलेंस की सुविधा मयस्सर नहीं है। स्वास्थ्य सेवा बिमार व लाचार है। गरीब मरीज कहाँ जायेंगे? रोगी को भाड़े की गाड़ी से मुख्यालय जाना पड़ता है। पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है।

★ मशरक प्रखंड कार्यालय की क्या स्थिति है?

पूछिए मत, प्रखंड कार्यालय में अधिकारी सेलेकर अदना सा कर्मचारी तक भ्रष्टाचार में डूबकी लगा रहे हैं। ऐसे में विकास की बात बेमानी है। बिना रिश्वत दिए कोई भी कार्य संभव नहीं है।

★ मनरेगा व अन्य योजनाओं में काम करवाने के बावजूद मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है, क्यों?

सरकार की दोषपूर्ण नीति व नौकरशाहों के लालफिताशाही के कारण ये स्थिति बनी है। आखिर जन प्रतिनिधि क्या करें? सरकार की मंशा काम होने देने की नहीं है। सिर्फ फंसा कर टालने की नियति है।

★ जन वितरण दुकान की वर्तमान स्थिति बतायें। क्या लाभुकों को राशन व किरासन समय पर मिलता है?

जन वितरण दुकानदारों की स्थिति भयावह है। तीन महीना बाँटा जाता है, तो अगला तीन महीना का राशन-किरासन भ्रष्टाचार, बिचौलिए व अधिकारियों की भेंट चढ़ जाता है। विडंवना यह है कि राशन बाँटना हो तो 5 हजार और नही बाँटना हो तो 15 हजार अधिकारियों को नजराना दी जाती है? ऐसे में सुधार की गुंजाइश कहाँ है? यहाँ तक कि किसी के घर में मौत भी हो जाए तो लाभुक को राशन-किरासन मयस्सर नहीं होता। इसके लिए जिम्मेवार कौन है?

★ प्रखंड में तथा मशरक पूर्वी में पेंशन की क्या स्थिति है?

बदतर है। प्रखंड में कई बार तालाबंदी करने के बाद भी पेंशन कुछ ही लाभुकों को मिल पाया है। आखिर कितनी बार आंदोलन करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा परेशानी वृद्ध व विधवाओं को हो रही है। अधिकारियों को इसकी चिन्ता नहीं है। उन्हें तो कमीशन चाहिए।

★ कबीर अंत्येष्टि व कन्या विवाह योजना का कितना लाभ आपके क्षेत्र में मिला है?

कबीर अंत्येष्टि का पैसा अपने स्तर पर मुखियागण द्वारा प्रदान किया गया है। लेकिन इस योजना का पैसा छह महीना या साल भर पर आता है, आखिर योजना का लाभ कैसे मिलेगा? कन्या विवाह योजना का लाभ नहीं मिलने का कारण बी.डी.ओ. साहब कहते हैं कि इस योजना का चार्ज नहीं मिला है। इसके इतर लाभुक मुखिया की मजदूरी नहीं समझ पाते। सरकार व उसके अधिकारी सिर्फ मुखियाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। कबीर अंत्येष्टि के अन्तर्गत लाभुकों को लगभग 2 लाख रूपये वितरीत किया है,

लेकिन सरकार द्वारा मात्र 52000 रूपये का चेक मिला है। बताइए कोई मरता है तो मुखिया के पास, झगड़ा हो तो मुखिया के पास, लेकिन मुखिया किसके पास जायें? सरकार सिर्फ और सिर्फ कागज में चल रही है। सरकार के दलाल अधिकारी चार-पाँच महीने पर जाँच करने आते हैं। अब आप ही बताएँ भूखे मजदूर व वनपोषक व लाभुक उन्हें पकड़ कर पीटेंगे नहीं तो क्या करेंगे?

★ पंचायत प्रतिनिधियों की वर्तमान में क्या स्थिति है?

सरकार की योजनाएँ सिर्फ कागजों पर दौड़ रही है। विकास भी कागजों पर मुखर हो रहा है। देखिए आपके सामने ईंट वाला, मनरेगा, मजदूर, वनपोषक घेर के पैसे के लिए बैठे हैं। ऐसे में सरकार क्यों विकास की उम्मीद करती है। नतीजा ढाई के तीन पात की स्थिति है। सरकार की दोगली नीति के कारण मजदूरों का दूसरे राज्यों में पलायन हो रहा है। सरकार 177 रूपये देती है। उन्हें मानक मजदूरी मिलेगी तभी उनका पलायन रूकेगा। वनपोषकों का बकाया भुगतान न होने का सीधा असर यह हो रहा है कि पौधे सूख रहे हैं। लगभग यही स्थिति पूरे प्रखंड की है। चौदहवें वित्त का पैसा है तो उसके मद्देनजर जल नल योजना की शुरूआत शीघ्र होगी। दूसरी ओर यह निर्विवाद सत्य है कि यह योजना फ्लॉप ही होगा।

सामान वेतन हमारा अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे : संतोष कुमार

सर्वविदित है जब जनता के सब्र का बाँध टुटता है तो मजबूत सत्ता की कुर्सी भी बहते देर नहीं लगती। यह आत्मचिंतन का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जिससे शिक्षक समुदाय को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। एक पंचवर्षीय योजना तक भी सरकार की नियमावली टाँय-टाँय-फिस्स हो जाती है। जब सरकार नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति में शैक्षिक व प्रशैक्षणिक योग्यता समान खोजती है। जब काम के घंटे समान है तो तो उसके अनुरूप वेतन चाहते हैं तो क्या गुनाह करते हैं? यह सरकार के दोयम दर्ज की सोंच का परिचायक है। मौजूदा सरकार ने शिक्षकों की विरादरी को साजिश के तहत कई खंडों में बाँटकर शिक्षकों की अस्मिता पर कठोर-कुठाराघात कर रही है जो दोरंगी नीति का द्योतक है। ऐसे में शिक्षक समुदाय दिनानुदिन रूसी क्रांति की ओर बढ़ रही है। सरकार द्वारा वेतन फिटमेंट कमिटी की सिफारिश की भी मुखालफत की जा रही है जो निंदनीय है। सरकार के नित्य नये तुगलकी कानूनों/फरमानों से क्या भला होने वाला है? जबतक सरकार की दोरंगी नीति का खात्मा नहीं होगा, शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक सारी योजनाएँ व अन्य बेमानी साबित होते रहेंगे। वक्त का तकाजा है कि मौजूदा शासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। क्या यह शासन के ढोल की पोल खोलन के लिए पर्याप्त नहीं है? शिक्षकों के समस्याआं पर केवल सच राष्ट्रीय मासिक पत्रिका विशेष प्रतिनिधि **आनन्द प्रकाश पाण्डेय** व छाया पत्रकार **अशोक कुमार तिवारी** ने अंचल प्राथमिक शिक्षक संघ मशरक के अध्यक्ष **संतोष कुमार** से शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर साक्षात्कार किया, प्रस्तुत है साक्षात्कार का अंश:

★ आपका नाम?

संतोष कुमार

★ सरकार की वर्तमान शिक्षा पद्धति पर आप क्या कहेंगे?

देखिए सरकार की मंशा शिक्षा के प्रति दोयम दर्जे की है। यह सिर्फ नित्य नये प्रयोगों वाली सरकार है। रोज नये-नये तरीकों का इस्तेमाल कर शिक्षक, छात्र व अभिभावकों को हलकान कर रही है। मसलन, शौच करते लोगों से सीटी मारकर भगाओ, कभी बैंक में खाते खुलवाओ, बनियागिरी करो जैसे कई प्रमुख काम है। सरकार की इस तरह की तुगलकी फरमान सिर्फ और सिर्फ राजीनति से ओत-प्रोत है। बानगी देखिए कभी सामान्य को छात्रवृति नहीं, तो कभी अतिपिछड़ा को नहीं, कभी अन्य को नहीं। तो कभी सभी को मिलेगा, कभी 75% की नौटंकी तो कभी बिना 75% का पैसा मिलेगा। एक तरफ कहती है जाति सूचक शब्द नहीं, हर समय जातिवाद का ही ककहरा का प्रयास करती है। जातिवाद व असंतोष का बढ़ावा सिर्फ वोट की राजनीति के तहत होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है सरकार का एकमात्र उद्देश्य साक्षर बनाना ही रह गया है।

★ मीड-डे-मील योजना छात्रों के हित में है या नहीं?

महोदय, मीड-डे-मील योजना निश्चित तौर पर शिक्षा के आड़ में स्लेट के स्थान पर प्लेट पकड़ा दिया है। इस योजना से भीड़ इकट्ठी हो रही है। निश्चय ही यह योजना बंद होनी चाहिए। यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में कोढ़ के खाज की तरह हे। शिक्षकों का पूरा समय इसी में निकल जाता है।

★ सरकार की शिक्षकों के प्रति जो उदासीन रवैया है, इस पर आपका क्या विचार है?

सरकार की नीति शिक्षकों के खिलाफ है। सरकार की नीतियों से शिक्षकों में आक्रोश है। सरकार की दोगली नीति के कारण ही शिक्षक सड़क से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत मात्र ऐसा देश है जहाँ शिक्षकों को अपने हक के लिए सड़क से न्यायालय तक

लड़ना पड़ता है बाकि अन्य देशों में ऐसा नहीं होता, जिसका दूरगामी परिणाम सबके सामने है। चपरासी को 36 हजार रूपये और शिक्षक को 20-25 हजार। ऐसे में शासन गुणवतापूर्ण शिक्षण का ख्वाब देखती है। RTE कानून का यह खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। सरकार खुद मैकाले के मार्ग पर चलकर शिक्षा रूपी रीढ़ को तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन सरकार को भी तैयार रहना चाहिए। शिक्षक भी उनकी औकात बताने को तेयार है।

☆ समान शिक्षा प्रणाली पर आपकी क्या राय है?

समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था इंगलैंड सहित अन्य देशों में है। चाहे राजा का या रंक का एक ही विद्यालय में पढ़ेगा। सरकार एक साजिश के तहत यह प्रणाली लागू नहीं कर रही है। समान शिक्षा लागू होते ही उनके मंत्री, नौकर शाह सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। कारण की उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ना पड़ेगा। उनके चाटुकार मंत्री, विधायक, नौकरशाह कभी नहीं चाहेंगे। सरकार भी यही चाहती है कम से कम पाटी के लिए झंडा ढोने, दंगा कराने जैसे सत्कर्म भी तो वे ही करेंगे न कि कान्वेंट में पढ़ने वाले अफसरों, मंत्रियों के रईसजादे।

☆ सरकार की वर्तमान योजनाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे?

सरकार की जितनी भी योजनाएँ कार्यान्वित हो रही है, एक-दो को छोड़ सभी शिक्षक-छात्र व अभिभावकों के लिए परेशानी का सवब बना हुआ है। बानगी के रूप में खाता खुलवाना, छात्रवृति के लिए नाना प्रकार स्वांग कराती है। प्रतिमाह अरबों रूपये कागजी घोड़े दौड़ाने में खर्च होता है। कभी खुद किताब देती है, तो कभी बाजार से तो अब खाते में पैसा नित्य इसी तरह का नौटंकी आम हो गया हे।

प्रश्नः क्या सरकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर रही है? यदि हाँ तो आपका क्या विचार है?

उत्तरः पत्रकार महोदय, सरकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का खुला उल्लंघन कर रही है, जबकि समान कार्य समान वेतन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। आखिर इस विसंगति का शिकार किसने बनाया? यह एक ज्वलंत प्रश्न है। सरकार अपने विधायकों का वेतन प्रत्येक साल अप्रत्याशित रूप से बढ़ा देती है, लेकिन शिक्षकों के वेतन के मामले में सीने पर साँप लोटने लगता है। विधायक, सांसद जो पाँच साल के लिए आते हैं, उनहें पेंशन चाहिए और जो 60 साल सेवा देता है, उसे पेंशन नहीं। ऐसी दोगली सोंचवाली सरकारों को शर्म नहीं आनी चाहिए। ऐसे में बढ़ते बिहार का सपना देखना पत्थर पर दूब उगाने के बराबर है।

प्रश्नः केवल सच राष्ट्रीय मासिक पत्रिका की ओर से शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

उत्तरः महोदय, सर्वप्रथम केवल सच को उसकी बेबाकी, निर्भीकता और 100% सत्य लिखने के लिए साधुवाद! संदेश के रूप में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि -

"कमजोर नहीं है इतना हम, दुनियाँ को दिखलायेंगे
शिक्षकों की ताकत का, अबकी अहसास करायेंगे।

अपराध नियंत्रण व जनता से बेहतर संबंध कायम रखना हमारी प्राथमिकता : बिपिन कुमार

● आनन्द प्रकाश पाण्डेय/अशोक तिवारी

सामान्यतः किसी अपराध के घटने में पुलिस को दोषी बताकर उसे कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन क्या बाकई में सारा दोष अकेले पुलिस के सिर मढ़ दिया जाना उचित है? क्या अपराधों के घटना में समाज और शासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता? इस प्रश्न के उत्तर की जड़ें दूर कहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। परंतु आज बढ़ते हाइटेक अपराधों के कारण जनता भयाक्रांत है। पुलिस का कर्तव्य है कि वह जनता को भयमुक्त करें। लेकिन हमारी बहुत-सी सरकारें आज भी पुलिस का इस्तेमाल जनता की सुरक्षा से ज्यादा अपने लाभ के लिए कर रही है। पुलिस का काम दिनानुदिन कठिन होता जा रहा है और जनता की सेवा करने में आये दिन उनके सामने नई-नई चुनौतियाँ आ रही है। इसके बावजूद पुलिस महकमा हर चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए जनता के कल्याण का कार्य कर रही है। पुलिस को शांति-व्यवस्था का कार्य सौंपकर समाज ने उन्हें पुनीत कर्तव्य सौंपा है और इस कर्तव्य का निर्वहन पवित्र भावना से करनी आवश्यक है। विदित हो नव पदास्थापित थानाध्यक्ष भगवानपुर हाट बिपिन कुमार ने केवल सच टीम को बातचीत के क्रम में बताया कि पुलिस-पब्लिक संबंध कायम रखना व अपराध पर नियंत्रण मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। हमारा यही प्रयास रहेगा कि जनता से बेहतर संवाद कायम हो। विपिन कुमार ने आगे बताया कि यहाँ भूमि विवाद, की अधिकता है ऐसे विवादों ठीक ढंग से आपसी मेल-मिलाप के द्वारा निपटारा किया जायेगा। अंत में केवल सच राष्ट्रीय मासिक पत्रिका के माध्यम से नव पदास्थापित थानाध्यक्ष ने लोगों को यह संदेश दिया कि सच्चाई के मार्ग पर अपने परिवार के लिए, समाज के लिए निष्ठापूर्वक कार्य को अंजाम दे, समाज के मुख्यधारा से कभी विमुख न हो, जीवन में संतोष का स्थान दें, लालच नहीं करें। हमेशा एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग की भावना रखें। पुलिस पर भरोसा रखें। हम सभी आपकी सेवा में तत्पर हैं।●

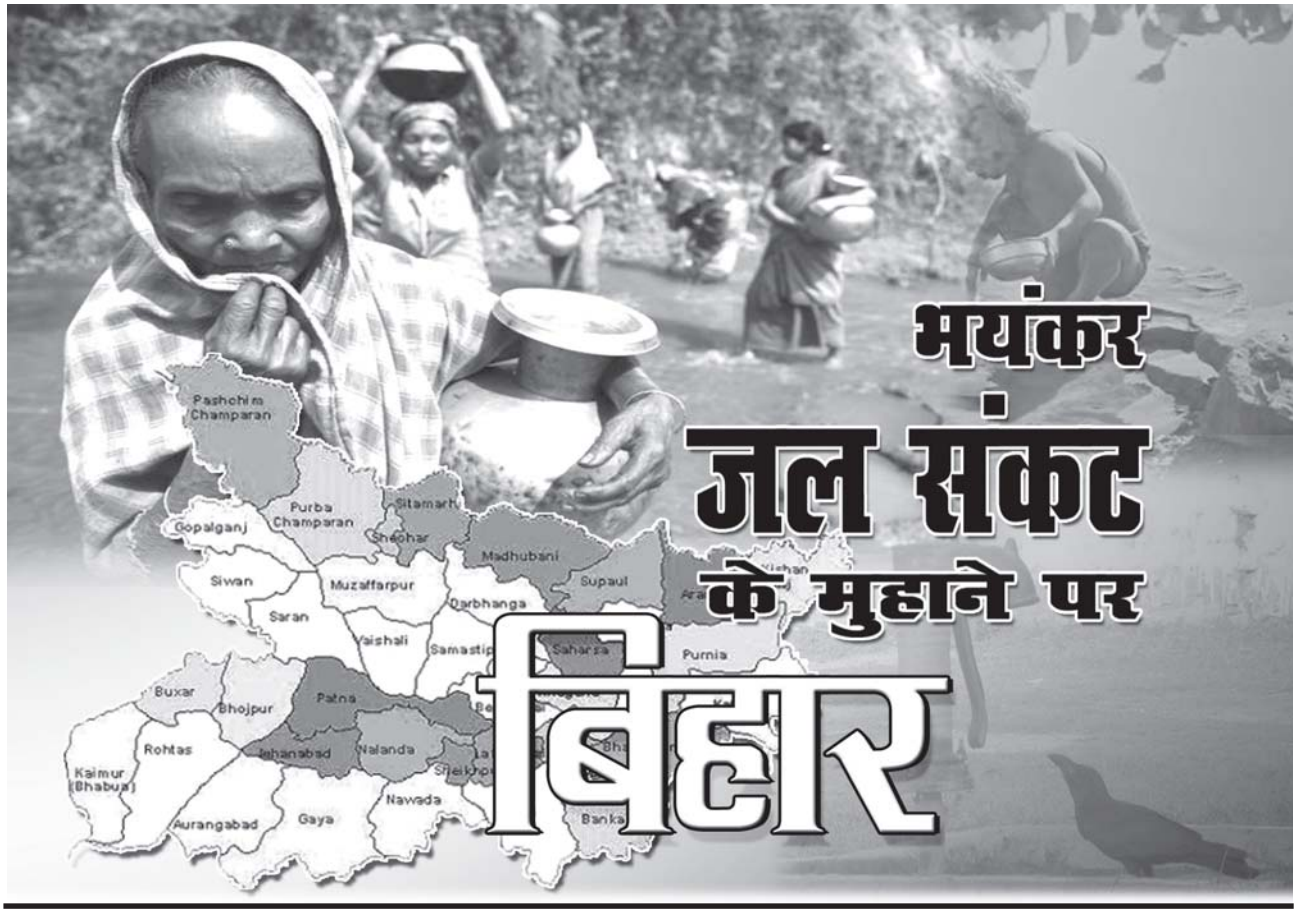

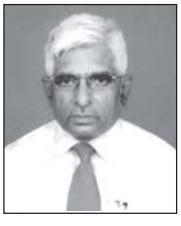

● **ललन कुमार प्रसाद**

तथ्य की शुरूआत तो 15 अगस्त 1947 से किया जा रहा है, जब देश आजाद हुआ था। लेकिन, बिहार के उतने ही रकवे की बात की जा रही है, जितना 15 नवम्बर 2000 को बिहार से अलग कर दिये गये झारखण्ड राज्य का गठन हुआ था। ऐसा इसलिए की पाठक यह न समझे की मैं एक लाख 73 हजार 877 वर्ग किलोमीटर रकवा मानकर चल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ 94 हजार 163 वर्ग किलोमीटर रकवा मानकर चल रहा हूँ। इसमें झारखण्ड का 79 हजार 714 वर्ग किलोमीटर का रकवा शामिल नहीं है। भारत में कभी बिहार की पहचान यहां की कुल जल संपदा को लेकर होती थी। इस राज्य में नदियों, तालाबों और नहरों का जाल बिछा है। आजादी के समय इस राज्य में छोटी-बड़ी करीब 350 नदियां थी, जिनमें से करीब 270 नदियां सूख गई हैं, बरसाती बन गई है, कइयों का वजूद मिट गया है और कइयों का वजूद मिटने के कगार पर है। 8-9 मुख्य नदियों से जुड़ी 250 के करीब जलधाराओं का मिट जाना उत्तरी बिहार के इलाके के लिए चिंता का विषय है। दरअसल अंग्रेजों के समय से ही लोगों के मन में नदियों के खिलाफ गलत धारणाएं पैदा की जाने लगी थी। मसलन नदियों की वजह से बाढ़ आती है और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इस बात को ध्यान में रखकर 1950 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण निति बनाई गई। इस निति के तहत आनन-फानन में कोशी, कमला बलान, बागमती, महानंदा और बूढ़ी गंडक के दोनो तरफ तटबंध (बांध) बनाने का काम शुरू कर दिया गया। नतीजा इन बड़ी नदियों को सहायक नदियों, जल-धाराओं और छाड़न से सम्पर्क खत्म हो गया और यह सारी नदियां बरसाती नदियां बनकर रह गई। सालों भर पानी के प्रवाह के आभाव में इन नदियों के किनारे अतिक्रमण को बढ़ावा मिल गया और इन्हें पाटकर खेतों और मकानों में तब्दील किया जाने लगा। यह प्रकृति के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ करने का नतीजा है। इस राज्य में 8 जल-प्रपात तथा 10 जलकुण्ड या झरने हैं। इस राज्य में क एक लाख 98 हजार 452 है। जिनमें से 44432 सरकारी और एक लाख 54 हजार 20 प्राइवेट। अब इस राज्य में 80 हजार से भी कम तालाब रह गये हैं। मसलन पटना शहर को कभी तालाबों का शहर कहा जाता था। 1950-60 के दशक में पटना शहर में तालाबों की संख्या 104 थी, अब घटकर एक दर्जन से भी कम रह गई है। पटना सिटी का मंगल तालाब शहर का सबसे बड़ा तालाब है। इसके अलावा अनिशाबाद स्थित मानिकचंद तालाब और गर्दनीबाग स्थित कच्ची तालाब प्रमुख है। पुराना सचिवालय परिसर के अंदर पीछले गेट के समिप स्थित तालाब और पटना म्यूजियम के पीछे पटना आर्ट कॉलेज के पूरब में स्थित तालाबों की बंदोबस्ती मछली पालन हेतु मतस्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जाता है। पटना-गया रोड, जिसे बुद्ध मार्ग कहते हैं, इसी रोड के किनारे स्थित सेन लेबोरेट्री के सामने से एक रोड निकलती है जो गार्डेनर रोड में जुड़कर समाप्त हो जाती है। इसी जोड़ने वाली रोड के किनारे

अदालतगंज तालाब अवस्थित है।

देश भर में तालाबों के खात्में के पीछे सरकार और समाज दोनो ही जिम्मेदार हैं। लेकिन सरकार ज्यादा जिम्मेदार हैं- चाहे केन्द्र की हो या राज्य की। तालाबों के खात्मे का सबसे बड़ा कारक सरकारी नितियां और कुछ सरकारी मुलाजिम हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारक कुछ मंत्री, विधायक, सांसद, नेता, रसूक वाले लोग, दबंग और भू-माफिया के लोग हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारक जनता के पैसों पर ऐसोआराम की जिंदगी बसर करने वाले कुछ सरकारी मुलाजिम। चौथा सबसे बड़ा कारक है देश की बेतहाशा बढ़ती आबादी, अज्ञानता और निजी स्वार्थ। बेतहाशा बढ़ती आबादी को एकोमोडेट करने के लिए तालाबों को मिट्टी से भरकर रिहायशी इलाके बनाये गये हैं तथा खेतों का विस्तार किया गया है, जो आज भी जारी है। अर्थात जो तालाब और पोखर बच गये हैं, उन पर भी अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। आश्चर्य की बात है कि कोई भी कारक कुदरती नहीं है, सब के सब मनुष्यों द्वारा पैदा किए गये हैं। फिर आजादी के पहले तालाबों को सबसे बड़ा जल संसाधन माना जाता था, लेकिन बहुत दुख की बात है कि आजादी के बाद से सरकारी भाषा में तालाबों को जल संसाधन नहीं माना जाने लगा है। तभी तो केन्द्र तथा राज्य सरकारें तालाबों को अधिग्रहित कर तालाबों के जमीन पर इमारते खड़ी करने लगी है, सड़के बनवाने लगी है, पार्क बनवाने लगी हैं। सरकारी तालाब तो सरकार का ही है, उसे अधिग्रहित करने में कोई परेशानी नहीं होती है और ना ही किसी को कोई मुआवजा देना पड़ता है। आज हमारे देश में डरावने जल संकट का बहुत बड़ा कारण तालाबों का अस्तित्व समाप्त हो जाने से पैदा हुआ है। ऐसा इसलिए की तालाबों की भारी कमी के कारण वर्षा जल का सिर्फ 8 फिसदी हिस्सा हम सहज पाते हैं और शेष 92 फिसदी पानी बहकर नालों से होते हुए नदियों में चला जाता है।

इस राज्य में 12 नहरे हैं। जिनसे कई शाखाएं और उपशाखाएं निकली है। कुल मिलाकर इन सभी नहरों की सिंचाई क्षमता करीब 33 लाख हेक्टेयर भूमि है। पूर्वी कोसी नहर की चार शाखाएं हैं-मुरलीगंज (64 किमी०), जानकी नहर (82 किमी०), पूर्णिया (64 किमी०) और अररिया (58 किमी०)। इस नहरों के कुछ उपशाखाएं हैं। इन चार शाखाओं और उपशाखाओं को मिलाकर पूर्वी कोशी नहर की लम्बाई 3040 किलोमीटर है। गर्मियों में अब तो कई जिलों की नहरें सूखी पड़ी रहती है। लालगंज, वैशाली और हाजीपुर प्रखण्ड से गुजरने वाली नहरे गर्मियों में सूखी पड़ी रहती है। सूखी पड़ी रहने के कारण बेगूसराय से गुजरने वाली नहर में मकान बना दिये गये हैं। वर्तमान में कुछ नहरों का वजूद मिट गया है और कई नहरों का वजूद मिटने के करीब है। यह तथ्य पिछले साल ही प्रमाणित हो गये। इस राज्य में सप्तधारा या सतधरवा, ब्रह्मकुण्ड, सूर्यकुण्ड, नानक कुण्ड और मखदुम कुण्ड नामक प्रमुख जलकुण्ड हैं। जिनका उद्गम स्थल राजगीर है। इस राज्य में गोमुख कुण्ड, लक्ष्मण कुण्ड, सिताकुण्ड, रामेश्वर कुण्ड और ऋषि कुण्ड नामक प्रमुख जलकुण्ड भी है, जिनका उद्गम स्थल मुंगेर है। बिहार के प्रमुख जल-प्रपात है-सुखलदरी जलप्रपात, परसाडीह जलप्रपात, तमासीन जलप्रपात, गुरसिन्धु जलप्रपात, मालूदह जलप्रपात, केरीदह जलप्रपात, गोवा जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात, इत्यादि। यह सभी जलप्रपात बिहार के बिहार के गया, रोहतास और नवादा जिलों में पड़ते हैं। नवादा से 35 किलोमीटर दूर स्थित काकोलत जलप्रपात बहुत ही प्रसिद्ध है।

जल प्रपातों का निर्माण उन नदियों के मार्ग में होता है, जिनके तल में कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्रमबद्ध स्थिति में होती है। अर्थात् विशेष भगौलिक परिस्थिति में जल प्रपातों को जन्म नदियां ही देती है। नदी तल का ढ़ाल किसी स्थान पर एकाएक तीव्र हो गया हो या उर्धवाधार हो और नदी के जल का जो अंश तीव्र वेग से गिरने लगे तो उस अवस्था को जलप्रपात कहते हैं। बिहार के जलप्रपातों में जल की मात्रा लगातार घटती ही जा रही है। ऐसा इसलिए की नदियों में जल की मात्रा लगातार

गंगा के पाट की चौड़ाई (किलोमीटर में)

वर्ष	सुल्तानगंज	भागलपुर	कहलगांव	नारायणपुर	बिहपुर	कुरसेला
1990	3.60	3.40	2.26	11.10	3.05	4.30
2001	2.93	2.83	1.91	5.28	2.00	4.25
2006	2.08	2.58	0.82	1.65	2.00	3.35

कम होती जा रही है। दरअसल नदियां, जिनका उद्‌गम स्थल पठार हो और पठारों पर घने जंगल कम होने लगे तो वहां से निकलने वाली नदियों में भी जल की मात्रा कम होने लगती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव जल प्रपातों पर पड़ता है, क्योंकि इनका जन्म नदियों से ही हुआ है।

इस राज्य में अनेक बांध है। बिहार की मिट्‌टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्‌टी मानी जाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि बिहार की मिट्‌टी सोना उगलती है। सिर्फ सतह ही नहीं, भू-जल भंडार के मामले में भी बिहार देश का सर्वाधिक समृद्ध राज्य है। फिर राज्य में सालाना औसतन 1027 मिली मिटर वर्षा होती है। इस राज्य में प्राकृतिक व कृत्रिम तथा सतही व भू-जल स्त्रोतों का वृहत भंडार है। अर्थात् भगौलिक संरचना और रकवा की दृष्टि से यह भारत का एक ऐसा राज्य है, जहां पानी की थोड़ी सी भी कमी की कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर भी बिहार राज्य को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। पीने के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए और रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी की भारी कमी से जुझना पड़ रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार देश का एक कृषि प्रधान राज्य। अकूत जल संपदा ही तो बिहार की ताकत रही है, क्योंकि कृषि की जान पानी है। लेकिन, दुख की बात है कि बिहार में अब पानी की भारी कमी हो गई है। पानी की कमी के चलते हमारी खेती-किसानी चौपट हो गई है। खनिजों और उद्योगों के आभाव में बिहार पहले से ही गरीब है। अब तो पानी की भारी कमी के चलते बिहार कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। बिहार की खेती योग्य 54 लाख हेक्टेयर भूमि में से 9.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को छः महीने पानी से मुक्ति की छटपटाहट रहती थी, जो उत्तरी बिहार में पड़ती है। कभी 206 जल धाराएं नेपाल से उत्तरी बिहार में प्रवेश करती थी लेकिन आज की तारीख में उनमें से 160 अस्तित्व में नहीं है। अर्थात् नेपाल से उत्तरी बिहार में प्रवेश करने वाली 80 फिसदी जल धाराओं का अस्तित्व मिट गया है। पिछले 24-25 वर्षों में नेपाल के सघन वन क्षेत्रों में आयी कमी के चलते बारिस में आयी कमी के साथ-साथ जल संग्रहण और जल संरक्षण की मात्रा में भी भारी कमी आयी है। दरअसल, नदियों में पानी की आपूर्ति ग्लैशियर और सघन वन, दोनो मिलकर करते हैं। लेकिन, जिन नदियों में पानी की आपूर्ति पठारों और पहाड़ियों के घने जंगलों से होती है, यही वहां के सघन वन क्षेत्रों में कमी आ जाये तो नदियां सुखने लगती है। जब नदियां सुखने लगती है जल-प्रपात भी सुखने लगते हैं। ऐसा इसलिए कि जल-प्रपातों को पानी की आपूर्ति नदियों से होती है। सघन वन क्षेत्र में आयी कमी के चलते ना केवल नदियां सुखने लगती है, बल्कि तालाब भी सुखने लगते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सघन वन क्षेत्र का मतलब क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार वन क्षेत्र तीन प्रकार के होते हैं-सघन वन क्षेत्र, मामूली वन क्षेत्र और खुला वन क्षेत्र। सघन वन क्षेत्र वे होते हैं, जिनमें 70 फिसदी से अधिक वृक्षछत्र यानि कैनोपी होती है। 40 फिसदी से लेकर 70 फिसदी तक के वृक्षछत्र वाले वन मामूली घने वनों और 10 फिसदी से 40 फिसदी तक वृक्षछत्र वाले वन खुले या छितरे वनों की श्रेणी में आते हैं। दरअसल, यही सघन वन यानि घनघोर जंगल वनजीवों के असली आश्रयदाता हैं। इन घने वन क्षेत्रों के नीचे एक भरापूरा वन जीव संसार

फलत-फूलता है।

जहाँ वन होते हैं, वहां वृक्षों से जमीन पर गिरी पत्तियां, छाल, छोटी-छोटी टहनियां, फल-फूल आदि बहुत अधिक होते हैं, जो अपघटित होकर मिट्‌टी की भौतिक दशा सुधारते हैं। मिट्‌टी की सांध्रता (पोरोसिटी) बढ़ा देते हैं। इस कारण अधिक मात्रा में वर्षा का पानी रिस-रिसकर जमीन के भीतर चला जाता है, जिससे भू-जल की बढ़ोत्तरी होती है। भू-जल का स्तर ऊपर उठता है और नदियों तथा तालाबों में पानी की आपूर्ति होती है। मसलन, हिमाचल प्रदेश के फर, स्प्रूस और देवदार के वृक्षों में किए गये अध्ययन से पता चला है कि वहां प्रथम दस मिनटों में 38. 0 से 44.8 सेंटी मिटर प्रति घंटे की दर से वर्षा का पानी जमीन में अंदर चला जाता है, जबकि बिना जंगलों वाले स्थानों पर यह दर केवल 18 सेंटीमीटर प्रति घंटे हैं। जमीन के अंदर वृक्षों की ढ़ेर सारी लंबी-लंबी जड़ों में लंबे समय तक पानी को संचय करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि वृक्ष लगाना लंबे समय तक पानी को संग्रहित और संरक्षित रखने का बहुत ही असरदार साधन माना गया है। वर्षा का पानी जब वृक्षों पर गिरता है तो उसका अधिकतर भाग जमीन पर आ जाता है। परन्तु कुछ भाग तो पत्तियों, शाखाओं आदि पर ही रह जाता है, जो वाष्पीकरण द्वारा वातावरण में वापस लौट जाता है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्रकार के जंगलों में किये गये अध्ययन से पता चला है कि देवदार के वन कुल वर्षा का 25 फिसदी, कैल के वन 29 फिसदी और बान के वन 17 फिसदी वर्षा का पानी वापस वातावरण में लौटाने की क्षमता रखते हैं। फिर सघन वन जमीन की सतह से पानी के भाप में तब्दील होने की प्रक्रिया को 50 फिसदी तक

बिहार की प्रमुख नहरें

नहर के नाम	उद्गम स्थल	नहर की लम्बाई (कि०मी० में)	सिंचाई की क्षमता (लाख हेक्टेयर में)	सिंचाई का क्षेत्र
पूर्वी सोन	बारून (सोन नदी का दाहिना किनारा)	130	2.5	पटना व गया जिला
पश्चिमी सोन	टेहरी (झारखण्ड)	---	3.0	आरा, बक्सर और चौसा
त्रिवेणी	त्रिवेणी (पं. चम्पारण)	---	1.0	---
कमला	कमला नदी (उत्तरी भाग)	---	---	मधुबनी जिला
पूर्वी कोसी	हनुमान नगर जलाशय के बांये किनारे	44	6.0	पूर्णिया व सहरसा जिले
पश्चिमी कोसी	हनुमान नगर जलाशय के दांये किनारे	115	3.0	दरभंगा जिला
राजपुर	---	---	1.60	मुंगेर व सहरसा जिले
तिरहुत	वाल्मिकी नगर जलाशय	---	4.8	सारण जिला
सारण	वाल्मी नगर जलाशय	---	6.9	पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा
ढ़ाका एवं तेऊर	ललवाकिया नदी एवं तेऊर नदी	---	2.5	पूर्वी चम्पारण
सकरी	---	---	---	मुंगेर, गया और पटना

कम कर देते हैं, जिससे भूमि की नमी सालों भर बनी रहती है। एक वृक्ष सालभर में दो हजार लिटर पानी धरती में संग्रहित और संरक्षित कर देता है। सघन वनों के वृक्षों के चलते वर्षा जल का 50 फिसदी पानी संग्रहित और संरिक्षत हो जाता है। यही कारण कि सघन वन वर्षा के पानी का संग्रहित व संरक्षित कर नदियों में पानी की आपूर्ति करते हैं और तालाबों को सुखने से बचा लेते हैं। नतीजा बिहार की 350 छोटी-बड़ी नदियों में से 270 नदियां सूख गई है, बरसाती बन गई है। अर्थात् बिहार की छोटी-बड़ी 270 नदियां मार्च आते-आते सूख जाती है, बरसाती बनकर रह जाती है। बरसात में इन नदियों में अच्छी खासी मात्रा में पानी रहता है। अर्थात् बिहार की लगभग अच्छी फिसदी नदियों का वजूद मिट गया है। सिर्फ छोटी-बड़ी 70 नदियों का वजूद है। इन 70 में से कई नदियों का वजूद मिटने के कगार पर है। कभी 8-9 लाख क्यूसेक जल प्रवाह देख चूकी कोसी नदी में पिछले 26-27 वर्षों में 4 लाखर क्यूसेक पानी का बहाव रह गया है। मधुबनी-सुपौल आदि जिलों में बहने वाली तिलयुगा नदी कोसी से भी बड़ी नदी थी, लेकिन आज यह कोसी की सहायक नदी बनकर रह गई है। पानी की मात्रा में आयी भारी कमी के चलते गंगा नदी भी काफी सिकुड़ गई है। अर्थात गंगा का पाट काफी कम हो गया है। महज 26-27 वर्ष पहले उत्तर बिहार में बगहा से लेकर किशनगंज के आखिरी सिरे तक 470 किलोमीटर की लम्बाई में फैले इलाके में लगभग हर दूसरे-तीसरे किलोमीटर की दूरी पर कोई न कोई छोटी या बड़ी नदी मिल जाया करती थी। लगभग 882 छोटी नदियां गंगा, गंडक, बुढ़ी गंडक और कोसी में मिलती थी। कोसी, कमला बलान, बागमती, घाघरा, फल्गु और बुढ़ी गंडक ऐसी नदियां है, जो एक साथ कई-कई धाराओं में बहती है। श्री हलधर त्रिपाठी सहृदय ने अपनी किताब ''बिहार की नदियां'' में जिक्र किया है कि कोसी नदी की 31 धाराएं थी-बेती-घेमुरा, पुरइन, तिलावह, सोनेह, परवाने, चिलौनी धार, सुरसर धार, हइया धार, कोदई-गुलेला, गेरूआ-कमताहा, गोरेभगड़, चकरदाहा, नागर, हिरन, लिबरी, कारी कोसी और सौरा धार। बूढ़ी गंडक की 15 धाराएं थी- हरहा, कापन, मसान, रामरेखा, वाणगंगा, पंडई, धारम, करहटा, उरई, कोनहरा, झरही, तलाबे, तियर, अनुरवा और धनौती। कमला बलान की 10 धाराएं थी-कमला बाछराजा, जीवछ कमला, पैठघाट कमला, सोनी, धौड़ी, बलान और अन्य चार धाराएं। गंडक की

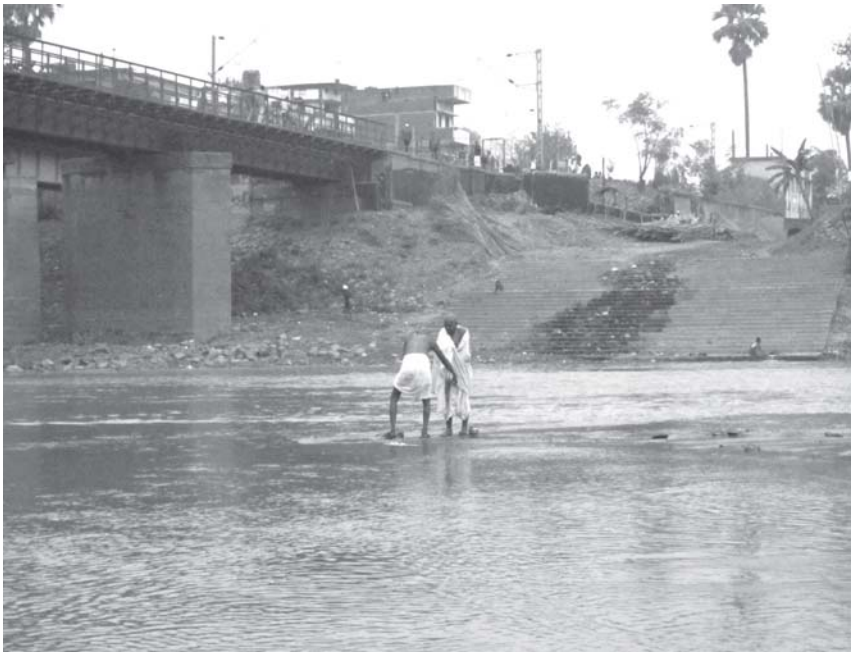

7 धाराएं थी-कुसुमा, बरिगड, त्रिशुली, वृद्ध गंडकी, मर्सिय गंडी, दारा मार्दी गंडी और सेती गंडकी। बागमती की 6 धाराएं थी-लालबकेया, चकनाहा, सिपरी धार, छोटी बागमती, कोला और लखनदेई। करेह की 9 धाराएं थी-अवधारा, हरदी, मरने, बघोर, मुरहा, धाउस, बेलौती, जमुने और थोमने। घाघरा की 13 धाराएं थी-वासिष्ठी, ठुलाभेरी, सेती, भेरी बवई, शारदा, मनोरमा, कुटिला, कुवानो, राप्ती, छोटी गंडक, झरही और दाहा। पुनपुन की 7 धाराएं थी-आद्री, मादर, बिलारो, नेरा, सिनेने, पंगछारा और मुरहर। फल्गु की 9 धाराएं थी-निरंजना, सरस्वती, मोहाने, सूनर, भुरभुरी, मनसिंघी, ननयांग, जलवार और पेंगवार। महानंदा की 6 धाराएं और इसी तरह कियूल, चानन, अंजना, सोन आदि नदियों की कई धाराएं थी।

★ सूख गयी मोझदायिनी फल्गु नदी :- वेद में फल्गु नदी को गंगा नदी की तरह पवित्र माना गया है। फल्गु नदी का महत्व पितृमोझ से जुड़ा है। देश-दुनियां के सनातन धर्मावलम्बियों की आस्था का केन्द्र इस पवित्र फल्गु नदी में आज स्नान और तर्पण के लिए पानी नहीं है, लेकिन एक समय था, जब गया के बड़े भू-भाग की सिंचाई इस नदी के पानी से होती थी। दक्षिण बिहार के गया शहर में ऐतिहासिक नदी फल्गु में लाखों लोग प्रति वर्ष अपने पित्रों की मुक्ति के लिए तर्पण करते हैं। खासकर पितृपक्ष के दौरान यहां मेला लगा रहता है। विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के अनुसार प्रति वर्ष करीब 25 लाख तीर्थयात्री गया धाम में पित्रों को मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से कर्मकाण्ड करने आते हैं। जिसके लिए पिण्डदानियों को फल्गु का पांच रूपये में एक ग्लास पानी या एक चुक्का पानी खरीदना पड़ता है। दरअसल, फल्गु नदी का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। करीब दस से बारह फूट खोदे जाने के बाद अंत:सलिलि फल्गु का पानी निकलता है। जिला प्रशासन की ओर से देवघाट पर कुण्ड नहीं खोदा गया है। ऐसे में स्थानीय लोग काफी मेहनत से 10 से 12 फूट गड्ढ़ा खोदकर फल्गु नदी का पानी निकालते हैं। इसलिए वे फल्गु के पानी को पांच रूपये ग्लास या चुक्का बेचते हैं।

अब प्रश्न उठता है कि कभी फल्गु नदी से गया शहर के बड़े भू-भाग की सिंचाई की जाने वाली यह नदी सूख कैसे गयी? तथ्य यह है कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। जहां पहले घना जंगल हुआ करता था। बारिस होने के बाद उसके एक तिहाई पानी का अवशोषण जंगल के पेड़ों की जड़े कर लेती थी। इसके साथ बारिस का पानी जमीन के अंदर भी जाता था। जंगल के पेड़ अवशोषित पानी को तीन महीने बाद जमीन में छोड़ते थे। यही पानी फल्गु नदी में आता था। अब हालात बदल गये हैं। विकास के बहाने पठार पर मौजूद पेड़ काटे जा चुके हैं। इस कारण बारिस का पानी अवशोषित होने के बजाय पठारों से नीचे की ओर बह जाता है। जल संचय नहीं हो पाता है। यही कारण है कि सिर्फ बारिस के समय ही थोड़ा पानी फल्गु नदी में दिखता है।

★ पुनपुन नदी में पानी बहुत कम रह गई है :- पुनपुन नदी भी पवित्र नदी मानी जाती है। इसलिए इसके किनारे कई धार्मिक संस्कार होते हैं। कहा जाता है कि इसमें स्नान और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है तथा उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। खासकर गया जाने के पहले हिन्दू तीर्थयात्री यहां आकर अपना सिर मुंडवाते हैं, स्नान करते हैं और पूजा-पाठ करते हैं। कभी इस नदी में सालों भर पानी रहता था और नावें चलती थी। इसका अधिकांश पानी नहर के रूप में निकालकर सिंचाई के काम में आता था। लेकिन अब नदी में पानी बहुत ही कम रहता है। गंगा नदी की सहायक नदी है पुनपुन नदी। यह कुरथा में गंगा से मिलती है और पटना की पूर्वी सीमा बनाती है। आज पुनपुन नदी में पानी के कई कारण है। पहला कारण है कि इसका उद्गम किसी ग्लैशियर से नहीं हुआ है। यह झारखण्ड राज्य के हजारीबाग और पलामू जिले के पठारी भाग से निकलती है, जहां पहले घने जंगल हुआ करते थे। जिसके चलते बारिस का पानी वहां संग्रहित हो जाता था। वही पानी धीरे-धीरे नदी में आता रहता था, जिससे सालों भर नदी में पानी का प्रवाह बना रहता था। लेकिन सघन जंगलों कें खत्म हो जाने यानि बड़ी संख्या में पेड़ों की कमी हो जाने के कारण अब वहां जल संग्रहित नहीं हो पाता है। इस कारण हजारीबाग और पलामू के पठारों से पुनपुन नदी में सतत रूप से पानी नहीं आ पा रहा है। साथ ही इस नदी के रास्ते में छोटी-छोटी बरसाती नदियां मिलती थी, ऐसा अब नहीं हो पा रहा है। तीसरा पिछले चार वर्षों में मानसून औसत से कम बरस रहा है। बिहार में समान्यत: 1027 मिलीमीटर बारिस सलाना होती थी, जो वर्ष 2014 में 17 फिसदी कम यानि 847 एम.एम. बारिस हुई और वर्ष 1915 में 27 फिसदी कम यानि 745 एम.एम. बारिस हुई।

★ सोन नदी :- सोन नदी का उद्गम स्थल गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मेकल पर्वतमाला का अमरकंटक स्थान है। पहले यहां जंगल बहुत था। यह नदी झारखण्ड के पलामु जिले से होते हुए एक विशाल नदी के रूप में बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के रोहतास, औरंगाबाद और भोजपुर जिला होते हुए पटना जिला में प्रवेश करती है। पटना शहर से पहले दानापुर से 16 किलोमीटर दूर गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी में सालों भर बड़ी-बड़ी ढ़ेर सारी नावें चला करती थी, लेकिन अब इस नदी में बहुत ही कम ही पानी रहता है। अमरकंटक के मेकल पर्वतमाला और झारखण्ड के पलामू जिले के पठारी भाग में पहले घने जंगल हुआ करते थे, जिसके चलते बारिस का पानी वहां संग्रहित हो जाता था। वही पानी धीरे-धीरे नदी में आता था, जिससे सालो

भर पानी का प्रवाह बना रहता था। लेकिन सघन जंगलों के खात्मा होने के कारण पानी वहां संग्रहित नहीं हो पाता है। इस कारण सोन नदी में सतत रूप से पानी नहीं आ पा रहा है। साथ ही इस नदी के रास्ते में छोटी-बड़ी जो बरसाती नदियां मिलती थी, ऐसा अब नहीं हो पा रहा है। तीसरा पीछले कुछ वर्षों से मानसून औसत से कम बरस रहा है।

☆ सूख गई है सोन, बिन पानी की हो गई है पुनपुन :- पटना शहर के भू-जल का खजाना यानि जलोढ़, जिसमें भू-जल का पानी भरा रहता है, वह गंगा से नहीं, सोन और पुनपुन नदियों पर टिका हुआ है। यह ठीक है कि पटना शहर तीन तरफ से तीन नदियों-गंगा, सोन और पुनपुन से घिरा हुआ है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के वैज्ञानिक बताते हैं कि इन तीन नदियों का निचला स्तर जलोढ़ से मिलता है, लेकिन सोन और पुनपुन का आंतरिक जल-प्रवाह पटना शहर के भू-जल को रिर्चाज करता है। परन्तु इन दोनो नदियों में अब नाम मात्र का पानी बचा है। इन दोनो नदियों की आंतरिक जलधारा तो न जाने कब की टूट चुकी है। इसके चलते पटना शहर का भू-जल ठीक से रिर्चाज नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं गंगा नदी में पानी की मात्रा में 86 प्रतिशत की कमी हो जाने की वजह से गंगा नदी खुद को इसी जलोढ़ से रिर्चाज करती है। हालांकि वैज्ञानिक बताते हैं कि पटना शहर के नीचे स्थित जलोढ़ में पानी की कमी नहीं है, लेकिन यदि पटना शहर के लोग भू-जल का अंधाधून दोहन बंद नहीं करेंगे तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग द्वारा भू-जल को ठीक से रिर्चाज नहीं करेंगे तो निकट भविष्य में कुछ ही वर्षों के बाद पटनावासियों को भू-जल की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा।

बिहार, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत का एक बड़ा इलाका सूख ही रह गया है। बुंदेलखण्ड और महाराष्ट्र का सूखा तो किसानों के आत्माहत्या का वजह बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45 फिसदी, बिहार में 44 फिसदी, झारखण्ड में 40 फिसदी और पश्चिम बंगाल में 24 फिसदी कम बारिस हुई है। नतीजा, बिहार के 38 जिलों में से 30 जिलों के 277 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है। एकडंगा पंचायत के 25 गांवों की 500 हेक्टेयर जमीन प्यासी ही रह गई है। नतीजा सरकारी अनुमान के अनुसार बिहार में इस बार 17 लाख टन धान कम पैदा हुआ है, जिससे 2800 करोड़ रूपये के नुकसान पहुंचने की आशंका व्यक्त की गई है।

☆ पटना शहर के भू-जल की स्थिति :- पटना शहर में तीन स्तरों पर भू-जल उपलब्ध है। इनमें ऊपरी सतह की गहराई 30 से 40 मिटर यानि 100 से 200 फीट है। समान्यत: बोरिंग और हैंडपम्प 60 से 200 फीट की गहराई में लगाये जाते हैं। गर्मी के दिनों में 60 से 120 फिट की गहराई से जुड़े बोरिंग और हैंडपम्प सूख जाते हैं। इस लेयर में पानी का घटना-बढ़ना वर्षा के पानी पर निर्भर करता है। शहर में शुद्ध भू-जल का स्तर करीब 120 से 140 फिर की गहराई में पहुंच गया है। इसके बाद पानी का बीच वाला लेयर 60 से 120 मिटर यानि 200 से 400 फिट की गहराई तक है, जो सूखता नहीं है। लेकिन गर्मी के मौसम में इस लेयर से पानी के दोहन की क्षमता में कमी आ जाती है। निचले लेयर की गहराई 120 से 200 मिटर है। यानि 400 से 700 फिट, जिसमें समान्यत: पानी हमेशा ही बना रहता है।

पटना के शहरी और ग्रामीण इलाकों में आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिससे भू-जल का दोहन तेजी से बढ़ रहा है। पटना शहर की आबादी 1971 से 2011 के बीच 6. 5 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गई और अब तो करीब 26 लाख हो गई है। पहले जहां लोग कुंआ और नगर निगम द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले पानी पर निर्भर थे, अब हर घर में समरसेबुल पम्प से भू-जल का दोहन किया जा रहा है, जो उस समय से दसगुणा अधिक बढ़ गया है।

पटना शहर में धरती की कोख से अंधाधूंध भू-जल का दोहन हो रहा है। शहर में नगर निगम की 117 बोरिंग चलायी जा रही है। इनमें से 30 में 100 हॉर्सपावर के और शेष में कुछ में 75 हॉर्सपावर और कुछ में 60 हॉर्सपावर के मोटर लगे हुए हैं। 100 हॉर्सपावर वाले बोरिंग से एक घंटे में 60 हजार गैलेन यानि 8 लाख 10 हजार लिटर पानी निकाले जा सकते हैं। प्रतिदिन नगर निगम के बोरिंग से कई करोड़ लिटर पानी निकाले जा रहे हैं। फिर लाखों निजी बोरिंग से प्रतिदिन कितना पानी निकाला जा रहा है, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। पटना नगर निगम क्षेत्र में 5 लाख 80 हजार मकान बनाये गये हैं, जिनमें से महज 2 लाख 56 हजार मकान ही पंजिकृत है। पटना शहर में 50 हजार से ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं। अभी पटना नगर निगम क्षेत्र में दो से ढ़ाई लाख घरों में लोगों ने समरसेबुल पम्प लगा रखा है। पूरे बिहार में भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त 75 वाटर पम्प लगाये गये हैं। जिनमें से अकेले पटना शहर में 25 वाटर प्लांट हैं। इसके अलावे पूरे शहर में

अवैध रूप से सैकड़ों वाटर पम्प लगाये गये हैं। केवल पटना शहर में हर महीने पानी का कारोबार 15 करोड़ का है। अर्थात् प्रति वर्ष 180 करोड़ का है। अपार्टमेंट्स के ढ़ेर सारे फ्लैट्स, निजी मकानों तथा बड़े-बड़े होटलों में सावर के साथ-साथ बाथटब का इस्तेमाल किया जाता है। बाथटब का इस्तेमाल करने पर एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ नहाने 200 से 400 लिटर पानी बहा दिया जाता है।

ध्यान रहे, एक लिटर बोतल बंद पानी तैयार करने के लिए पांच लिटर पानी बर्बाद किया जाता है। बिहार भर में बड़े-बड़े वाटर प्लांट कारखाने जैसे-कोको कोला, पेप्सी, थम्सअप, स्प्राईट आदि के अलावा बोतल बंद पानी के छोटे-छोटे लाखों वाटर प्लांट लगाये गये हैं। करोड़ों घरों में आर.ओ. वाटर प्यूरोफाइन मशीने लगी है। अपार्टमेंट्स, घरों, दफ्तरों, होटलों, क्लबों आदि जगहों में करोड़ों की संख्या में वाटर प्यूरीफाईन मशन, एयर कंडिश्नर लगाये गये हैं। जिनके इस्तेमाल के दरम्यान प्रतिदिन करोड़ों लिटर पानी बहा दिये जाते हैं। पटना क्लब, बांकिपुर क्लब, मौर्या होटल, आदि जगहों मे स्वीमिंग पुल बना हुआ है। एक छोटे से स्वीमिंग पुल को भरने मे एक लाख 50 हजार लिटर पानी लग जाता है। यही कारण है कि भू-जल के दोहन हेतु पटना शहर में हर साल कई हजार समरसेबुल मोटर पंप लगाये जा रहे हैं। बेतहाशा भू-जल दोहन के चलते पटना शहर में भू-जल का स्तर सलाना 4 - 6

फीट नीचे जा रहा है। पटना शहर में नगर निगम द्वारा 16 घंटे पानी की आपूर्ति किया जाना समझ के बाहर है। दरअसल लोगों में पानी स्टोर करने की प्रवृति नहीं है। यही कारण है कि पटना नगर निगम को दो चरणों के बजाये चार चरणों में पानी की आपूर्ति करनी पड़ती है। जबकि 1970 तक इसी शहर में केवल दो चरणों में चार-चार घंटे ही पानी की आपूर्ति की जाती थी। अपार्टमेंट कल्चर में भू-जल का दोहन अंधाधूंध हो रहा है। अपार्टमेंट, निजी मकानों, बड़े-बड़े होटलों, प्राइवेट क्लबों आदि में आर.ओ. व फिल्टर वाटर प्लांट्स आदि की बोरिंग से 24 घंटे में कितनी बार और कितना पानी निकाला जाता है, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। हजारों अपार्टमेंट्स में भू-जल का दोहन चौबिसों घंटे जारी रहता है। इस तरह हम पाते हैं कि सिर्फ पटना शहर में धरती की कोख से प्रतिदिन कितने करोड़ लिटर पानी निकाला जाता है, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारा समाज भू-जल के दोहन में कितना निष्ठुर और गैरजिम्मेदार है। अपार्टमेन्ट्स, बहुमंजिली इमारत तथा बड़े-बड़े सरकारी और गैर सरकारी भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग तथा दूसरे भू-जल रिर्चाज सिस्टम नहीं लगाये गये हैं, जबकि ऐसा किया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया है। बिहार सरकार के साथ-साथ पटना नगर निगम के निठल्ले मुलाजिम इस ओर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं।

पटना शहर जहाँ पानी कुछ ज्यादा ही किल्लत है।

वार्ड संख्या	एरिया	सर्वाधिक प्रमुख समस्या
03	बिहार कॉलोनी	बोरिंग नहीं
08	पटेल नगर	बोरिंग फेल
11	हरनी चक	बोरिंग नहीं
17	दोपुलवा	बोरिंग फेल
20	देवी स्थान	बोरिंग नहीं
22 बी	सामुदायिक कुर्जी भवन के निकट	बोरिंग नहीं
27	बुद्ध घाट	कम क्षमता की बोरिंग
29	मनोकामना मंदिर	जर्जर वाटर पाइप लाईन
36	निशा मंदिर	बोरिंग नहीं
40	कॉलेजियट स्कूल	बोरिंग नहीं
42	झब्बू लाल प्राथमिक स्कूल के निकट	जर्जर वाटर पाइप लाईन
42	काजीपुर पुलिस चौकी	कम क्षमता की बोरिंग
48	सैदपुर नाला	बोरिंग नहीं
49	गंगा घाट	बोरिंग फेल
54	भागवतचक पथ	बोरिंग नहीं
54	बड़ी पहाड़ी	बोरिंग नहीं
61	मर्तूलीगंज	जर्जर वाटर पाइप लाईन
63	जमुनी राय का कुंआ	बोरिंग नहीं

भू-जल भंडार के मामले में भारत की स्थिति ठीक नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली सहित 11 मेट्रो शहर में 2020 तक यानि दो साल के अंदर भू-जल करीब-करीब समाप्त हो जायेगा, ऐसा निति आयोग की रिपोर्ट में प्रकाशित है। भू-जल के मामले में आज बिहार की स्थिति भी खास्ता हाल है, जबकि भू-जल भंडार की दृष्टि से बिहार देश का सर्वाधिक समृद्ध राज्य है। इस मामले में बिहार की राजधानी पटना देश का सर्वाधिक समृद्ध शहर है। पटना शहर में भू-जल की उपलब्धता 28 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मिटर) यानि 28 अरब क्यूबिक मिटर है, जो इस शहर के लोगों की जरूरत से ढ़ाई गुणा अधिक है। फिर भी पटना शहर की बड़ी आबादी शुद्ध पेयजल के लिए तरस रही है। अंधाधूंध भू-जल दोहन के चलते पटना शहर का भू-जल स्तर लगातार तेजी से घट रहा है। मसलन गंगा नदी से सटे किनारे वाले इलाके में आज से 22 साल पहले जहां 40 फीट की गहराई में पानी उपलब्ध हो जाता था, वही पर 80 से 90 फीट की गहराई में साफ पानी मिल पा रहा है। बगैर किसी रोक-टोक के जिस तेजी से भू-जल का दोहन किया जा रहा है,

उससे आने वाले कुछ ही वर्षों के अंदर पटना शहर के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। पूरे बिहार में बेलगाम भू-जल दोहन के चलते भू-जल का स्तर इतना नीचे चल गया है कि बिहार के जमुई जिले के चकई प्रखण्ड में भू-जल का स्तर एक हजार फीट से भी नीचे चला गया है। पाताल से पानी दोहन करने के लिए बिहार में ढ़ेर सारी जगहों पर धरती छलनी कर दी गई है।

★ पटना शहर के 70 फिसदी वेट लैंड खत्म हो गये हैं :- वर्षों पहले कभी पटना शहर वेट लैण्ड्स (नम भूमि) का विस्तृत और आर्दश क्षेत्र हुआ करता था। वेट लैण्ड का यह क्षेत्र सगुना मोड़ से लेकर पटना सिटी तक फैला हुआ था, जिसका अब 70 फिसदी हिस्सा नष्ट हो चुका है। इसे बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय नुकसान हुआ है। वर्तमान में जहां मीठापुर बस स्टैंड, चाणक्य लॉ युनिवर्सिटी से लेकर अन्य कई शिक्षण संस्थान बना दिये गये हैं, वहां बहुत ही बड़ा तालाब हुआ करता था, जिसे जल्ला इलाका कहा जाता था। वहां सैकड़ों एकड़ से अधिक इलाके में सालों भर पानी भरा रहता था, जिससे कई सौ एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। राजेन्द्र नगर से सैदपुर तक का ज्यादातर हिस्सा लो लैण्ड एरिया था, जो बरसात में डूबा ही रहता था। कभी मुसल्लहपुर और बाजार समिति का पूरा का पूरा एरिया वेट लैण्ड होता था, आज जहां सैदपुर स्थित पटना युनिवर्सिटी के छः बड़े-बड़े होस्टल और ढ़ेर सोर टिचर्स क्वार्टस हैं, वहां से लेकर महात्मा गांधी सेतु तक सैकड़ों एकड़ जमीन में फैला हुआ काफी लंबा-चौड़ा बड़ा तालाब हुआ करता था। सैदपुर से संदलपुर तक फैले हुए उस तालाब में सालों भर पानी भरा रहता था, जिसमें बड़े पैमाने पर सिंघाड़े की खेती होती थी और उसे जल्ला इलाका कहा जाता था। गुणसागर तालाब के नाम से वह तालाब सरकारी दस्तावेज में दर्ज है। मछली पालन हेतु उस तालाब की बंदोबस्ती 1996 तक होती थी। आज न्यू अजिमाबाद कॉलोनी और संदलपुर कॉलोनी उसी तालाब के एक बड़े हिस्से को मिट्टी से भरकर बसायी गयी है। दरअसल पटना सिटी से लेकर संदलपुर, बाजार समिति, सैदपुर, बहादुरपुर, कुम्हरार, कंकड़बाग, बोरिंग कैनाल रोड आदि स्थानों को होते हुए सगुना मोड़ तक हजारों एकड़ जमीन में फैले हुए पटना शहर में तालाबों की भरमार थी। इसलिए पटना शहर को तालाबों का शहर कहा जाता था। इन तालाबों के बीच जो खाली जमीन थी, जिनपर सड़के, मकान, कॉलोनियां आदि बना दी गई है, वे सारी वेट लैण्ड थें। ऐसा इसलिए कि सारे तालाबों के बीच की खाली जमीन दिखती तो सूखी लेकिन काफी नम होती है। इसलिए पटना शहर के हजारों एकड़ भूमि में फैले तालाबों से पटी इस भूमि को वेट लैण्ड इलाका कहा जाता था। वेट लैण्ड के चलते पटना शहर में न सिर्फ भू-जल का स्तर बेहद ऊँचा था, बल्कि साफ पानी भी प्रचूर मात्रा में उपलब्ध था।

★ वेट लैण्ड का मतलब :- वेट लैण्ड उस भूमि को कहते हैं, जहां प्राकृतिक रूप से जल संग्रहित रहता है, जिससे भू-जल प्राकृतिक रूप से रिर्चाज होता रहता है। ऐसे क्षेत्र में समुचित जैव विविधता मौजूद होती है तथा आसपास की हवा में मौजूद प्राकृतिक रूप से फिल्टर होकर पर्यावरण होकर जरूरत से ज्यादा धूलयुक्त नहीं होने देता है।

वेट लैण्ड्स के फायदे :-

☞ भू-जल प्राकृतिक रूप से रिर्चाज होता रहता है।

☞ पर्याप्त जैव विविधता मौजूद रहती है।

☞ अपेक्षाकृत अधिक नम होने से हवा का प्राकृतिक रूप से फिल्टरेशन होता रहता है।

वेट लैण्ड से होने वाले नुकसान :-

☞ भू-जल का प्राकृतिक रूप से रिर्चाज होना रूक जाता है।

☞ वेट लैण्ड में स्थायी रूप से रहने वाले सैकड़ों जिवों का सफाया हो जाता है। इसमें कई प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां शामिल है। इसके कारण प्राकृतिक रूप से चली आ रही खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।

☞ नमी की कमी के चलते उस इलाके विशेष की हवा का प्राकृतिक रूप से फिल्टरेशन नहीं हो पाता है।

★ पूरी दुनियां में भू-जल का सर्वाधिक दोहन भारत में होता है :- कुल वैश्विक भू-जल का 72 फिसदी का उपयोग भारत, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान सहित दस देशों में होता है। लेकिन पूरी दुनियां में भारत भू-जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हम भारतीय चीन और अमेरिका से अधिक भू-जल का दोहन करते हैं। अकेले हमारे देश में सलाना करीब 38 बीसएम भू-जल का दोहन होता है। जबकि चीन और अमेरिका मिलकर सलाना 12 बीसीएम भू-जल का दोहन करते हैं। सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार हमारे देश में पिछले दस वर्षों में भू-जल के स्तर में 61 फिसदी की कमी आयी है। विश्व बैंक के 2012 के रिपोर्ट के अनुसार भू-जल के कुल इस्तेमाल का 25 फिसदी से भी ज्यादा हिस्सा भारत में उपयोग किया जाता है। भारत के ग्रामीण इलाके के जरूरत के पानी का 85 फिसदी पानी की आपूर्ति भू-जल से किया जाता है और शहरी इलाकों की जरूरत का 55 फिसदी पानी की आपूर्ति भू-जल से किया जाता है। ऐसा इसलिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश के ज्यादातर हिस्से में उपलब्ध पानी का 90 फिसदी हिस्सा खेती-किसानी, 7 फिसदी हिस्सा उद्योगों में और 3 फिसदी हिस्सा घरेलू कार्यों में किया जाता है। उत्तर भारत में धान और गेंहू जैसी फसलों की सिंचाई हेतु भू-जल का बेतहाशा

दोहन किया जा रहा है। देश का कृषि प्रधान राज्य होने के चलते बिहार में भू-जल का बहुत अधिक दोहन किया जाता है। नतीजा बिहार में भू-जल के स्तर में काफी गिरावट आ गई है। भारत में सुरक्षित भू-जल का भंडार पिछले तीन वर्षों में 70 बीसीएम से घटकर 38 बीसीएम रह गया है। ऐसा इसिलए कि देश में जितने भू-जल का दोहन होता है, उसका 42 फिसदी से भी कम पानी वापस धरती की कोख में लौटाया जाा है। अर्थात् अंधाधून भू-जल के दोहन के चलते पिछले 60 सालों में भू-जल का स्तर साढ़े तीन गुणा नीचे चला गया है। जल संकट कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा

सकता है कि 1947 में आजादी के समय जब देश की आबादी 35 करोड़ थी, तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता 6043 घन मिटर थी, जो 2016 में जब देश की आबादी 120 करोड़ हो गई तो जल की उपलब्धता घटकर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1545 घन मिटर रह गई। अर्थात् आजादी के बाद के महज 70 वर्षों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता में 25 प्रतिशत की कमी हो गई।

★ नालियों में बह जाता है सप्लाई का 15 प्रतिशत पानी :- लगभग 1200 किलोमीटर बिछायी गयी पाईप लाईन से वाटर बोर्ड द्वारा प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ लिटर पानी सप्लाई की जाती है, जिसमें से लगभग 67 लाख 50 हजार लिटर यानि 15 फिसदी बर्बाद हो जाता है। कारण है नगर निगम द्वारा प्रदान की गई बेहद कमजोर और लचर जलापूर्ति सिस्टम। जिस सिस्टम जलापूर्ति होती है, लोहे का वह पाईप लाईन आजादी के पांच साल बाद 1952 में बिछी थी, तब से आबादी लगभग चार गुणा बढ़ गई है। लेकिन पाईप लाईन का दायरा नहीं बढ़ा है। पीएमसीएच में 1960 में एक लाख लीटर क्षमता का पानी की टंकी का निर्माण किया गया था। उस दौरान पीएमसीएच में वाटर सप्लाई के लिए पाईप लाईन भी बिछाया गया था। लेकिन 2015 तक पीएमसीएच में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या कई गुणा बढ़ गई। पानी की मांग कई गुणा बढ़ने पर उसी साल यानि 2015 में एक लाख लीटर क्षमता की दूसरी टंकी का निर्माण किया गया। नई टंकी द्वारा पानी की सप्लाई भी उन्ही लगभग 55 साल पुराने पाईपलाईन से किया जाने लगा, जो कई जगहों पर जंग लगने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। जब नया बोरिंग होता है और उसे उसी पुराने पाईप लाईन से जोड़ दिया जाता है तो बोरिंग से पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे पुराने पाईप लाईन सहन नहीं कर पाती है और डैमेज हो जाती है। यही कारण है कि पूरे पटना शहर में पटना नगर निगम द्वारा बिछायी गयी पाइप लाईन में जगह-जगह लिकेज आम बात हो गई है।

यह पटना नगर निगम के विगत कुछ दशकों के घोर लापरवाही का नतीजा है। विगत कई दशकों से वाटर सप्लाई पाईप लाईन के रख-रखाव (मेंटनेन्स) की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। नतीजा जंक लगने के कारण लोहे की जर्जर व कमजोर हो चुकी पाइप लाईन कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में सप्लाई का लगभग 12-13 प्रतिशत पानी सड़क पर पसर जाता है और नालों में बह जाता है। जर्जर हो चुकी पाइप लाइन दर्जनों जगहों पर जाम हो चुकी है, तो दर्जनों जगहों पर मिसिंग लिंक का शिकार बन चुकी है। यही कारण है कि पटना शहर के कई मोहल्लों में पानी का सप्लाई लेवल ठीक नहीं है तो कई मोहल्लों में बहुत ही कम है। इतना कम की लोगों को पानी के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़ा रहकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। सच पूछिए तो इसकी असली वजह सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों का निठल्लापन है। दरअसल में सरकारी कर्मचारी जनता के सेवक नहीं मालिक बन बैठे हैं। जनता के पैसों पर पलने वाले ज्यादातर अधिकारियों व कर्मचारियों से जनता बुरी तरह त्रस्त है।

मैले पानी के निकासी के पाईप लाईन और साफ पानी के आपूर्ति करने वाले पाईप लाईन ज्यादातर जगहों पर जमीन के अंदर बहुत पास-पास बिछे हुए हैं, जिसके चलते सिवरेज के पाईप लाईन से निकला गंदा पानी जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त हो गई वाटर सप्लाई पाईप लाईन में प्रविष्ट कर पीने के साफ पानी को इतना अधिक प्रदूषित कर देता है कि वाटर सप्लाई चालू होने के बाद पहले आधे घंटे तक उससे दुर्गंध आती है। आज स्थिति यह है कि 70 फिसदी से अधिक क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पाईप लाईन से घरों में दुषित तथा गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। नतीजा आज पटना शहर के किसी भी मोहल्ले में नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला साफ पानी पीने के लायक नहीं रह गया है। नतीजा अधिकतर घरों के लोग सुबह-शाम लंबी-लंबी कतारों में खड़ा रहकर घंटों इंतजार के बाद प्राप्त पानी का उपयोग बर्तन धोने, कपड़ा धोने आदि में करते हैं, क्योंकि वाटर सप्लाई लाईन से प्राप्त पानी इतना दूषित होता है कि उससे दुर्गंध आती है। इसलिए अधिकतर घरों, कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों आदि में पीने का पानी खरीदा जाता है या जल शोधक मशीने लगाकर शुद्ध किया जाता है।

पटना शहर के मोहल्लों की ढ़ेर सारी पतली-पतली गलियों में रहने वाले लोग आए दिन अपनी सुविधा के अनुसार गलि की सड़कों को काटकर वाटर सप्लाई पाईप लाईन का छेदा बड़ा कराके उसमें मोटा पाईप लगवा देते हैं, जिससे की उन्हें सप्लाई का पानी उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में मिल सके। लेकिन जब अवैध तरीके से ऐसा कराया जाता है तो सिवरेज का ढ़ेर सारा गंदा पानी साफ पानी आपूर्ति करने वाले पाईप में मिल जाता है, जिससे की सप्लाई किए जाने वाला साफ पानी दूषित हो जाता है। ऐसा नगर निगम में कार्यरत्त कर्मियों की मिलीभगत के चलते ही संभव हो पाता है। फिर जल्दी-जन्दी, चोरी-छूपे इस कार्य का अंजाम तक पहुंचाने के दौरान मुख्य पाईप लाईन इस तरह से जोड़ी गई पाईप से अच्छी तरह से सील नहीं होने के कारण इन जगहों पर सप्लाई का साफ पानी लगातार दूषित होता रहता है। सरकार को इस भ्रष्ट कार्य पर सख्ती से रोक लगा देनी चाहिए।

★ आबादी में हो रही अनवरत बेतहाशा वृद्धि पर जरूरी है रोक :- साल 1804 में दुनियां की आबादी 100 करोड़ थी, जो 1934 में बढ़कर 200 करोड़ हो गई, 1967 में 300 करोड़, 1981 में 400 करोड़ और 2018 में 736 करोड़ हो गई। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, उस समय देश की आबादी महज 35 करोड़ थी, जो 2018 पूरा होते-होते बढ़कर 135 करोड़ हो गई। वर्तमान में देश की आबादी बहुत अधिक है। इतनी अधिक है कि लोगों की सहुलियत के लिए जितना भी किया जा रहा है, सब कम पड़ता जा रहा है। खाने के लिए अनाज कम पड़ गया है, पीने के लिए पानी कम

पड़ गया है, रहने के लिए मकान कम पड़ गया है, शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान कम पड़ गये हैं, इलाज के लिए अस्पताल कम पड़ गये हैं, खेलने-कूदने के लिए खेल के मैदान कम पड़ गये हैं, आवागमन तथा माल की ढुलाई के लिए रेल, बस, कार, हवाई जहाज, ऑटो, बाईक आदि सब के सब कम पड़ गये हैं। घूमने के लिए पार्क कम पड़ गये हैं, खेती के लिए जमीन कम पड़ गई है, सड़क-पुल आदि के लिए जमीन कम पड़ गई है, शुद्ध हवा के लिए तथा जल संरक्षण के लिए पेड़- पौधे कम पड़ गये है, जल संरक्षण के लिए तालाब कम पड़ गये हैं, नौकरी के लिए खाली पद (वेकेंसी) कम पड़ गये हैं, जलाने के लिए बिजली कम पड़ गई है, वाहनों को दौड़ाने के लिए सड़क कम पड़ गई है, पैदल चलने के लिए सड़क के किनारे स्थित फुटपाथ कम पड़ गये हैं, नदियों को पार करने के लिए पुल कम पड़ गये हैं, इत्यादि। अर्थात् जीवन के हर क्षेत्र में हमें कमी का सामना करना पड़ रहा है या कमी झेलने के लिए हम मजबूर हैं। अर्थात् जनसंख्या विस्फोट के चलते हमें हर तरह की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हम हर तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। नतीजा, लोग अपराध की ओर उन्मुख होने लगे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट अपराध की जननी है। इसलिए बेतहाशा बढ़ती आबादी को रोकने के लिए जनता को हम दो हमारे एक के सिद्धांत को अपनाना ही होगा।

★ तेजी से हो रहे जंगल के सफाये पर जरूरी है रोक :- एक अनुमान के अनुसार हर मिनट दुनियां में 48 फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल काटे जा रहे हैं। हर साल दुनियां भर में 15 अरब पेड़ काटे जाते हैं। दुनियां में सबसे अधिक करीब 65 अरब पेड़ रूस में है, जबकि भारत में 35 अरब से भी कुछ कम है। बात यह है कि अनवरत बढ़ती आबादी को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार तेजी से जंगलों को काटा जा रहा है। इसके अलावा अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी तेजी से जंगलों का सफाया किया जा रहा है। मसलन दुनियां भर में प्रति व्यक्ति सालाना 52 किलो पेपर की खपत है। अगर देश में रेलवे का टिकट न ले तो हर रोज 35 पेड़ कटने से बच जायेंगे। रोजाना हमारे देश में तीन लाख टिकट बुक किए जाते हैं। एक पेड़ से ए-4 साईज की 8335 सिट बनती है। एयरपोर्ट के टॉयलेट और बाथरूम में यात्रियों को टिसू पेपर जिस बेरहमी से इस्तेमाल करते देखता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि हम इतने असंवेदनशील

क्यों हो गये हैं? यदि हम एक रूमाल का इस्तेमाल करे तो जरा सा भी टिसू पेपर बर्बाद नहीं होगा और नित्य लाखों पेड़ कटने से बच जायेंगे। बिहार सरकार जनता की सुविधा के लिए पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछा रही है। इसमें से ढ़ेर सारी सड़के दो लेने की है, कुछ सड़के तो चार-चार और छः लेन की है। कई दो लेन वाली सड़कों को चार लेन और चार लेन वाली सड़कों को छः लेन में तब्दील किया जा रहा है। इसके लिए करोड़ों पेड़ काट दिये जाते हैं, लेकिन सरकार पेड़ों को लगाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। जबकि इस कार्य को किया जाना नितांत अनिवार्य है और करने में कोई झंझट भी नहीं है। इसके लिए थोड़ी इच्छाशक्ति की जरूरत है। यदि इसके लिए सरकार को जमीन उपलब्ध कराने की कोई परेशानी भी नहीं उठानी है। राज्य भर में करोड़ों किलोमीटर लम्बे सड़कों के दोनो तरफ, तालाबों के चारो किनारों पर, नहरों के दोनो तरफ, सरकारी स्कूलों के चारो तरफ उसके बॉन्ड्री वाल के भीतर, सरकारी कार्यालयों के चारो ओर उनके बॉन्ड्री वाल के भीतर, सरकारी अस्पतालों के चारो तरफ उसके बॉन्ड्री वाल के भीतर आदि जगहों पर बगैर किसी विलंब के युद्धस्तर पर सरकार को वृक्षारोपण के जनकल्याणकारी कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। शुरू में लगाये गये छोटे-छोटे पौधों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचने पाये, इसका समुचित इंतजाम करना चाहिए। शुरू में लगाये गये छोटे-छोटे पौधों की हिफाजत करने में जनता को भी भरपूर सहयोग करना चाहिए। सरकार और समाज के आपसी सहयोग से ही इस महत्वपूर्ण और जरूरी कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है और हर हाल में तत्परतापूर्वक मनोयोग से पहुंचाया जाना ही चाहिए। ध्यान रहे जल संकट और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाना सरकार और समाज दोनो की बराबर की जिम्मेदारी है।

★ जरूरी है तेजी से पिघल रहे ग्लैशियरों को बचाना :- पिछले 110 साल में देश का औसत तापमान 0.60 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जिसके कारण ग्लैशियरों के पिघलने की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिकों ने ऊपर ली गई तस्वीरों, उपग्रह माप और कम्प्यूटर मॉडल का इस्तेमाल कर पता लगाया है कि अंटार्कटिका में वर्फ 1980 की तुलना में चौगुणा तेजी से पिघल रही है, जिसका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका में 2009 से हर साल 278 अरब टन वर्फ पिघल रही है, जबकि 1980 के दशक में 44 अरब टन वर्फ पिघल रही थी। कैलोफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एरिक ने बताया है कि उपग्रह आधारित अध्ययन में यह

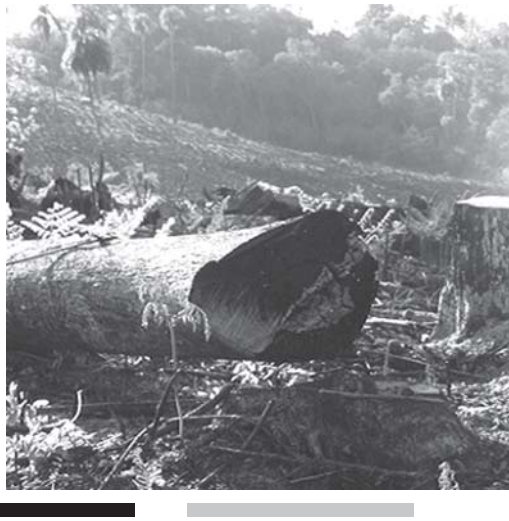

दिखायी दिया है कि स्थिर समझे जाने वाले पूर्वी अंटार्कटिका में भी हर साल 56 अरब टन वर्फ पिघल रही है।

ग्लैशियरों के पिघलने की गति को कम करने यानि स्वभाविक बनाये रखने के लिए पर्यावरण में कार्बन के उत्सर्जन में भारी कटौती करनी होगी। यह तभी संभव जब हम बिजली की फिजुलखर्ची न करे और बिजली की खपत में अधिक से अधिक कमी लाये। ऐसा किया जाना व्यवहारिक है। मसलन, बिजली के समान्य बल्ब की जगह सिर्फ एल.ई.डी. बल्ब का ही इस्तेमाल किया जाये। इस बात को ध्यान में रखकर मोदी सरकार बहुत ही सस्ती दर पर सबों को एलईडी. बल्ब उपलब्ध करा रही है। स्वचालित वाहनों के इस्तेमाल पर कारगर अंकुश लगाकर भी कार्बन के उत्सर्जन में भारी कमी लायी जा सकती है। कार खरीदने का अधिकार उन्ही के पास होना चाहिए, जिनके पास कार के पार्किंग की जगह है। ऐसा करने पर कारों के इस्तेमाल में स्वत: भारी कमी आ जायेगी। स्वचालित वाहनों का कारब्यूरेटर साफ रखने, इंजन की ट्यूनिंग सही रखने और समय-समय पर सर्विसिंग कराने पर इन वाहनों के उत्सर्जन में भारी कमी लायी जा सकत है। स्वचालित वाहनों में प्रिमियम पेट्रोल और यूरो टू डीजल यानि उम्दा किस्म की डीजल का इस्तेमाल करके भी कॉर्बन के उत्सर्जन में भारी कमी लायी जा सकती है। एकांकी वाहनों के बजाये सामुहिक वाहनों का इस्तेमाल करके कॉर्बन के उत्सर्जन में भारी कमी लायी जा सकती है। भारत में औसतन सलाना 60 करोड़ मिट्रिक टन पराली जलायी जाती है। धान और गेंहू की फसलों की कटाई के बाद खेतों में पराली नहीं जलाने से भी कॉर्बन के उत्सर्जन में भारी कमी लायी जा सकती है। इसके लिए धान एवं गेंहू के फसलों की कटाई के तुरंत बाद केन्द्र और राज्य सरकारों को सरकारी खर्च पर खेतों को जुतवा देना चाहिए। जिससे की किसानों को पराली जलाने का मौका ही नहीं मिले। खुले में, सड़कों के किनारे और कचड़ा डम्पिंग यॉर्ड में कचड़े को जलाने पर रोक लगाकर भी कॉर्बन के उत्सर्जन में भारी कमी लायी जा सकती है।

★ जरूरी है भू-जल स्तर की मॉनेटरिंग :- बिहार सरकार ने राज्य के सभी 534 प्रखंडों में भू-जल की निगरानी के लिए टेलीमिटर लगवाने का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। कुल 571 जगहों पर यह सयंत्र लगवाया जा चुका है। यह यंत्र ट्यूबवेल या बोरिंग से जुड़ा रहता है। इस यंत्र की विशेषता है कि यह अपने आप सेटेलाईट से जुड़ जाता है और भू-जल स्तर मापकर सेटेलाइट को भेजता है तथा हर तीसरे घंटे उस आंकड़ें को संबंधित विभाग को उपलब्ध करा देता है। इसका फायदा यह होगा कि यह यंत्र सरकार को भू-जल स्तर मेंटेन करने हेतु हमेशा सचेत करता रहेगा। असल दिक्कत यह है कि सरकार द्वारा टेलीमिटर को रेगुलर और उचित तरीके से कार्यान्वित करा पाना। इसके दो कारण है-पहला की सरकार योग्य तकनीशियनों को बहाल नहीं कर पाने की और दूसरा 90 फिसदी सरकारी मुलाजिमों का निकम्मा तथा गैर जिम्मेदार हो जाना। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनके द्वारा बहाल सरकारी मुलाजिम योग्य हो और कार्य को रेगुलर तथा समय पर करने के लिए बाध्य हो। अन्यथा इस कार्य का भी वही हाल होगा, जो आज से 13-14 वर्ष पहले सरकार द्वारा बहाल लगभग 4 लाख शिक्षकों का है। सरकार बार-बार इन शिक्षकों का पात्रता परीक्षा लेती है, फिर भी 4 लाख बहाल इन शिक्षकों में से 90 फिसदी शिक्षक अपात्र ही है।

★ जरूरी है भू-जल स्तर नियंत्रण के कारगर उपायों को अपनाना :- सरकार को भू-जल के अवैध दोहन पर अविलंब कारगर अंकुश लगाना होगा। इसके लिए सरकार को घरों, अपार्टमेंट्स, स्कूलों, कॉलेजों, होटलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस अड्डों, सरकारी कार्यालयों आदि जगहों में पानी के एक-एक बूंद का हिसाब रखने के लिए वाटर मिटर लगवाने होंगे। वाटर मिटरों की रिडिंग समय पर मुस्तैदी से करानी होगी। त्रुटिपूर्ण वाटर मिटरों को बगैर किसी विलंब के बदलवाना होगा। पानी के अवैध कनेक्शनों की पहचान कराकर उन्हें बैध कराने होंगे अथवा कटवाने होंगे। बिहार सरकार ने मई 2018 के पहले सप्ताह में घोषणा किया था कि तीन महीने के अंदर घरों, कार्यालयों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में वाटर मिटर लगवाने का काम शुरू कर दिया जायेगा। लेकिन, इस साल के जनवरी में भी शुरू नहीं कराया जा सका। सिर्फ घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, काम को अंजाम तक पहुंचाना भी होगा। सरकार को नई बोरिंग कराने और बोरवेल लगाने के लिए लाईसेंस अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। हर इलाके में वहां के भू-जल स्तर के मुताबिक बोरवेल लगवाने की अधिकत्तम गहराई निर्धारित कर देनी चाहिए। जिससे की सरकारी और प्राइवेट बोरवोल वाले अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी गहराई तक चाहे बोरिंग लगा ले, ऐसी प्रवृति पर अंकुश लगायी जा सके। ऐसा करके भू-जल के अंधाधून दोहन पर रोक लग सकेगा। नतीजा भू-जल के स्तर को और नीचे गिरने से रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार को अच्छा खासा राजस्व भी मिलने लगेगा।

लगभग सभी राज्य के किसानों को सस्ती दर पर बिजली दी जाती है। कई राज्यों में किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है। इससे किसानों की प्रवृति अधिकाधिक भू-जल दोहन करने की बन गयी है। जिससे पानी की काफी बर्बादी हो रही है। किसान खेतों की सिंचाई ड्रिप सिंचाई तकनीक से करने लगे, इसके लिए सरकार के द्वारा किसानों को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता अविलंब उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे की कम से कम पानी के इस्तेमाल द्वारा अधिक से अधिक खेतों की सिंचाई की जा सके। इसके साथ ही यह भी जरूरी की फसलों के समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि कर दी जाये, जिससे की किसानों पर अनुचित आर्थिक बोझ न पड़े। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बढ़ाये गये समर्थन मूल्य पर बगैर किसी विलंब के पैदावार खरीद ली जाये। जिससे की किसानों के पैदावार बर्बाद न होने पाये तथा बिचौलियों के द्वारा आर्थिक रूप से शोषित होने

से बचाया जा सके।

★ जरूरी है तालाबों को संरक्षण व संवर्धन :- हर हालत में अब न सिर्फ तालाबों को और अधिक खत्म होने से बचाना होगा बल्कि इनका तेजी से बिस्तार और उचित रख-रखाव भी करना होगा। तालाबों को खत्म होने से न बचा पाना इसलिए जरूरी है कि यह कृत्य आत्मघाती है। अपना कब्र आप खोदने जैसा है। इसका विस्तार इसलिए जरूरी है कि इनकी संख्या पर्याप्त से बहुत ज्यादा कम है। इतना कम है कि इनसे हमारे अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है। तालाबों का समुचित रख-रखाव इसलिए जरूरी है कि जो तालाब बच गये हैं, उनकी सक्रियता काफी कम हो गई है। इसलिए तालाबों के जीर्णोधार के साथ-साथ हर साल उनकी तलहट्टी से गाद निकालनी होगी। क्योंकि तालाबों के पेंदे में जमी यह गाद ही तालाबों की सक्रियता पर विपरित प्रभाव डालती है। इसके चलते तालाब स्वभाविक गति से भू-जल को रिर्चाज नहीं कर पाते हैं और इसलिए इनकी जलधारण करने की क्षमता भी घट गई है। तालाबों को अतिक्रमण से बचाने के लिए न्यायालयों ने जो आदेश दिये हैं, उन आदेशों का सख्ती से पालन हो, इसे सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभानी होगी। जनता को चाहिए कि अब एक भी तालाब का अतिक्रमण न होने दे। 100 फीट लंबा, 100 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा एक तालाब के निर्माण पर करीब 2 लाख 50 हजार रूपये खर्च आते हैं। सरकार को ऐसे 1000 तालाबों का निर्माण युद्ध स्तर पर एक साल के भीतर कराने चाहिए। जिसपर कुल खार्च 250 करोड़ रूपये आयेंगे। तालाबों के संरक्षण व संवर्द्धन के कार्य को सरकार और समाज दोनो को ही पूरी जिम्मेदारी के साथ निभानी चाहिए। सघन वन क्षेत्र में लगातार कमी होने के चलते सलाना औसत वर्षा में लगातार कमी होते जा रही है, क्योंकि वृक्ष ही बादलों को आकर्षित कर वर्षा कराते हैं। ऐसे में अधिकाधिक वर्ष जल को सहेज कर संग्रहित करना बहुत जरूरी हो गया है। यह तालाब ही है, जो वर्षा जल को शरण देते हैं। नतीजा अधिकाधिक उपजाऊ मिट्टी नदियों में जाने से बच जाती जायेंगी तथा बरसात के मौसम में शहर और गांव की सड़के अस्थायी तालाब का रूप लेने से बच जायेंगे।

★ जरूरी है जलाशयों में जमी गाद को निकाला जाना :- बिहार के कुछ प्रमुख नदियों के दोनो तरफ तटबंध बनाकर बांध यानि जलाशय बना दिये गये हैं। लेकिन, बांध बनाने के बाद से लेकर आज तक एक बार भी इन जलाशयों के पेंदे में जमी गाद को नहीं निकाला गया है। जिसके चलते इन जलाशयों की जल धारण करने की क्षमता में काफी कमी आ गयी है। ऐसा इनके पेंदे में गाद जमा होने के कारण इनकी सक्रियता में आयी कमी के चलते हो गया है। मसलन चंदन नदी पर बने बांका जिला स्थित चंदन जलाशय को ही ले लिजिए, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इस जलाशय की जल धारण क्षमता अब काफी कम हो गई है। यही हाल बिहार के अन्य सभी जलाशयों की है। इसलिए जरूरी समय-समय पर इन जलाशयों के पंदे में जमी गाद को निकाला जाना।

नदियों, तालाबों और जलाशयों में जमी गाद को निकालने के बाद उस गाद को बगैर किसी बिलंब के निष्पादन (डिस्पोजल) और वितरण (डिस्टीब्यूसन) की उचित व्यवस्था किया जाना भी जरूरी है। नदियों, तालाबों और जलाशयों के पेंदे से प्राप्त गाद बहुत ही उम्दा प्राकृतिक खाद होती है, जिसे खेतों में डालकर उनकी उर्वराशक्ति को स्वभाविक रूप से बढ़ायी जा सकती है।

★ जरूरी है रेनवाटर हार्वेस्टिंग कानून का पालन किया जाना :- बिहार सरकार ने अपार्टमेंट्स, बहुमंजिली इमारत और बड़े-बड़े सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से युक्त करना, कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया है। लेकिन, किसी भी सरकारी भवन में जब इस कानून को नहीं माना जा रहा है तो भला गैर सरकारी भवनों में कैसे माना जायेगा। सरकार और पटना नगर निगम के मुलाजिम इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर हम यही पाते हैं कि बिहार सरकार को रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य से कोई लेना-देना नहीं है, जो कि निश्चित रूप से घातक है।

सरकार चाहती है कि हर घर नल-जल मिले यानि पीने का साफ पानी मिले। इसके लिए पटना नगर निगम ने चापाकलों की मरम्मत के लिए प्रति वार्ड 50 हजार रूपये आवंटित किया है। पटना शहर का कोई भी चापाकल खराब नहीं हुआ है, भू-जल का स्तर नीचे जाने से पानी नहीं दे रहा है। इन सभी चापाकलों की गहराई 20 फीट बढ़ा दी जाये तो सभी चापाकल पानी देने लगेंगे। लेकिन ऐसा करने पर ये चापाकल दो-तीन वर्षों में ही पानी देना बंद कर देंगे, क्योंकि तब तक भू-जल का स्तर काफी नीचे चला गया होगा। पटना नगर निगम ने पटना शहर में 19 स्थानों पर पम्प हाउस और उसके मुख्य वाटर सप्लाई के नेटवर्क से जोड़ने के लिए 22 करोड़ रूपये आवंटित किया है। चापाकलों का मरम्मत कराने और पम्प हाउस बनवाने का कार्य एक सप्ताह के अंदर शुरू कर दिये जाने का आदेश दे दिया गया है, जिससे कि पटना शहर के अधिक से अधिक घरों को नल-जल उपलब्ध होने लगे। लेकिन ऐसा करने से भू-जल का स्तर और अधिक तेजी से नीचे गिरने लगेगा, जिसके चलते तीन-चार वर्षों के अंदर पानी की समस्या फिर पैदा हो जायेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसा उपाय करे जिससे कि भू-जल का दोहन नियंत्रण हो तथा भू-जल बड़े पैमाने पर रिर्चाज होता रहे। इन दोनो उपायों को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा, इसकी विस्तृत चर्चा इस आलेख में पहले ही की जा चुकी है। ●

(लेखक फायर एण्ड सेफ्टी विशेषज्ञ हैं।)
मो०:- 9334107607
वेबसाईट :- www.psfsm.in

झुग्गी-झोपड़ियों को आगजनी से बचाता है

फायर रेजिसटेंट व वाटर प्रूफ छप्पर

● ललन कुमार प्रसाद

भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है। यहां सवा छः लाख से अधिक गांव है। खासकर गर्मियों में यहां एक-एक दिन में सैकड़ों घर आगजनी की भेंट चढ़ जाते हैं। उसका नामोनिशान मिट जाता है। नतीजा जान-माल की भारी क्षति होती है। एक ही दिन में करोड़ों रूपये का नुकसान हो जाता है। अनेक छोटे-छोटे बच्चों एवं मवेशियों की जाने चली जाती है। कभी-कभी तो गांवों की पूरी की पूरी टोली खाक में मिल जाती है। कुछ ही समय में खलियान में रखी तैयार फसल की गांठें राख में तब्दील हो जाती है। वैसे ही हमारे किसान भाई सालों भर आर्थिक तंगी से जुझते रहते हैं, ऐसे में देहाती आगजनी किसान भाईयों को आर्थिक रूप से दिवालीया बना देती है और उनमें से कईयों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देती है। इसी बात को ध्यान में रखकर बिहार सरकार के फायर बिग्रेड के शीर्ष अधिकारी हर साल घोषणा करते हैं कि गांवों में कच्चे मकानों तथा झुग्गी झोपड़ियों के छप्परों को फायर रेजिसटेंट बनाया जायेगा। ऐसा इसलिए कि शहरों की तुलना में गांवों में आगजनी की घटनाएं बहुत ज्यादा घटती है। दरअसल, शहरों में पक्के मकान होते हैं, जबकि गांवों में भारी संख्या में कच्चे मकान और झुग्गी झोपड़ियां होती है। बात यह है कि गांवों में जर्बदस्त गरीबी है। कुछ ही लोग धनी होते हैं, शेष सभी गरिब होते हैं। यही कारण है कि गांवों की गरीब जनता, किसान और मजदूर ये सब कच्चे मकानों और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। जिनपर घास-फूस, सरकंडे, पुआल, ताड़ और नारियल की जटाओं से निर्मित छप्पर को बांस के ढ़ांचे (फ्रेम) से बांधने के लिए मूंज और नारियल की रस्सी इस्तेमाल की जाती है। यह सभी तेजी से जलने वाले पदार्थ होते हैं। ऐसे में किसी कारणवश किसी कच्चे मकान या झुग्गी झोपड़ी के छप्पर में आग लग जाती है तो उसे फैलने से रोकना कठिन हो जाता है। ऐसे हालात में हवा कुछ तेज बहने लगती है, जिससे समीप की दूसरी झुग्गी-झोपड़ियों की छप्परों में जल्दी आग पकड़ लेती है। ऐसे में आग को बुझाना तो दूर तेजी से फैलने से रोकना भी कठिन हो जाता है, जिसे देखकर लोग कहने लगते है कि हवा को इसी समय तेजी से बहनी है। यह तो वैज्ञानिक तथ्य है कि आंख की आंच से हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती जाती है तो खाली जगह को भरने हेतु हवा चारों ओर से बहकर तेजी से उस जगह को छाप लेती है। नतीजा जब आग लगती है तो उस स्थान पर हवा तेजी से बहने लगती है। अब तो गांवों में आगजनी की दृष्टि से स्थिति और भी माकूल हो गई है। इसके दो कारण है-पहला, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत छः करोड़ से भी अधिक गरीब परिवारों को सिलेंडर और रेगुलेटर के साथ गैस का चूल्हा उपलब्ध करा दिया गया है और दूसरा की गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है।

लेकिन दुख की बात है कि बिहार सरकार का अग्निशमन विभाग हर साल घोषणा तो करता है लेकिन, बनवाते एक भी नहीं है। इसके कई कारण है। इन्हीं कारणों में से एक शायद यह तो नहीं है कि बिहार सरकार के फायर बिग्रेड में अयोग्य फायर पर्सनल की भरमार। भारी संख्या में बहाल इन फायर पर्सनल को यह जानकारी है भी या नहीं कि फायर रेसिसटेंट छप्पर किस बला का नाम है, क्योंकि बिहार के किसी भी गांव में एक भी फायर रेसिसटेंट छप्पर देखने को नहीं मिलता है। अगर यह फायर पर्सनल इतना भी नहीं जानते हैं तो फायर रेसिसटेंट छप्पर बनवाना तो इनकी दूर की कौड़ी है। यह गांव के गरीब किसान मजदूरों के प्रति धोखा नहीं तो और क्या है। इतना ही नहीं लगता है कि गांव की जनता को धोखा देने का यह सिलसिला बदस्तूर भविष्य में भी बेरोक-टोक जारी रहेगा। ऐसा इसलिए कि बिहार सरकार अयोग्य युवाओं को फायरमैन के पद पर बहाल कर रही है। बात यह है कि बिहार सरकार फायरमैन की बहाली हेतु जो आवेदन आमंत्रित करती है, उसमें यह शर्त शामिल नहीं होता है कि आवेदनकर्ता के पास फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोई डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है। यह बिहार सरकार के साथ-साथ फायर बिग्रेड के शीर्ष अधिकारियों की मानसिक सोच के दिवालियापन को दर्शाता है। ऐसे में जनता के पैसों पर ऐशोअराम फहराने वाले बिहार सरकार और फायर बिग्रेड के शीर्ष अधिकारी जनता के लिए बोझ के सिवा और कुछ नहीं है। सरकार पिछली गलती से भी सबक नहीं ले रही है। आज से 12-13 साल पहले बहाल शिक्षक बार-बार पात्रता परीक्षा दिलवाने के बावजूद उनमें से 90 प्रतिशत शिक्षक आज भी अपात्र हैं। कहा जाता है कि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं तो ऐसे में 90 फिसदी अपात्र शिक्षक अच्छे व सभ्य समाज का निर्माण

कैसे कर सकते हैं। ऐसे में समाज आबाद होने के बजाय बर्बाद हो रहा है।

बिहार की राजधानी पटना के एक्जीविशन रोड के किनारे आशियाना ग्लैक्सी के 410, चौथी मजिल पर स्थित पाटलीपुत्रा स्कूल ऑफ फायर एण्ड सेफ्टी मैनेजमेंट के एक फैकेल्टी का कहना है कि झुग्गी झोपड़ियों में हर साल भारी संख्या में घटने वाली भीषण आगजनी से निजात दिलाने के लिए केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूढ़की, उत्तर प्रदेश ने ऐसी प्राद्योगिकी विकसित की है, जो घास-फूस के छप्परों को आग से बचाती है। यहां पर इस बात का भी उल्लेख कर देना जरूरी है कि पूरे बिहार में फायर सेफ्टी मैनेजमेंट व इंडस्ट्रीयल सेफ्टी मैनेजमेंट के करीब 100 शिक्षण संस्थान हैं, इनमें कितने रजिस्ट्रड नहीं है, इसका कोई हिसाब-किताब सरकार के पास नहीं है और गैर रजिस्ट्रड सेफ्टी संस्थान डिप्लोमा और डिग्री बांट रहे हैं। सेफ्टी संस्थान के शिक्षण संस्थानों में से सिर्फ दो ही के प्रोसपैक्टस में सिलेबस यानि पाठ्यक्रम है-एक इंडस्ट्रीयल सेफ्टी मैनेजमेंट (आईएसएम, पटना यूनिवर्सिटी) और दूसरा, पाटलीपुत्र स्कूल ऑफ फायर एण्ड सेफ्टी मैनेजमेंट, पटना। यह आश्चर्य का विषय है कि पाटलीपुत्र स्कूल ऑफ फायर एण्ड सेफ्टी मैनेजमेंट को छोड़कर बिहार के किसी भी दूसरे सेफ्टी मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट में फायर सेफ्टी मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की जाती है, जबकि आगजनी की 85 फिसदी घटनाएं सॉर्ट सर्किट के चलते घटती है। पटना विश्वविद्यालय, बिहार और झारखण्ड की सबसे अच्छी विश्वविद्यालय मानी जाती है। पटना विश्वविद्यालय सरकारी विश्व विद्यालय है और पटन विश्वविद्यालय के आईएसएम दरभंगा हाउस में 1984 से सेफ्टी मैनेजमेंट की पढ़ाई की जा रही है। आईएसएम में भी फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का लैब नहीं है जबकि पाटलीपुत्र स्कूल ऑफ फायर एण्ड सेफ्टी मैनेजमेंट, पटना में फायर सेफ्टी मैनेजमेंट को लेकर देश का सबसे अच्छा लैब है। आईएसएम, दरभंगा हाउस, पटना विश्वविद्यालय वर्षो तक हर साल पाटलीपुत्र स्कूल ऑफ फायर एण्ड सेफ्टी मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट में लैब वर्क करने के लिए अपने स्टूडेंट को भेजती रही है, लेकिन अब नहीं भेजती है। यह सेफ्टी मैनेजमेंट के स्टूडेंट के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है।

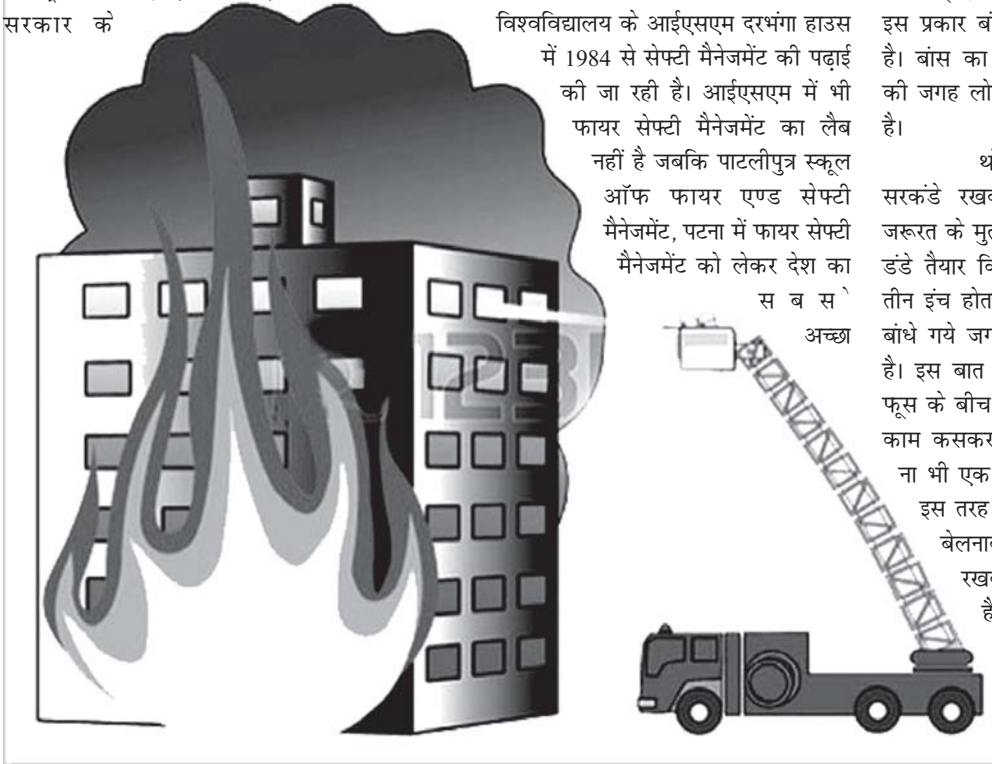

★ **फायर रेसिसटेंट व वाटरप्रूफ छप्पर बनाने की विधि :-** फायर रेसिसटेंट छप्पर बनाने की विधि में इस बात का विशेष ख्याल रखना पड़ता है कि बांस का फ्रेम इतना मजबूत तैयार हो कि बाद में कुछ समय के बाद झूके नहीं। इसके लिए उम्दा किस्म के सीधे परिपक्व और दो इंच मोटे बांस प्रयुक्त किये जाते हैं। दो इंच मोटे बांस को बीच से चीड़कर दो तह में एक-दूसरे के ऊपर लम्बवत् एक फूट के अंतर पर बिछाया जाता है। इस प्रकार बांस का फ्रेम बनकर तैयार हो जाता है। बांस का ढ़ांचा तैयार करने के लिए सुतली की जगह लोहो के तार का इस्तेमाल किया जाता है।

थोड़े से फेस के बीच में दो-तीन सरकंडे रखकर लोहे के तार से बांधते हुए जरूरत के मुताबिक लम्बाई के ढ़ेर सारे बेलनाकार डंडे तैयार किए जाते हैं, जिनका व्यास लगभग तीन इंच होता है और लोहे के तार से आपस में बांधे गये जगहों के बीच की दूरी छः इंच होती है। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि फूस के बीच में सरकंडे रखने के बाद बांधने का काम कसकर किया जाये, क्योंकि कसकर बांधना भी एक तरह का फायर रेसिसटेंट क्रिया है। इस तरह से तैयार किये गये फूस सरकंडे के बेलनाकार डंडे को बांस के ढ़ांचे पर रखकर लोहे के तार से बांधते चले जाते हैं।

छप्पर के ऊपर सतह पर कटबैकयुक्त चिकनी मिट्टी के गारे का एक सेंटीमीटर मोटा प्लास्टर लगाया जाता है। इस प्लास्टर के

सूखने के बाद उसी गारे का दूसरा प्लास्टर लगाया जाता है। फलस्वरूप पहले प्लास्टर में जो दरारे आ जाती है, वे दूसरे प्लास्टर से भर जाती है। यदि दूसरा प्लास्टर सूखने के बाद भी कुछ दरारे पड़ जाती है तो उन्हें उसी कटबैकयुक्त चिकनी मिट्टी के गारे से भर दिया जाता है। इसके साथ-साथ उसी गारे का एक सेंटीमीटर मोटा प्लस्तर छप्पर की भीतरी सतह में भी लगाया जाता है। फिर छप्पर को पूरी तरह से सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर उस प्लस्टर किये हुए छप्पर पर हांथ से लिपाई के द्वारा गोबरी का लेप किया जाता है। इस लेप के सुखने के बाद उसी पर गोबरी का दूसरा लेप कर दिया जाता है। इस प्रकार छप्पर के आंतरिक प्लस्तर पर गोबरी का लेप (कोट) चढ़ा दिया जाता है। गोबरी का लेप चढ़ाने के बाद छप्पर पर वाटर रेसिसटेंट घोल के दो लेप-एक सूखने के बाद दूसरा, बारी-बारी से ब्रश की सहायता से चढ़ा देते हैं। इस तरह तैयार पूरी छप्पर फायर रेसिसटेंट के साथ-साथ वाटर रेसिसटेंट बन जाता है। जिसके चलते वर्षा ऋतु में ऐसे छप्पर पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंत में छप्पर का कालापन दूर करने के लिए गोबरी का लेप चढ़ाये छप्पर की सतह पर सरेस मिल चूने की घोल से एक या दो बार पुताई कर दी जाती है। इससे छप्पर का रंग सफेद हो जाता है और देखने में अच्छा लगता है।

★ गोबरी क्या है और कैसे तैयार किया जाता है? :- गोबरी तैयार करने के लिए बराबर-बराबर मात्रा में गोबर और चिकनी मिट्टी लेते हैं। इन दोनों को पानी की सहायता से अच्छी तरह मिलाते हैं। गोबर और चिकनी मिट्टी को समान अनुपात में मिलाकर तैयार किये गये इसी

मिश्रण को गोबरी कहा जाता है।

★ कटबैक क्या है और यह कैसे झुग्गी झोपड़ी के छप्पर को फायर रेसिसटेंट बना देता है? :- तारकोल और मिट्टी के तेल या डीजल के घोल को कटबैक कहते हैं। 10 घन फुट चिकनी मिट्टी के गारे के लिए 15 किलोग्राम तारकोल (80/100 ग्रेड) और 3 किलोग्राम मिट्टी का तेल या डीजल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले ताड़कोल को गर्म करके पिघलाया जाता है। फिर पिघले हुए ताड़कोल को एक कनस्तर में, जिसमें मिट्टी का तेल या डीजल की आवश्यक मात्रा पहले से ही रखी रहती है, धीरे-धीरे डालते जाते हैं और किसी बांस के डंडे की सहायता से चलाते रहते हैं, ताकि ताड़कोल या तेल आपस में अच्छी तरह से घूलमिल जाये।

अब प्रश्न उठता है कि ताड़कोल और मिट्टी का तेल दोनो ही अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ हैं, इसलिए तुरंत आग पकड़ लेते हैं। फिर कटबैकयुक्त चिकनी मिट्टी के गारे का इस्तेमाल करके बनाया गया छप्पर फायर रेसिसटेंट कैसे हो जाता है? बात यह है कि चिकनी मिट्टी के गारे में बहुत ही कम मात्रा में मिट्टी का तेल या ताड़कोल मिलाया गया होता है, जिसमें से मिट्टी का तेल उड़ जाता है और ताड़कोल गारे में इस तरह से मिल जाता है कि उसके कण अलग-अलग हो जाते हैं। इसलिए कटबैकयुक्त मिट्टी के गारे में आग लगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

★ वाटर रेसिसटेंट घोल क्या है और कैसे तैयार किया जाता है? :- वाटर रेसिसटेंट घोल, तारकोल और मिट्टी के तेल या डीजल को एक विशेष अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके लिए एक किलोग्राम ताड़कोल में दो लिटर मिट्टी का तेल या डीजल मिलाया जाता है। सबसे पहले ताड़कोल को पिघलाते हैं फिर पिघले हुए ताड़कोल को एक कनस्तर में जिसमें पहले से मिट्टी का तेल डीजल आवश्यक मात्रा में रखा रहता है, किसी बांस के डंडे की सहायता से मिलाते हुए धीरे-धीरे डालते जाते हैं ताकि ताड़कोल और तेल आपस में अच्छी तरह घूलमिल जाये। ●

(लेखक फायर एण्ड सेफ्टी विशेषज्ञ हैं।)
मो०:- 9334107607
वेबसाईट :- www.psfsm.in

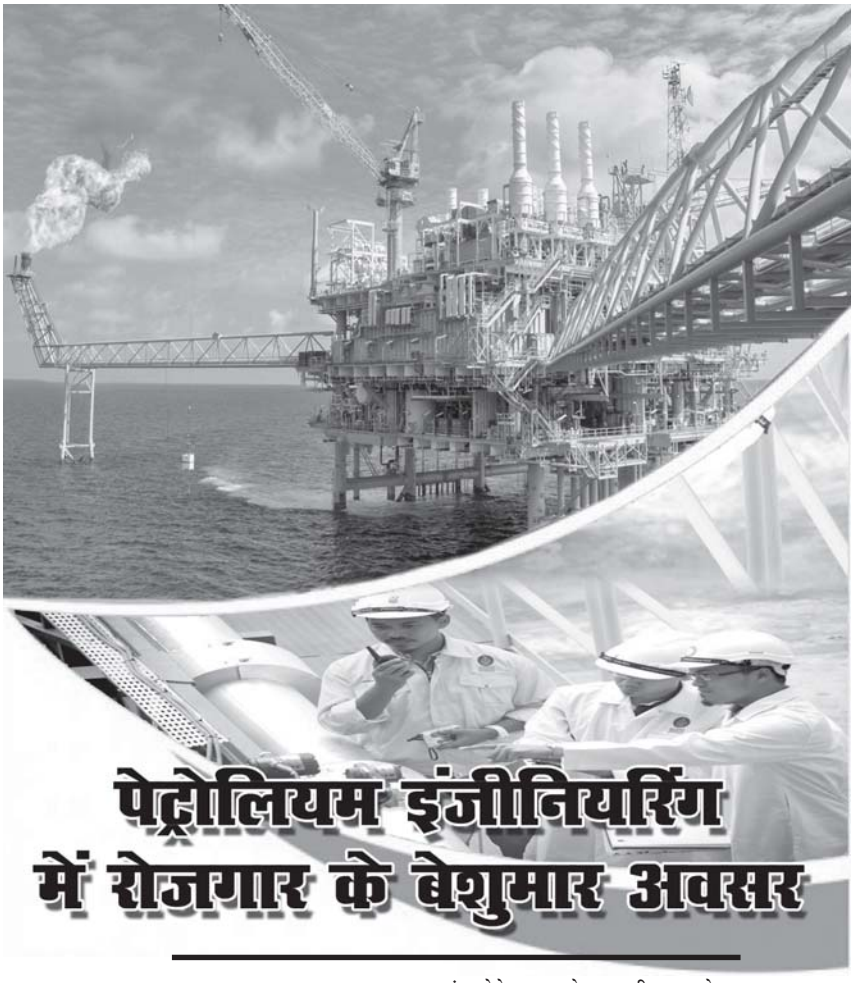

पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में रोजगार के बेशुमार अवसर

● **ललन कुमार प्रसाद**

आधुनिक समाज के ढ़ेर सारे क्षेत्रों में हम पूरी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर निर्भर हैं, यह हमारी आम और खास, दोनो तरह की जरूरतों को पूरा करता है। आम व मूलभूत जरूरत, जैसे-खाना पकाना। आधुनिक रसोईघर की कल्पना बगैर कुकिंग गैस के कैसे कर सकते हैं? कुकिंग गैस क्या है? एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। खास जरूरत, जैसे-हवाई जहाज पर उड़ना। हवाई जहाज को उड़ाने के लिए एवीऐशन टरवाइन फ्यूएल का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और इसका विकल्प भी कोई अन्य फ्यूयेल नहीं है। अर्थात् हवाई जहाज केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही उड़ाया जा सकता है, किसी अन्य फ्यूयेल से नहीं। लेकिन इसके विकल्प के रूप में आज बायो फ्यूयेल का का इजात कर लिया गया है। किन्तु इसका उत्पादन नहीं के बराबर हो रहा है। आम जरूरत के तौरपर ट्रांसपोटेशन को ही ले लिजिए- ट्रांसपोटेशन चाहे आदमी का हो या जानवर का या लगभग सभी प्रकार के समानों का, इसका साधन पेट्रोलियम ही है। पेट्रोल और डीजल न हो तो हम बाइक, स्कूटर, स्कूटी, ऑटो, मिनी बस, बस, मिनी ट्रक, ट्रक, रेल इंजन, जहाज, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, मिशाईल लॉचिंग पैड इत्यादि देश के भीतर या बाहर कैसे ले जा सकेंगे? यहां तक की मरीज को एम्बुलेंस द्वारा घर से अस्पताल तक कैसे ले जा पायेंगे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेनाओं की गतिशिलता और प्रहार की क्षमता भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर निर्भर है। इसलिए तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था कि आधुनिक समाज का लाईफ लाईन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स।

★ **क्या है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग? :-** पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के उत्पादन हेतु प्लांट का निर्माण करना और उत्पादन से सम्बद्ध मशिनों को बनाना, उन्हे लगाना, ऑपरेट करना, रख-रखाव इत्यादि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के तहत आता है।

पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स : कच्चे तेल और प्राकृति गैस, कच्चे तेल को उपयोग योग्य बनाने, उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों को देश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पाईप लाईन बिछाने, पेट्रोल, डीजल, किरासन के भंडारण हेतु टैंक टैयार करने, पेट्रोल पंप, गैस फिलिंग स्टेशन आदि स्थापित करने का काम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के तहत आता है।

जमीन के अंदर दबे अर्थ क्रस्ट में दबे पेट्रोलियम का खोज करना, उसे जमीन के अंदर से जमीन की ऊपरी सतह तक खीचना, शुद्ध करके इस्तेमाल हेतु बनाने का काम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के तहत आता है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को दो भागों में बांटा गया है :- अपस्ट्रीम सेक्टर और डाउनस्ट्रीम सेक्टर।

★ **अपस्ट्रीम सेक्टर :-** इस सेक्टर में तरल पेट्रोलियम और गैसीय पेट्रोलियम की खोज करना यानि पेट्रोलियम के एक्सपोलरेशन का कार्य करना, उत्पादन हेतु ड्रीलिंग (ऑफ शोर ड्रीलिंग और ऑन शोर ड्रीलिंग) का कार्य करना, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को जमीन की सतह पर लाना और इन दोनो को एक-दूसरे से अलग करने का कार्य किया जाता है।

★ **डाउनस्ट्रीम सेक्टर :-** इस सेक्टर में उत्पादित

क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को तेल शोधक कारखाने तक पहुंचाना, तेल शोधन के बाद प्राप्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे-पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, नेफ्ता, इथर, फ्यूएल ऑयल, लीक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस इत्यादि का भंडारण, वितरण और क्रय-विक्रय का कार्य किया जाता है।

★ क्यो है रोजगार की अपार अवसर? :- लगातार बढ़ती आबादी की जरूरतों की पूर्ति हेतु सारी दुनियां में ऊर्जा की खपत बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि पूरी दुनियां में एनर्जी सेक्टर का अनवरत व्यापक विस्तार हो रहा है। इसलिए इस क्षेत्र में इंजीनियरों और तकनिकी विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है। वैसे तो प्रोफेशनल्स की मांग हमेशा बनी रहती है, लेकिन ऊर्जा का विशिष्ट क्षेत्र होने के नाते पेट्रोलियम के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। इसके तीन कारण है-पहला की आज की दौर में पेट्रोलियम पदार्थों की उपयोगिता दिन व दिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, दूसरा की पेट्रोलियम के क्षेत्र में प्रशिक्षित पढ़े-लिखे युवकों की भारी कमी है और तीसरा की पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एक ग्लोबल करीयर है। इसलिए इससे जुड़े पेशेवरों की नियुक्तियां देशी-विदेशी ढ़ेर सारी सरकारी-गैर सरकारी कंपनियों में होती है। इस क्षेत्र में सैलरी भी आकर्षक मिलती है। डिप्लोमा के बाद औसत वेतन कम से कम 40 हजार रूपये प्रतिमाह होता है। बैचलर डिग्री के बाद 55 हजार रूपये मासिक होता है और मास्टर डिग्री के बाद 65 से 70 हजार रूपये प्रतिमाह होता है।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, ओ.एन.जी.सी. रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, एस्सार ऑयल लिमिटेड, आदि जैसी देश की कई बड़ी कंपनियां शानदार सैलरी पैकेज पर नौकरियों के ऑफर दे रही है। विदेशों में भारतीय तेल कंपनियां तेल की खोज और उत्पादन में हांथ आजमां रही है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ग्लोबल इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर देश-विदेश में बहुत काम करना पड़ता है। पेट्रोलियम इंजीनियरों के लिए भारत के अलावा खाड़ी देशों और विकसित देशों में भी करीयर निर्माण के अच्छे अवसर हैं। ऐसे में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का क्षेत्र आने वाले समय में काम करने के लिए भारी संख्या में विभिन्न प्रकार की नौकरियां सृजित करेगा। लेकिन, इस क्षेत्र में काम करने के लिए कम्युनिकेशन स्कील और अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है। यदि आपकी कम्युनिकेशन क्षमता अच्छी है तो विदेशों में भी पेट्रोलियम इंजीनियरों की भारी मांग है।

★ इन पदों पर मिलेगी नौकरी :- जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट, ऑयल ड्रीलिंग इंजीनियर, ऑयल रिजरवॉयर इंजीनियर, वॉयर प्रोडक्शन इंजीनियर, ऑयल वेल लॉग एनालिस्ट, ऑयल फैसिलिटी इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर और टेक्निकल सर्पोट इंजीनियर।

★ नौकरी हेतु प्रमुख संस्थान :- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ओ.एन.जी.सी., आई.बी.पी. कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, एस्सार ऑयल लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, लुब्रिकेट्स इंडिया, ढ़ेर सारे रिफाइनरी कंपनिया, इत्यादि।

★ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के प्रमुख कोर्सेज :-
- ☞ डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग।
- ☞ बी.ई./बी.टेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग।
- ☞ बी.टेक पेट्रोलियम रिफाइनिंग एण्ड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग।
- ☞ बी.टेक पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजीनियरिंग।
- ☞ बी.टेक पेट्रलियम रिजरवॉयर एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग।
- ☞ बी.टेक अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग।
- ☞ एम.ई./एम.टेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग।
- ☞ एम.टेक पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग।
- ☞ एम.टेक पेट्रोलियम रिफाइनिंग एण्ड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग।

★ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के प्रमुख शिक्षण संस्थान :-
- ☞ धनबाद स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद, झारखण्ड, वेबसाइट : www.ismdhanbad.ac.in
- ☞ युनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्टडीज, देहरादून, उत्तराखण्ड। वेबसाईट : www.upes.ac.in
- ☞ पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम युनिवर्सिटी, गुजरात।
- ☞ राजीव गांधी इंस्टीच्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेल, उत्तर प्रदेश। वेबसाईट : www.rgipt.ac.in
- ☞ डॉ० हरी सिंह गौर युनिवर्सिटी, सागर, मध्य प्रदेश।
- ☞ भारतीदसन इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, तमिलनाडू।
- ☞ पाटलीपुत्र स्कूल ऑफ फायर एण्ड सेफ्टी मैनेजमेंट, 410, चौथी मंजिल, आशियाना ग्लैक्सी, एक्जीवीशन रोड, पटना-800001, बिहार। ●

(लेखक फायर एण्ड सेफ्टी विशेषज्ञ हैं।)
मो०:- 9334107607
वेबसाईट :- www.psfsm.in

कानूनी सलाह
शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

जमानत और बन्धपत्रों के बारे में उपबन्ध
(Provisions as to Bail and Bonds)

☞ चार्जशीट आने के बाद जमानत धारा 437 के अन्तर्गत गुणागुण के आधार पर ही जताी है।

☞ धारा 436 (1), 437 के अन्तर्गत जमानत केवल मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी दे सकता है।

☞ धारा 439 के अन्तर्गत सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय जमानत देता है।

☞ धारा 438 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत का अन्तरिम आदेश उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय देते हैं।

☞ अग्रिम जमानत तब तक प्रभावी होती है, जबतक अभियुक्त का विचारण समाप्त न हो जाये या न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाये।

☞ न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण न्यायिक अभिरक्षा माना जाता है।

☞ उच्च न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का उपबन्ध नहीं हे।

☞ जमानत का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त और जमानतियों से यह आश्वासन प्राप्त करना है कि वे विचारण के समय उपलब्ध रहेंगे।

☞ जमानतीय मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत देने से इन्कार करने पर पुलिस अधिकारी धारा 432 दण्ड संहिता के अन्तर्गत सदोष परिरोध के लिए उत्तरदायी होता है।

☞ जमानतीय मामले में जमानत को विचारण न्यायालय खारिज नहीं कर सकता है।

☞ धारा 482 के अन्तर्गत तथा उच्च न्यायालय को धारा 436 के अन्तर्गत जमानत खारिज करने को अन्तर्निहित शक्ति है।

☞ जमानत खारिज हो जाता है, तो खारिजी के आदेश के लिए न अपील होगी न पुनरीक्षण।

☞ जमानत का आदेश अन्तर्वर्ती आदेश है।

☞ जमानत का आवेदन खारिज हो जाता है, तो पुनः आवेदन उसी न्यायालय में दिया जा सकता है, जिसने जमानत को आवेदन खारिज किया है। जमानत के सम्बन्ध में प्राड्.याय लागू नहीं होता है।

☞ धारा 395 के अन्तर्गत निर्देश न्यायालय, धारा 397 के अन्तर्गत पुनरीक्षण न्यायालय तथा धारा 389 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय जमानत का आदेश देते हैं।

☞ विशेष परिस्थितियों में कुछ निश्चित समय के लिए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना पैरोल कहलाता है। पैरोल शर्ट टर्म बेल होता है। जब साधारण जमानत का आवेदन खारिज हो जाता है, तो पैरोल का आवेदन दिया जाता है।

विचारण (Trials)

☞ पूर्वदोषसिद्धि का साक्ष्य लेने का प्रावधान समन मामले के विचारण में नहीं है।

☞ समन मामले में दण्ड के प्रश्न पर नहीं सुना जाता है।

☞ समन मामले का वारण्ट मामले जैसा विचारण किया जाता है और अभियुक्त उन्मोचित हो जाता है तो उन्मोचन दोषमुक्ति माना जायेगा।

☞ अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसे दोषसिद्धि का दण्डादेश दिया जा सकता है।

☞ अभियुक्त किसी ऐसे अपराध के लिए दण्डित किया जा सकता है, जिसका परिवाद या समन में उल्लेख नहीं है लेकिन जो स्वीकृत या साबित तथ्यों से उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है। (धारा 255(3))

☞ जहाँ किसी परिवाद पर सम्मन जारी किया जाय और समन में नियत किये गये दिन को परिवादी उपस्थित न हो, तब मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है। (धारा 258)

☞ धारा 256 के प्रावधान केवल परिवाद पर संस्थित किये गये मामलों पर ही प्रयोज्य होते हैं, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किये गये मामलों पर नहीं।

☞ परिवादी अन्तिम आदेश पारित किये जाने से पूर्व मजिस्ट्रेट की अनुमति से परिवाद वापस ले सकता है। (धारा 257)

☞ परिवाद वापस लेने का प्रभाव दोषमुक्ति होता है।

☞ परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समन मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य मजिस्ट्रेट कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में निर्णय सुनाये बिना रोक सकता है। (धारा 258)

☞ 6 मास के कारावास से दण्डनीय अपराध का विचारण न्यायहित में वारण्ट मामले के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। (धारा 259)

☞ समन मामले में आरोप विरचना आवश्यक नहीं होता है।

☞ समन मामले में विचारण का प्रारम्भ तब माना जाता है जब अभियुक्त को अपराध की विशिष्टियाँ बतायी जाती है। (धारा 251)

☞ समन मामले में उन्मोचन नहीं होता है। अर्थात् समन मामला एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है।

☞ वारंट मामले का समन मामले की तरह विचारण या समन मामले का वारण्ट मामले की तरह विचारण एक अनियमितता है और धारा 465 द्वारा ठीक होने योग्य है, विचारण दूषित नहीं होता जब तक पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।

☞ संक्षिप्त विचारण (धारा 260 से धारा 265 तक)

☞ संक्षिप्त विचारण में तीन मास से अधिक का कारावास नहीं दिया जा सकता है। (धारा 262(2))

☞ संक्षिप्त विचारण की शक्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।

☞ संक्षिप्त विचारण साधारणतः समन मामले का किया जाता है। कुछ वारण्ट मामले का भी विचारण किये जाने का प्रावधान धारा 260 में है।

☞ यदि मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण के लिए प्राधिकृत नहीं है फिर भी अपराध का संक्षिप्त विचारण करता है, तो विचारण शून्य होगा। (धारा 461)

☞ उच्च न्यायालय द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रकार के अपराधों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं-

(1) जो केवल जुर्माने से दण्डनीय हो।

(2) जो जुर्माने सहित या रहित 6 मास तक के कारावास से दण्डनीय है।

(3) उपर्युक्त अपराधों के दुष्प्रेरण या अपराधों को करने के प्रयत्न के अपराध।

☞ जहाँ संक्षिप्त विचारित किसी मामले में धारा 260 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल दो सौ रूपये से अनधिक जुर्माने का दण्डादेश पारित करता है वहाँ अपील नहीं होगी। (धारा 37 एम)

मगध इंटरनेशनल स्कूल टिकारी मे लगी विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी

● नवीन कुमार रौशन

टिकारी शहर के प्रतिष्ठित मगध इंटरनेशनल स्कूल में नये सत्र 2019-20 के लिए नामांकन शुरू हो गया है। टिकारी और आसपास गांव/कस्बों से आये अभिभावकों एवं बच्चों से विद्यालय का पूरा प्रांगण भर गया और नामांकन के पहले ही दिन रिकॉर्ड 125 बच्चों का नामांकन हुआ। नामांकन पत्र भरने और फी जमा करने हेतु 8 काउंटर बनाये गये थे, जहां अभिभावकगण नामांकन, शिक्षण शुल्क, परिवहन शुल्क एवं विद्यालय के शैक्षिक एवं विधि-व्यवस्था से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर रहे थे।

नामांकनोत्सुक अभिभावकों के बच्चे कक्षा निर्धारण हेतु जब-तक जांच परीक्षा दे, तब-तक अभिभावकों के दर्शनार्थ हेतु विद्यालय के निर्देशक सुधीर कुमार ने बताया कि अभिभावकों के मनोरंजन हेतु कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विज्ञान-उत्पादों के मॉडल विद्यार्थियों द्वारा ही निर्मित है। शिक्षकों ने तो केवल मॉनेटरिंग की। बच्चों द्वारा निर्मित कलाकृतियों एवं मॉडलों में बुद्ध एवं सुभाष की प्रतिमा, डस्टवीन, सकारात्मक सोच दर्शाती संदेशपरक कई पेंटिंग, ड्रोन, सेंसर काउंटिंग बोर्ड, टेस्ला क्वायल, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, स्मार्ट सिटी, इलेक्ट्रोमैगनेटिग जी.बी.सी., एनिमल सेल, फ्री इनर्जी, सोलर सिस्टम सेव, इलेक्ट्रिसिटी, हाईड्रो इलेक्ट्रिसिटी आदि मॉडल एवं कलाकृतियां काफी आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक थी। विज्ञान प्रदर्शनी में तो बच्चों ने कमाल ही कर दिया था। कलाकृतियों एवं मॉडलों के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा, साफ-सफाई, यातायात के नियम, सौर ऊर्जा के उपयोग, जल संचय, प्रदूषण की रोकथाम से जुड़ी समस्याओं के समाधान के संदेश छोड़ने में सफल रही।

अतिथिगण एवं अभिभावक बंधु, छात्र-छात्राओं के नृत्य-संगीत के उत्कृष्ट प्रदर्शन देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। खासकर बच्चों द्वारा नानाविद्य वाद्य-वादन और वह भी निर्दोष वादन। उन्होंने बच्चों के प्रदर्शन को सराहा और उनके लिए खूब तालियां बजायी। इसी क्रम में विद्यालय के दो छात्राओं सुश्री आंबिया एवं सुश्री अंजली ने संवादशैली के माध्यम से बताया कि अनुशासन, स्वच्छ शैक्षिक वातावरण, प्रायः हर मार्गों पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था, प्रारंभिक कक्षाओं के हर सेक्सन में मेड की उपस्थिति इस विद्यालय की खास पहचान है, जो हमारे विद्यालय को शेष विद्यालय से पृथक विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गीत-संगीत-नृत्य, ज्ञान-विज्ञान, कला यानि हर क्षेत्र में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने टिकारी एवं टिकारी से बाहर अपनी प्रतिभा सिद्ध की है।●

टूट रहा जग में विश्वास

मूल्यवान विश्वास जगत में,
रिश्तों की है यह पहचान।
किस्मत ने फैसले सुनाया,
उनके संग बढ़ चला इंसां।
जिस पर था मुझको विश्वास,
टूटी उससे मेरी आस।
तार-तार उम्मीद का संबल,
खंडित होता सारा वितान।
घात मिला, प्रतिघात हुआ,
पीड़ा है, मन है उदास।
डूब रहे सूरज सा ढलता,
जीवन में आ रही है शाम।
चल पाऊंगा कितना पग अब,
जी भर कर सकता हूँ काम।
टूट जाएगा प्यारा सा जग,
कैसे समझाएं अपनों को।
कैसे जग में प्रीत बढ़ाएं,
टूट रहा अपनों का विश्वास।
किस पर करूं मैं अब विश्वास,
चाह रहा खामोश रहूं।
नई इबारत गढ़ने का ले,
बनके रहे मेरी पहचान।

डॉ० संगीता मिश्रा
डंगाली कालीतला, बोलपुर
शांति निकेतन,
वीरभूम वेस्ट बंगाल

रेणु की कहानियों में नारी का स्वरूप

● डॉ० संगीता मिश्रा

फणीश्वरनाथ रेणु एक ऐसे कथाकार थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध किया। उनका नाम आते ही हमारी आंखों के सामने ग्रामीण जीवन पूरी सहजता के साथ चित्रित हो जाता है।

रेणुजी ने कहानियों के साथ उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में नारी के अलग-अलग रूप है, पर उसमें स्वभाविकता और सहजता के समावेश है। रेणुजी को ग्रामांचल का कथाकार कहा जाता है। यह बहुत हद तक सच है, लेकिन उन्होंने शहरी जीवन पर भी कहानियाँ लिखी है। उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन की नारियों के साथ शहरी परिवेश की नारियों का भी बहुत स्वभाविक चित्रण है।

आलोचक डा. चन्द्रशेखर तिवारी की नजर में रेणुजी की कहानियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक उन कहानियों का है, जिनकी कथा भूमि ग्रामीण परिवेश के है। दूसरी महानगरों से जुड़ी है। वैसे रेणुजी का मन ग्रामीण परिवेश में रमता है। उनकी कहानियाँ रसप्रिया, लालपान की बेगम, पंचलाइट, संवदिया आदि ग्रामांचल से जुड़ी कहानियाँ है। आजाद परिंदे, जलवा, अग्निखोर आदि शहरी जीवन से जुड़ी कहानियाँ हैं। इसमें वह सहजता नहीं मिलती जो रेणु की विशेषता है।

इनके इस विचार से यह स्पष्ट है कि उनकी परिवेश से जुड़ी कहानियों में जो सहजता है, उसका अभाव शहरी परिवेश से जुड़ी कहानियों में है। रेणु की ग्रामीण जीवन से जुड़ी कहानियों में जो यथार्थता का पुट है, उसके पीछे एक मुख्य कारण यह है कि उन्होंने ग्रामीण जीवन को खुद जिया है। उस परिवेश की कठिनाइयों को झेले है। उनकी मानसिकता को देखे है। रेणु ने अपनी कहानियों में ग्रामीण परिवेश की जिन नारी चरित्रों को प्रस्तुत किया है, उन्हें उनके परिवेश और मानसिकता के साथ चित्रण किया है। रेणु ने न सिर्फ उनके चरित्र को प्रस्तुत किया है, बल्कि उनके चरित्र के हर एक पहलू पर बड़ी ही पैनी दृष्टि डाली है। रेणु की किसी भी कहानी को ले लीजिए चाहे वह तीर्थोदक कहानी की ग्रामीण गृहणी लल्लन की माँ हो या लालपान की बेगम की बिरजू की माँ। रेणु की सबसे बड़ी विशेष्ज्ञता यह है कि उन्होंने जिस भी चरित्र की सृष्टि की है, उन सभी में नवीनता और विविध ता है। कोई घरेलू नारी है तो कोई कलाकार, कोई प्रेमिका तो कोई निम्न मनोवृति की नारी। ये सभी अपनी चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे से अलग है, लेकिन अपने आप में विशिष्ट है।

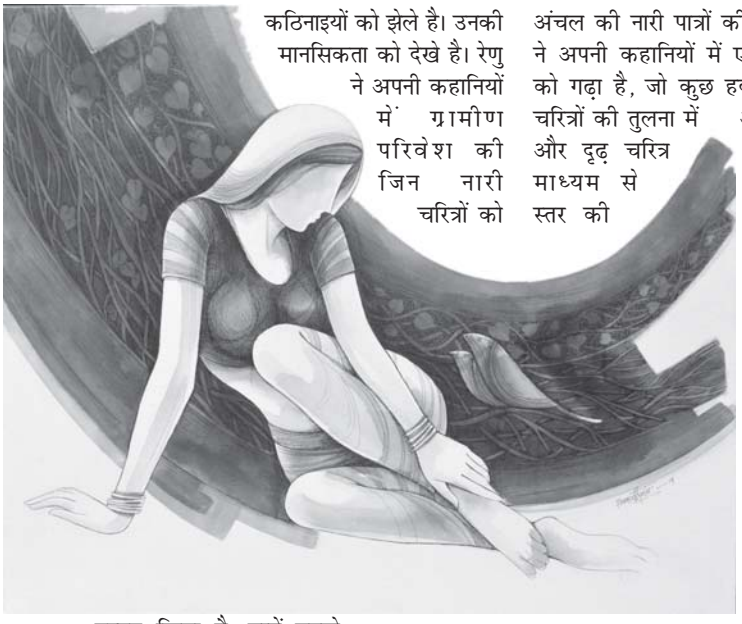

रेणु ने हर स्तर की नारी का चित्रण अपनी कहानियों में किया है। इसमें ग्रामीण अंचल की नारी पात्रों की संख्या अधिक है। रेणु ने अपनी कहानियों में एक सशक्त नारी चरित्रों को गढ़ा है, जो कुछ हद तक प्रेमचंद की नारी चरित्रों की तुलना में अधिक सबल, सशक्त और दृढ़ चरित्र की नारियाँ है। इनके माध्यम से रेणु ने समाज के हर स्तर की नारियों की दशा को दर्शाया और समाज की बहुत सी रूढ़ियों और आडंबरों से पर्दा भी उठाने का काम किया है। इन्हीं विशेषताओं ने उन्हें एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। हम कह सकते हैं कि उनकी कहानियों की नारी पात्र अधिकतर ग्रामीण नारियों के विभिन्न चरित्रों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। वास्तविकता के साथ-साथ विविधता भी है। ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेशों की नारियों की हर परिस्थिति से हमें अवगत कराती है। रेणु की यही विशेषता उन्हें अन्य कथाकारों से अलग करती है। ●

हंसना सीख लो

टूट जाना है अब मंजूर,
सर झुकाना है न मंजूर,
याद रखना,
झुकते रहे अगर तुम,
लोग ऐसे ही झुकाते जाएंगे,
गिरते को कोई उठाते नहीं
उठते को सब गिराते जाएंगे,
इतना भी न झुकना किसी के आगे
कि अपनी ही नजर से गिर जाओ,
सर उठाकर जीना है अगर
न झुकने की जिद ठान लो,
बुलंदियों पर पहुँचाने वालों को पूजते
यहीं तो दुनियाँ का दस्तूर है,
दर्द सहकर भी हँसना सीख लो
अपने भी जख्म देते जाएंगे,
खुद मरहम लगाना सीख लो।

प्रस्तुति :- डॉ० संगीता मिश्रा

बिहार एवं झारखण्ड की तेज़ी से बढ़ती पत्रिका

"केवल सच"

सबुत के साथ खबर लिखता है केवल सच मिडिया ग्रुप

भ्रष्टाचार एवं दहशतगर्दी और मुखिया से मुख्यमंत्री

थाना प्रभारी से डीजीपी के साक्षात्कर के लिए चर्चित

पत्रिका केवल सच

से आज ही जुड़े।

ब्रजेश मिश्र
संस्थापक सह संपादक

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ
Mob. 09431073769, 9308727077

केवल सच
राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
www.kewalsach.com

Kewal Sach TIMES
A National Magazine
www.kewalsachtimes.com

प्रधान कार्यालय- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान सं. 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
झारखण्ड कार्यालय- सेक्टर-1, ब्लॉक-22, फ्लैट-303, खेलगाँव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, होटवार, राँची (झारखण्ड)
सम्पर्क संख्या :- 09431073769, 9955077308, 9308727077

सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर

केवल सच सामाजिक संस्थान और श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट अपने भविष्य के आगामी योजनाओं में सामाजिक एवं बौद्धिक सुधार के क्षेत्र में पुर्नजागरण के शंखनाद हेतु बिहार और झारखण्ड राज्य के मेधावी/सक्षम/योग्य/दक्ष एवं कर्मठ नवयुवकों को अपने टीम में वैतनिक/अवैतनिक रूप से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करना चाहती है। उक्त स्वयंसेवी संस्थान मुख्य रूप से 'अपना घर' (वृद्धाश्रम आवास योजना), परिवार परामर्श केन्द्र, शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम (मूल रूप से निर्धन/बेसहारा लड़कियों हेतु) और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहती है। इन कार्यक्रमों से जुड़कर नवयुवक सामाजिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। उक्त संगठन इसके लिए टीम वर्क के तहत कार्य करना चाहती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वयक के अधीन वार्ड/ पंचायत/ प्रखण्ड/ अनुमण्डल/जिला समन्वयकों की नियुक्ति भी करना चाहती है। इस संस्थान से जुड़कर इच्छुक नवयुवक उक्त पदों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

संस्थान

shruti कम्युनिकेशन ट्रस्ट

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत संचालित

निबंधन संख्या : 22333/2008, आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2549-52 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1073

केवल सच सामाजिक संस्थान

भारतीय सोसायटी एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधित

निबंधन संख्या : 1141 (2009-10), आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

www.shruticommunicationtrust.org

www.ks3.org.in

Regd. Office:- East Ashok Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar)
Jharkhand State Office:- Sector - 1, Block - 14, Flat No.- 501, Khelgaon Houseing Colony, Hotwar, Ranchi
Mob.- 9431073769, 9308727077